राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

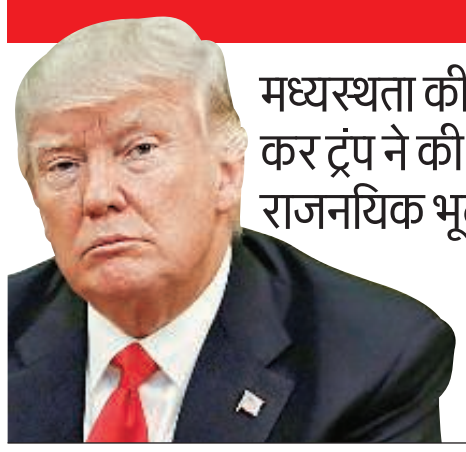

मध्यस्थता की बात कर ट्रंप ने की बड़ी राजनयिक भूल

>> 11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 46

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

माइनस डिग्री तापमान में भी नहीं डगमगाए थे कदम

नई दिल्ली : आज देश कारगिल विजय की 20वीं सालगिरह मना जांबाजों को श्रद्धासुमन अर्पित करेगा। 18 हजार फीट ऊंची चोटी पर थे दुश्मन। नहीं थी घास के तिनके की भी ओट। माइनस डिग्री तापमान। पर नहीं डगमगाए थे कदम। विशेष प्रस्तुति। ● पेज 13

सरोकार

पीएमओ तक पहुंचीं बुंदेलियों की जल चौपालें

बांदा : जल है तो कल है, यह बात बुंदेलियों के जेहन में उतर चुकी है। बांदा में गांव-गांव

आयोजित हुईं जल चौपालें इस बात की गवाह हैं। इसके तहत तालाब-कुआं जियाओ अभियान ने भी गति पकड़ ली है। जल संरक्षण की इस अनूठी पहल की गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गई। (पेज-6)

जागरण विशेष

कांवड़िया बन शिव का जलाभिषेक करता रहमान

प्रतापगढ़ : हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आपस में सब भाई-भाई...। ये बस कोरी

बात नहीं हैं। रहमान अली का उदाहरण सामने है। प्रतापगढ़ निवासी रहमान पिछले छह साल से अपने हिंदू दोस्तों संग बैजनाथ धाम की कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। (पेज-7)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

भाजपा ने मिजोरम में बनाया क्रिश्चियन मिशनरी सेल

आइजल : ईसाई बहुल मिजोरम में कमल खिलाने की तैयारी के मद्देनजर भाजपा ने पहली बार राज्य में क्रिश्चियन मिशनरी सेल की स्थापना की है। बुधवार से इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो गई। सूबे की 40 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी का एकमात्र विधायक है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा से ईडी ने दस घंटे की पूछताछ

चंडीगढ़ : हरियाणा में हिसार के पूर्व सांसद एवं आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब दस घंटे पूछताछ की।

कारोबार ▶ पृष्ठ 10

पतंजलि के हाथों बिकी रुचि सोया इंडस्ट्रीज

मुंबई : लंबी रस्साकशी और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार बाबा रामदेव नियंत्रित पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की बाजी जीत ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने रुचि सोया के लिए पतंजलि की 4,350 करोड़ रुपये की बोली को अनुमोदन दे दिया।

राज्यसभा में टूटी विपक्षी एकता, आरटीआइ बिल पारित

दिखाई ताकत ▶ विधेयक के पक्ष में 117, विपक्ष में 75 वोट पड़े

बीजद-टीआरएस ने दिया सरकार का साथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

16वीं लोकसभा के कार्यकाल में सरकारी विधेयकों के पारित होने में बड़ी बाधा रही राज्यसभा में सरकार ने गुरुवार को विपक्षी एकजुटता का तानाबाना तोड़ दिया। एक दिन पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) संशोधन और तत्काल तीन तलाक सहित सात विधेयकों का रास्ता रोकने की रणनीति तैयार की थी। लेकिन बीजू जनता दल (बीजद) और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने सरकार का साथ देकर आरटीआइ संशोधन विधेयक पारित करा दिया। अब ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि तत्काल तीन तलाक सहित कुछ दूसरे विधेयकों पर भी राज्यसभा में विपक्ष का अब तक का बहुमत अल्पमत में बदल सकता है।

एक दिन पहले ही विपक्ष की रणनीति तय हुई थी और उस पर हस्ताक्षर करने वालों में बीजद और टीआरएस भी शामिल थे। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार, संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और फिर बीजद का रुख बदल गया। दो दिन पहले लोकसभा में दोनों दलों ने आरटीआइ संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राज्यसभा में विधेयक के समर्थन में 117 जबकि विरोध में सिर्फ 75 मत पड़े। हालांकि कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने इस बीच हंगामे का कोई मौका नहीं छोड़ा। मतदान के बाद हार देखकर वे सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पहले सरकार ने संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए कहा, इस संशोधन के जरिये सिर्फ सेवा शर्तों और वेतन-भत्तों में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसा नहीं है। मौजूदा कानून के तहत मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर रखा गया था। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन से आरटीआइ की स्वायत्ता और अधिकारों में किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आएगी।

गुरुवार को राज्यसभा में आरटीआइ संशोधन बिल पर बोलते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। एएनआइ

राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार संसद को भी सरकारी विभाग की तरह चलाना चाहती है। ऐसी सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। कांग्रेस इस पूरे मामले से इसलिए भी नाखुश थी क्योंकि वह संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने पर अड़ी थी, लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। लोकसभा से आरटीआइ संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। दरअसल, कांग्रेस के लिए इस विधेयक का पारित होना एक बड़ा झटका है। अब तत्काल तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में आना है। राजग का घटक दल जदयू इसके विरोध में है, लेकिन बीजद समर्थन में।

जदयू का विरोध, बीजद का समर्थन, तलाक बिल पर मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लोकसभा में सरकार बोली, दूसरे धर्मों में भी पत्नी को गलत तरीके से छोड़ने पर सजा का प्रावधान
- इस महत्वपूर्ण विधेयक की असली परीक्षा राज्यसभा में ही होगी

लंबी बहस के बाद तीन तलाक विधेयक फिर लोकसभा से पास हो गया। चर्चा के दौरान सत्तापक्ष की ओर से जदयू बिल के खिलाफ तो विपक्ष की ओर से बीजद पक्ष में खड़ा नजर आया। विपक्ष के नेताओं ने पुराने तर्कों को दोहराया, जिसका कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिंदुवार जवाब दिया। प्रसाद ने साफ कहा, बिल का संबंध किसी धर्म से नहीं है, महिलाओं के इंसाफ से है। पिछली बार राज्यसभा से पास नहीं होने के कारण निरस्त हो जाने वाले इस बिल की असली परीक्षा फिर वहीं होगी।

लगभग साढ़े छह घंटे से अधिक चली बहस के दौरान सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा, हिंदुओं के बीच प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए कई कानून बनाने वाली कांग्रेस 1986 में भारी बहुमत के बावजूद शाह बानो मामले में क्यों पीछे हट गई। उस समय भी कांग्रेस वोटबैंक को देखते हुए शाह बानो के खिलाफ थी और आज भी उसी वोट की खातिर तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली शायरा बानो के खिलाफ है। आज सवाल किसी धर्म, पूजा, इबादत का नहीं है, सवाल इंसानियत, इंसाफ और मानवता का है।

गुरुवार को राज्यसभा में बोलते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

उन्होंने कहा, 2017 के बाद एक साथ तीन तलाक के 574 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 324 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कानून के अभाव में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तीन तलाक को अध्यादेश जारी कर अपराध बनाने के बाद भी 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रसाद ने कहा, यदि उस समय आपने काम कर दिया होता तो आज हमें यह नहीं करना पड़ता।

> मोदी सरकार घूम-घूम के नहीं चलती, सीधी चलती है। यह किसी धर्म, आस्था या वोट का सवाल नहीं है बल्कि नारी के सम्मान और उसके साथ इंसाफ का सवाल है।
> -रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री

प्रसाद ने अन्य धर्मों में तलाक मामले में अपराधिक सजा का प्रावधान नहीं होने के आरोप पर कहा, हिंदू धर्म में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर सात साल कैद का प्रावधान है। ईसाई, पारसी समेत अन्य धर्मों में भी पत्नी को अवैध तरीके से छोड़ने पर सजा का प्रावधान है। तीन तलाक को आपराधिक बनाने से पति-पत्नी में सुलह की संभावना खत्म होने की बात पर कहा, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष पति कहता है कि उसने तलाक नहीं दिया है तो केस खत्म हो जाएगा। पति के जेल जाने पर मुआवजे की बात पर कहा, तमाम अपराधिक मामलों में सजा होने पर यह सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं। वहीं, राजग की सहयोगी जदयू के सदस्य राजीव रंजन सिंह ने कहा, पार्टी किसी भी विवादित मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं होगी।

आजम खां की टिप्पणी लोस में बवाल पेज>>3
कांग्रेस के पाप का नतीजा भुगत रहा देश पेज>>3

बच्चों से दुष्कर्म मामलों पर विशेष जिला अदालतें बनाएं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को पोक्सो के तहत कोर्ट बनाने का आदेश
- **24,212** मामले दर्ज हुए हैं बाल यौन उत्पीड़न के एक जनवरी से 30 जून तक

बच्चों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने और ऐसे मामलों की जल्द जांच और ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश जारी किए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में पोक्सो में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं ऐसे हर जिले में बाल यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (पोक्सो) के तहत विशेष अदालत गठित की जाए। कोर्ट ने 60 दिन में अदालतों को गठित कर कामकाज शुरू कर देने का आदेश देते हुए कहा है कि ये अदालतें सिर्फ पोक्सो के मुकदमे सुनेगी।

इसके साथ ही बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकने और अपराधियों को दंडित किये जाने के प्रति जागरुकता लाने के लिए देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी। वीडियो क्लिप का प्रसारण टीवी चैनलों पर भी होगा। बुधवार को ही राज्यसभा ने पोक्सो संशोधन विधेयक पास किया है। इसमें बच्चों के दुराचारियों को 20 साल कैद से लेकर मौत तक की कड़ी सजा के प्रावधान किये गए हैं।

बच्चों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से व्यथित सुप्रीम कोर्ट ने बाल उत्पीड़न रोकने के उपाय पर स्वयं सुनवाई शुरू की है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता व अनिरुद्ध बोस की पीठ ने ये आदेश दिया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने देशभर से आंकड़े एकत्रित कराए थे जिसमें पता चला कि एक जनवरी से 30 जून तक बाल यौन उत्पीड़न के 24,212 मामले दर्ज हुए। 6449 में ट्रायल शुरू हुआ और 911 केस में फैसला आया। इस मामले में कोर्ट ने वरिष्ठ वकील वी गिरि को न्यायमित्र नियुक्त किया था और सुझाव मांगे थे।

गुरुवार को गिरि की ओर से कोर्ट को सुझाव दिये गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने भी रिपोर्ट दाखिल की और कोर्ट से और आंकड़े एकत्र करने के लिए कुछ समय मांगा लेकिन कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करने के बजाए ऐसे मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए क्रमवार निर्देश जारी किये। कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अदालतों और संसाधनों की कमी पर भी चिंता जताई।

कोर्ट ने कहा, अदालतों के गठन का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। खर्च में न्यायाधीश, सहयोगी स्टाफ और विशेष अभियोजक की नियुक्त व अदालतों में बच्चों के अनुकूल माहौल होना शामिल है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्चे को सहयोग करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता के साथ बच्चों के प्रति संवेदनशील व बाल अधिकार के प्रति समर्पण को महत्व दिया जाए।

कोर्ट ने गिरि का सुझाव स्वीकारते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह बाल उत्पीड़न रोकने और दोषियों को सजा देने के प्रति लोगों में जागरुकता लाने के लिए एक छोटी वीडियो क्लिप तैयार कराए और उसे सिनेमाघरों में चलाया जाए। टीवी चैनलों पर भी प्रसारण हो। क्लिप में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो साथ ही स्कूलों व पब्लिक प्लेस में भी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किये जाएं। कोर्ट ने राज्यों के फोरेंसिक जांच लैबोरेट्री के निदेशकों व संबंधित अथारिटी से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि जल्दी जांच करके बिना देरी के रिपोर्ट अदालत पहुंचे। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से तत्काल आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से चार सप्ताह में आदेश के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई 26 सितंबर तक टाल दी।

कोलेजियम नहीं, न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे चिंता का विषय : सुप्रीम कोर्ट पेज>>4

क्या कहा कोर्ट ने

- 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं जिन जिलों में बाल यौन उत्पीड़न के, वहां विशेष अदालतों का गठन किया जाए
- 60 दिनों में अदालतों का गठन कर कामकाज शुरू किया जाए,अदालतों के गठन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी
- देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले बाल यौन उत्पीड़न रोकने की वीडियो क्लिप दिखाई जाए। टीवी चैनलों पर भी हो प्रसारण

उप्र मदरसा बोर्ड अब सीबीएसई और आइसीएसई की राह पर

शोभित श्रीवास्तव, लखनऊ

- मदरसों के छात्र-छात्राओं को एक विषय का एक प्रश्नपत्र ही हल करना होगा
- 14 वर्ष से कम उम्र वाले विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे मुंशी और मौलवी की परीक्षा

अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के भी छात्र-छात्राओं को एक विषय की एक परीक्षा देनी होगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने सीबीएसई, आइसीएसइ व यूपी बोर्ड की तर्ज पर पाठ्यक्रम के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 2020 की मदरसा बोर्ड की परीक्षा में लागू होगी। बोर्ड ने मुंशी व मौलवी परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम 14 वर्ष की उम्र भी तय कर दी है।

अभी तक मदरसा बोर्ड के छात्र-छात्राओं को परीक्षा में विभिन्न विषयों के दो से तीन प्रश्नपत्र देने पड़ते हैं। अब मदरसा बोर्ड एक विषय का एक प्रश्नपत्र पैटर्न लागू करने जा रहा है। हर प्रश्नपत्र 100-100 अंकों का होगा। अब आलिया में पांच अनिवार्य विषय के साथ ही एक वैकल्पिक विषय यानी कुल छह पेपर देने होंगे। मुंशी व मौलवी परीक्षा में चार अनिवार्य विषय के साथ ही एक वैकल्पिक विषय की परीक्षा देनी होगी। जिस विषय का पाठ्यक्रम बड़ा होगा वहां प्रश्नपत्र में एक से अधिक खंड दिए जाएंगे। इसमें प्रश्नों को हल करने के लिए विकल्प दिए जाएंगे। बोर्ड ने प्रश्नपत्रों के गठन व उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पाठ्यक्रम समिति की बैठक शीघ्र बुलाने के निर्देश दिए हैं।

मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय ने बताया कि मुंशी व मौलवी की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष तय कर दी गई है। आयु की गणना परीक्षाफल घोषित होने वाले वर्ष की 31 मार्च से की जाएगी। यानी 2020 की मुंशी व मौलवी परीक्षा में वही परीक्षार्थी शामिल हो पाएंगे, जिनकी उम्र 31 मार्च 2020 को 14 वर्ष हो जाएगी।

डिग्री पूरी करने के अधिकतम वर्ष तय : मदरसा बोर्ड में डिग्री अधिकतम कितने वर्ष में पास की जा सकती है, यह अभी तय नहीं था। इसे भी बोर्ड ने तय कर दिया है। मुंशी व मौलवी कोर्स दो साल का है, इसे अधिकतम चार वर्ष में पास करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में पास न करने वाले छात्र बाहर हो जाएंगे। आलिम व फाजिल की दो वर्ष की डिग्री भी अधिकतम चार वर्ष में पास करनी होगी। कामिल की डिग्री तीन वर्ष की है, इसे भी अधिकतम छह वर्ष में पास करना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश में भाजपा को लगे झटके से अमित शाह नाराज, मांगी रिपोर्ट

नईदुनिया, भोपाल

- भाजपाध्यक्ष ने दो विधायकों की टूट को प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी करार दिया

मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन बुधवार को दो विधायकों द्वारा पाला बदल कर कांग्रेस का साथ देने पर भाजपा हाईकमान नाराज है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह से फोन पर बातचीत कर नाराजगी जाहिर की है। शाह ने इस घटना को प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी माना है।

ज्ञात हो, कर्नाटक के बाद सियासी गलियारों में मध्य प्रदेश सरकार को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं, इसी बीच बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में विधि संशोधन विधेयक को शून्य के मुकाबले 122 वोट से पारित करा दिया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही थी कि उनकी सरकार को न केवल कांग्रेस, बसपा, सपा और निर्दलियों का समर्थन हासिल हुआ था बल्कि भाजपा के दो विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल का भी साथ मिला था। इससे उन्होंने अपनी सरकार की मजबूती का सभी को एहसास करा दिया।

इसकी सूचना जब भाजपा हाईकमान को लगी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि शाह की नाराजगी के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में शिवराज सिंह, राकेश सिंह, सुहास भगत और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बैठक कर बागी विधायकों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में शिवराज सिंह शामिल होंगे। वह इस बारे में शाह को स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

हाईकमान भार्गव के बयान से भी नाराज : पार्टी सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा नंबर वन और नंबर टू संबंधी दिए बयान से नाराज है। पार्टी नेताओं की मानें तो उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है कि वह अपने बयानों पर लगाम लगाएं, वरना नेता प्रतिपक्ष पद से हाथ धोना पड़ सकता है। भार्गव ने लोकसभा चुनाव के बाद फ्लोर टेस्ट का बयान दिया था, तब भी पार्टी ने कहा था कि इस बयान से उनका लेना-देना नहीं है।

डैमेज कंट्रोल की कवायद पेज>>4

आइसीसी के मुखिया शशांक मनोहर को आम्रपाली समूह से मिली थी मोटी रकम

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के अध्यक्ष शशांक मनोहर के खाते में 36 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। वो फंड के गलत इस्तेमाल की श्रेणी में आता है क्योंकि वह उन लोगों का पैसा था, जिन्होंने आम्रपाली को घर खरीदने के लिए दिया था। मनोहर का नाम उन बिचौलियों की सूची में आता है, जिनको सीएमडी शर्मा ने 8.71 करोड़ रुपये में से भुगतान किया है।

शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आम्रपाली ग्रुप मामले में तीसरे पक्ष को मोटी रकम दिए जाने की जांच करने को कहा है। न्यायालय ने इसे 'धन का दुरुपयोग' बताया है। इसमें कंपनी के निदेशक शामिल हैं। अदालत ने कहा, 'निदेशक और कर्मचारियों ने लोगों के पैसे को गलत तरीके से दूसरों के खाते में डाला है।'

- बिल्डर अनिल शर्मा ने शशांक के खाते में ट्रांसफर किए थे 36 लाख रुपये
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा-यह रकम देना फ्लैट बायर्स के दिए पैसे का दुरुपयोग

शशांक मनोहर फाइल फोटो

इस बीच, पेशे से वकील मनोहर ने सफाई देते हुए कहा, 'मैं चार साल पहले पटना उच्च न्यायालय में आम्रपाली ग्रुप की तरफ से केस लड़ने गया था। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है।' मनोहर के खाते में पैसा शर्मा की देखरेख में ट्रांसफर किया गया था। मनोहर का नाम आदेश में दो बार आया है। पहली बार उन लोगों की सूची में, जिनके खाते में गलत तरीके से फंड ट्रांसफर किया गया। दूसरी बार तब जब शर्मा ने फोरेंसिक ऑडिटर्स की मदद से अपने द्वारा भुगतान किए गए लोगों की सूची बनाई थी।

सूची में चंदन होम्स प्राइवेट लि., शफायर डिजिडल प्रिंटर्स, मानस नर्सिंग होम, सुरभि एडर्वटाइजिंग प्राइवेट लि. और क्वालिटी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज लि. के नाम भी शामिल हैं। निदेशकों ने घर खरीदारों के पैसे को शादी, विदेश यात्राओं, जेवर, महंगी कारों, शेयर खरीदने में खर्च किया था। कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वह कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा, निदेशक शिव प्रिया, अजय कुमार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उल्लंघन को लेकर हवाला का मामला दर्ज करे।

नई जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 31 जुलाई को संभालेंगे नई जिम्मेदारी, आम सैन्य अधिकारियों की तरह 15 दिन रहेंगे तैनात

आतंकियों के गढ़ दक्षिण कश्मीर में फौजियों के साथ गश्त करेंगे धौनी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- जवानों के साथ पोस्ट पर ड्यूटी देंगे और गार्ड के रूप में रहेंगे तैनात
- 2012 और 2017 में भी बने थे सेना के विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा

आतंकरोधी अभियानों की कमान संभाल रही धौनी की बटालियन

महेंद्र सिंह धौनी को सेना ने 2011 में ब्रांड अंबेस्डर बनाते हुए 106 टेरीटोरियल आर्मी बटालियन (पैरा) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया था। उनकी बटालियन इन दिनों दक्षिण कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों की कमान संभाल रहे विक्टर फोर्स के अधीन है। उल्लेखनीय है कि धौनी अभी तक वह 350 वनडे और 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उनके नाम 10773 वनडे अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं।

महेंद्र सिंह धौनी की फाइल फोटो। प्रेट्र

क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्कों की झड़ी लगाकर बड़ी-बड़ी टीमों के हौसले पस्त करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी जल्द ही आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर में जवानों के साथ आपरेशनल ड्यूटी और पेट्रोलिंग (गश्त) करते नजर आएंगे। रक्षा मंत्रालय और सैन्य प्रशासन ने उन्हें कश्मीर में सेना के साथ सक्रिय ड्यूटी निभाने की अनुमति दे दी है। वह इसी माह 31 जुलाई को जिम्मेदारी संभाल लेंगे। यह पहला मौका होगा जब वह आम सैन्य अधिकारी की तरह कश्मीर में लगभग 15 दिन रहेंगे।

श्रीनगर में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धौनी 2012 में भी कश्मीर में करीब एक सप्ताह तक सेना के साथ रहे थे। उस समय उन्होंने विभिन्न जगहों पर जवानों और अफसरों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाया था। वह उड़ी सेक्टर समेत उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में भी गए थे। वह 2017 में भी कश्मीर आए थे और सेना के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए थे।

गश्ती दल का हिस्सा होंगे धौनी : अधिकारी ने बताया कि यह पहला मौका होगा जब वह आम सैन्य अधिकारियों की तरह कश्मीर में 15 दिनों तक रहेंगे। उन्हें कहां तैनात किया जाएगा, यह अभी तय नहीं है, लेकिन वह एक लेफ्टिनेंट कर्नल की हर प्रकार की ड्यूटी निभाएंगे। दक्षिण कश्मीर में जहां भी उनकी यूनिट का दस्ता गश्त के लिए जाएगा, वह उसका हिस्सा रहेंगे। वह गार्ड और पोस्ट ड्यूटी भी करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह आतंकियों के खिलाफ अभियान का भी हिस्सा बनेंगे तो उक्त अधिकारी ने कहा, अभी यह तय नहीं है, लेकिन सेना की 106 टीए बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल वह अपने पद और जिम्मेदारियों के मुताबिक हर गतिविधि में शामिल होंगे।

धौनी ने चार साल पहले ली थी पैराशूट ट्रेनिंग : धौनी ने पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय से अपनी रेजीमेंट में सेवा देने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए उन्होंने क्रिकेट से दो माह का अवकाश भी लिया है। करीब चार साल पहले धौनी ने आगरा ट्रेनिंग कैंप में भाग लेकर भारतीय सेना के विमान से पैराशूट ट्रेनिंग पूरी की थी। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान पांच बार पैराशूट से छलांग लगाई थी।

युवा वर्ग में बढ़ेगी सशस्त्र बल के प्रति जागरूकता : एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में ज्ञात धौनी का सशस्त्र बल के प्रति लगाव भी जगजाहिर है। उन्होंने अपनी रेजिमेंट में जाकर समय बिताने का फैसला लिया है। इससे युवा वर्ग में सशस्त्र बल के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की चल रही थी अटकलें : अनुमान था कि वर्ल्ड कप-2019 के बाद धौनी क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। उनके संन्यास पर काफी समय से अटकलें चल रही हैं।

रामपुर के कोर्ट ने आजम खां पर लगाया 3.27 करोड़ का जुर्माना

जागरण संवाददाता, रामपुर

- उपजिलाधिकारी की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का दिया आदेश

सपा सांसद और जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां को रामपुर सदर के उपजिलाधिकारी की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने यूनिवर्सिटी का गेट हटाने का आदेश जारी करते हुए तीन करोड़ 27 लाख का जुर्माना लगाया है। 15 दिन में आजम को खुद अवैध कब्जा हटाने का निर्देश के साथ ही पीडब्ल्यूडी को आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। ज्ञात हो, आजम के खिलाफ जमीन कब्जाने के 27 मुकदमे (25 किसानों और दो प्रशासन की ओर से) दर्ज कराए गए हैं। प्रशासन ने सपा नेता को भूमाफिया भी घोषित कर दिया है।

उपजिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी गेट से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, यूनिवर्सिटी का गेट लोक निर्माण विभाग की सड़क पर बना है। इसने मार्ग को बाधित कर दिया गया है। इसे 15 दिन के अंदर हटाया जाए। साथ ही तीन करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति की जाए। यह भी कहा, कब्जा मुक्त होने तक प्रतिमाह नौ लाख दस हजार क्षतिपूर्ति अलग से देने होंगे। यूनिवर्सिटी के सीईओ विधायक अब्दुल्ला आजम का कहना है कि यूनिवर्सिटी में सुंदरीकरण का कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा और कैबिनेट के फैसले से हुआ था। एसडीएम को कैबिनेट के फैसले को बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

पीडब्ल्यूडी ने दायर किया वाद : लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने इस संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया कि विवि परिसर के अंतर्गत बनी सड़क प्रांतीय खंड के स्वामित्व के मार्ग पसियापुरा, लालपुर डाम का हिस्सा है।

1073 घरों के आवंटन करने के लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) ने ड्रा किया। 1985 में करीब 19 हजार लोगों ने इन घरों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अब तक आवंटन नहीं मिल पाया था। इस ड्रा के बाद अब 1,073 लोगों को घरों का आवंटन किया जा सकेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 26 जुलाई 2019

जान दे दिए लेकिन जुबान नहीं खोली

कैप्टन सौरभ कालिया

जन्म : 29 जून, 1976 अमृतसर, पंजाब
शहीद हुए : 9 जून, 1999
यूनिट : 4 जाट रेजीमेंट

शौर्य गाथा: कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जरिए दिसंबर, 1998 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भर्ती हुए। जाट रेजिमेंट की चौथी बटालियन में पहली पोस्टिंग कारगिल में मिली। जनवरी, 1999 में उन्होंने कारगिल में रिपोर्ट किया। मई के शुरुआती दो हफ्तों में कारगिल के ककसार लांग्पा क्षेत्र में गश्त लगाते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों और विदेशी आतंकियों को एलओसी के इस तरफ देखा। 15 मई को अपने पांच साथियों- सिपाही अर्जुन राम, भंवर लाल बगारिया, भीका राम, मूला राम और नरेश सिंह के साथ लद्दाख की पहाड़ियों पर बजरंग पोस्ट की तरफ गश्त लगाने गए। वहां पाकिस्तानी सेना की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग का जवाब देने के बाद उनके गोला-बारूद खत्म हो गए। इससे पहले की भारतीय सैनिक वहां मदद लेकर पहुंच पाते, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। पाकिस्तानी रेडियो स्कार्दू ने खबर चलाई कि कैप्टन सौरभ कालिया को बंदी बना लिया गया है। उन्हें 15 मई से 7 जून (23 दिन) तक बंदी रखा गया और घृणित अमानवीय बर्ताव किया गया। 9 जून को उनके शरीर को भारतीय सेना को सौंपा गया।

जरा याद करो कुर्बानी...

अनधिकृत कॉलोनियों पर थमने का नाम नहीं ले रही सियासत

भाजपा ने जंतर-मंतर पर धरना देकर केजरीवाल पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और भाजपा दोनों इस काम का श्रेय लेना चाहती हैं। इसे लेकर दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप जारी है। वहीं, भाजपा नेता मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरने लगे हैं। गुरुवार को पूर्व मंत्री व राज्यसभा सदस्य विजय गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर धरना दिया।

गोयल ने कहा कि कॉलोनियों की नियमितीकरण पर मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियों की सीमा निर्धारित करने का काम तो केजरीवाल सरकार का था, लेकिन साढ़े चार साल में भी यह काम नहीं किया गया। अब सरकार वर्ष 2021 तक का समय मांग रही हैं। दिल्ली सरकार के नकारात्मक रवैये की वजह से केंद्र सरकार इस काम को करने जा रही है तो मुख्यमंत्री इसका श्रेय लेने की कोशिश में जुट गए हैं।

जंतर-मंतर पर गुरुवार को धरना देते राज्य सभा सदस्य विजय गोयल, सांसद हंसराज हंस और अन्य लोग। गोयल ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ध्रुव कुमार

उन्होंने कहा कि केजरीवाल का दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात और झूठ को लोगों के सामने लाने के लिए वह अनधिकृत कॉलोनियों की पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जनता को उसी तरह गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से शीला दीक्षित सरकार ने वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों को झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर किया था। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि टकराव की राजनीति छोड़कर यदि केजरीवाल केंद्र के साथ समन्वय बनाकर चलते तो अबतक अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो गई होतीं। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने कहा कि केजरीवाल सरकार सीमांकन का काम पूरा नहीं कर पाई, इसलिए यह काम अब केंद्र सरकार कर रही है। इसमें ड्रोन और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

गोपाल राय बोले, भाजपाई अपने गिरेबां में झांकें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों पर सियासत जारी है। अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने भाजपा को कठघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि अपने शासनकाल में भाजपा ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में एक ईंट भी लगाने का कार्य नहीं किया है। केजरीवाल सरकार ने पहले दिन से अब तक इन कॉलोनियों में छह हजार करोड़ का बजट खर्च करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों को लेकर धरने पर बैठे भाजपा सरकार के जिम्मेदार नेता दिल्ली में सफाई और सुरक्षा की दुर्दशा भी देख लें।

पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान राय ने कहा कि भाजपा सांसद और नेता जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1993 में भाजपा ने सरकार बनाई थी। तब पांच सालों में तीन मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा था, जो एक रिकॉर्ड है। पहले मदनलाल खुराना फिर साहिब सिंह वर्मा और उसके बाद सुषमा स्वराज। यदि भाजपा के पास इन कॉलोनियों के विकास कार्य को लेकर कोई आंकड़े हों तो बताएं। केंद्र में भी पांच साल बीत गए। अब दोबारा फिर से सरकार में आ गए हैं। अब तक कुछ कर लिया हो तो वह भी बता दें।

राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का इतिहास रहा है कि इन इलाकों के वासियों को कभी दिल्ली का समझा ही नहीं गया। यही वजह थी कि इन कॉलोनीवालों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। कांग्रेस सरकार ने भी काम की जगह सिर्फ जुमलेबाजी की थी, जमीन पर कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर दो नवंबर 2015 को कैबिनेट में पास किया और 15 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार को भेज दिया था। उसके बाद से लगातार केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए पत्र पर पत्र लिखे जा रही है। इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा 15 दिनों में जवाब मांगा गया था, जिसको केजरीवाल सरकार ने सात दिनों में ही भेज दिया।

न्यूज गैलरी

रोहित शेखर की हत्या में आरोपित अपूर्वा की जमानत याचिका रद

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपित उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका रद कर दी है। साकेत कोर्ट में अपूर्वा के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जिसके तहत अपूर्वा जमानत की हकदार हैं। इसके विरोध में पुलिस ने कहा कि अभी जांच जारी है। इस मामले में पुलिस ने 18 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें कहा था कि भाभी के साथ शराब पीने पर हुए झगड़े के बाद अपूर्वा ने रोहित की गला दबाकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कोर्ट में अपूर्वा के खिलाफ 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें 56 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी भी शामिल हैं। आरोप पत्र में अपूर्वा (35) पर धारा 302 के तहत आरोप लगा है जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है। (जासं)

आइपीएस अफसर की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा

ग्रेटर नोएडा : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने आइपीएस अफसर की पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय ने नोएडा सेक्टर-24 कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मनोज कुमार ने की। अधिवक्ता अनुज नागर ने बताया कि दिल्ली स्थित शोरूम के मालिक हेमंत बिष्ट ने कोर्ट में लगाई अर्जी में कहा कि नोएडा के सेक्टर-52 निवासी सोमिया सिंह ने फरवरी 2018 में उनके शोरूम से 22 लाख का फर्नीचर खरीदा था। आठ लाख का भुगतान कर दिया गया, जबकि बकाया 14 लाख रकम नहीं दी गई। आरोप है कि पीड़ित ने जब बकाया मांगा तो महिला ने धमकी दी कि उसके पति यूपी कैडर के आइपीएस हैं। आइपीएस पति पूर्वांचल के एक जिले में तैनात हैं। बकाया रकम नहीं दी जाएगी। (जासं)

पटना से दिल्ली आ रहे विमान में बच्ची की मौत

नई दिल्ली : पटना से दिल्ली आ रहे स्पाइसजेट के विमान में छह महीने की बच्ची रचिता की मौत हो गई है। वह हार्ट की बीमारी से पीड़ित थी। उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाया जा रहा था। बच्ची के पिता राजेंद्र रंजन मूलरूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन बच्ची को लेकर बुधवार रात पटना से दिल्ली आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-8481 में सवार हुए थे। रास्ते में बच्ची ने दम तोड़ दिया। आइजीआइ एयरपोर्ट के डीसीपी संजय भाटिया ने बताया कि बच्ची जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थी। उसके दिल में छोटा छेद था। उसका इलाज एम्स में चल रहा था। विमान में बच्ची के साथ उसके माता-पिता भी थे। उन्होंने किसी पर भी संदेह नहीं जताया है। (जासं)

एनबीसीसी ने तैयार किया 11 हजार करोड़ जुटाने का खाका

राहत के आसार ▸ सुप्रीम कोर्ट में दिया रोडमैप, आम्रपाली बिल्डर की परियोजनाओं को पूरा करने का भार निवेशकों पर टिका

बिल्डर की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42 हजार हैं निवेशक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

आम्रपाली बिल्डर की परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये की जरूरत का नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) ने अनुमान लगाया है। इस पूंजी को बिल्डर की प्रॉपर्टी व निवेशकों से जुटाया जाएगा। एनबीसीसी ने 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक रकम जुटाने का रोडमैप सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आम्रपाली बिल्डर की परियोजनाओं के निवेशक से मिलेगा। निवेशकों से वसूल कर दूसरी जगहों पर निवेश की गई रकम की रिकवरी से तीन हजार करोड़ से अधिक रकम जुटाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर की अधर में फंसी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए एनबीसीसी को जिम्मेदारी सौंप दी है। सबसे बड़ी चुनौती इन परियोजनाओं को पूरा करने में खर्च होने वाली रकम को जुटाने की है। परियोजनाओं को पूरा कराने का दारोमदार भी उन निवेशकों के कंधे पर टिका है, जिनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट को जो रोडमैप सौंपा है, उसके तहत वह 11320.42 करोड़ रुपये जुटा सकता है। जबकि परियोजना को पूरा करने में करीब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। एनबीसीसी के इस आकलन से उम्मीद है कि आम्रपाली बिल्डर की फंसी परियोजनाओं को पूरा करने में कोई अड़चन नहीं होगी।

आम्रपाली बिल्डर की विभिन्न परियोजना में करीब 42 हजार निवेशक हैं। इनसे 3624.65 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। फ्लैट बेचकर 321.31 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। बिल्डर की कामर्शियल प्रॉपर्टी के निवेशकों से 89.83 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

बिल्डर परियोजनाओं में बड़ी संख्या में बिना बिके फ्लैट हैं। एनबीसीसी इन फ्लैट की बिक्री से 1991.69 करोड़ रुपये जुटाएगा। इसके अलावा कामर्शियल प्रापर्टी को बेचकर 345.78 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। इस लिहाज से एनबीसीसी बिल्डर परियोजनाओं के मौजूदा निवेशकों व बचे हुए फ्लैट एवं कामर्शियल प्रापर्टी को बेचकर चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाएगा, जो फंसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि का लगभग आधा है। आम्रपाली बिल्डर ने निवेशकों से 12 हजार करोड़ से अधिक रकम वसूलकर उसका अधिकतर हिस्सा अन्य कंपनियों में निवेश कर दिया था। एनबीसीसी का आकलन है कि निवेशकों के 3152.30 करोड़ रुपये का डायवर्जन किया गया। एनबीसीसी इस रकम को वापस वसूलकर बिल्डर परियोजनाओं को पूरा करने में लगाएगा। इसके अलावा सप्लायर से खरीदी गई अनुपयोगी सामग्री व अन्य मदों से शेष रकम को जुटाया जाएगा। इसमें करीब पंद्रह करोड़ के गहने व डिपोजिट, 69 करोड़ नकद शामिल हैं।

11 आरोपितों को ईडी ने भेजा नोटिस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने धांधली से जुड़े 11 आरोपितों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों के अनुसार इनमें कुछ उन कंपनियों के संचालक भी शामिल हैं, जिन्होंने आम्रपाली ग्रुप ने करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए थे।

ईडी आम्रपाली ग्रुप के संचालकों की बेनामी संपत्तियों का ब्योरा भी जुटा रहा है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आम्रपाली ग्रुप से दूसरी और किन-किन कंपनियों को फंड ट्रांसफर किए गए और उस रकम का निवेश कहां किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी माह ईडी ने 42 हजार से अधिक निवेशकों को मकान का सपना दिखाकर करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) के तहत केस दर्ज किया है। आम्रपाली ने नोएडा में बहुमंजिला इमारतें बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बीच में ही काम को अधूरा छोड़ दिया गया। आम्रपाली ग्रुप की करीब 46 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। निवेशकों ने कंपनी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज कराए थे। कई निवेशकों ने अपनी डूबी रकम हासिल करने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन पदाधिकारी जेल में हैं।

मायावती के भाई आनंद की चौकड़ी करती थी भूखंड आवंटन का फैसला

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश में बसपा शासन काल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की लगाम किसी बड़े नौकरशाह के हाथ में नहीं थी। प्राधिकरण में निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर भूमि आवंटन तक का फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद के दिल्ली दरबार में होता था। आनंद के साथ हर समय एक चौकड़ी रहती थी। इसमें स्वयं आनंद के अलावा तीन अन्य लोग शामिल थे। इनमें एक सरकारी सेवा में था, जबकि दो निजी थे। चौकड़ी की मंजूरी के बाद ही प्राधिकरण अधिकारी कोई फैसला लेते थे।

हैरत की बात यह है कि प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यों पर विचार-विमर्श के लिए लखनऊ में शासन स्तर पर बैठक नहीं बुलाई जाती थी। सारे फैसले आनंद के दरबार में होते थे। 2007 से 2010 के बीच प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों ने सरकार के बजाय आनंद के लिए काम किया। नतीजतन बिल्डरों को दस फीसद धनराशि पर जमीन आवंटित की जाने लगी। सबसे पहले यह फैसला 2008-09 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ पंकज अग्रवाल व नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ मोहिंदर सिंह के कार्यकाल में हुआ। बोर्ड से प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा गया। शासन ने इस पर एक कमेटी बनाई। कमेटी ने आंख मूंद कर आर्थिक मंदी का हवाला देकर दस फीसद धनराशि पर भूखंड देने की संस्तुति कर दी। इसके बाद प्रदेश सरकार के तत्कालीन प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास व औद्योगिक विकास आयुक्त बीएन गर्ग ने प्राधिकरणों को पत्र भेजकर शासनादेश से अवगत कराया। इसके बाद दस फीसद धनराशि पर भूखंड आवंटित किए जाने लगे। इससे मोहिंदर सिंह का सरकार की नजरों में कद बढ़ गया। पहले उन्हें सिर्फ नोएडा प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण का भी सीईओ बना दिया गया।

बिल्डरों के नाम तय होने के बाद निकाले जाते थे टेंडर : बिल्डर योजना के भूखंडों का आवंटन नीलामी के आधार पर होता था। भूखंड आवंटन से पहले आनंद के दरबार में यह तय हो जाता था कि किस बिल्डर को जमीन आवंटित की जानी है। नाम तय होने के बाद भूखंड का आरक्षित मूल्य तय किया जाता था। टेंडर के प्रपत्र सिर्फ उसी बिल्डर को दिए जाते थे, जिसके लिए आवंटन होना होता था। औपचारिकता पूरी करने के लिए एक-दो अन्य बिल्डरों से कम दर पर टेंडर डलवाए जाते थे, ताकि कोई टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा न करे।

कैट ने कहा, भ्रामक विज्ञापन के लिए धौनी पर हो कार्रवाई

जासं, नई दिल्ली : आम्रपाली समूह मामले में क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कारोबारी संगठन कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से आम्रपाली समूह को बढ़ावा देने वाले भ्रामक विज्ञापन को लेकर दिग्गज क्रिकेटर धौनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

रामविलास पासवान को भेजे ज्ञापन में कैट ने कहा कि धौनी ने विज्ञापन के माध्यम से आम्रपाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने के लिए लोगों को बहुत प्रभावित किया है। बिल्डर दोषी पाया गया है इसलिए धौनी की भी जवाबदेही बनती है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि मशहूर लोग विज्ञापनों के लिए बड़ी रकम लेते हैं, लेकिन बिना तथ्यों की पुष्टि किए कि वे जिस सामान या सेवाओं का समर्थन कर रहे हैं, वे उसके लायक है या नहीं इसकी जवाबदेही नहीं लेते। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से संसद के वर्तमान सत्र में उपभोक्ता सुरक्षा विधेयक पारित करने को सुनिश्चित करने की मांग की। खंडेलवाल ने कहा कि इसके माध्यम से भ्रामक विज्ञापनों में मशहूर हस्तियों की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

दंपती बेटी संग चौथी मंजिल से कूदा, पति की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कर्ज से तंग

- मृतक सुरेश ने नौ बैंकों के ले रखे थे क्रेडिट कार्ड
- इनके बिल का भुगतान नहीं होने से करीब आठ लाख रुपये का कर्ज हो गया था

जगतपुरी में कर्ज से परेशान एक दंपती ने चार साल की बेटी के साथ मकान की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना में पति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेश कुमार (34) के रूप में हुई है। पत्नी मंजीत कौर (31) और बेटी तान्या का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

मंजीत कौर के बयान से पता चला है कि सुरेश ने नौ बैंकों के क्रेडिट कार्ड ले रखे थे। इनके बिल का भुगतान नहीं कर पाने के कारण करीब आठ लाख रुपये कर्ज हो गया था। इसे चुकाने में सुरेश असमर्थ था। इससे परेशान होकर परिवार ने यह कदम उठाया। मंजीत कौर के बयान पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

पंजाब के होशियारपुर का है परिवार : जानकारी के मुताबिक मूलरूप से होशियारपुर, पंजाब निवासी सुरेश कुमार परिवार के साथ जगतपुरी में रहता था। वह गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करता था। करीब छह साल पहले मंजीत कौर से उसकी शादी हुई थी। दोनों से करीब चार साल की एक बेटी है। सुरेश अपने ससुर कुलवंत सिंह के मकान में भूतल पर रहता था।

नौ बैंकों से ले रखे थे क्रेडिट कार्ड : सुरेश का वेतन कम था, लेकिन खर्च अधिक था। इसी वजह से उसने करीब नौ बैंकों से क्रेडिट कार्ड ले रखे थे। वह अपने वेतन से इनका बिल नहीं चुका पा रहा था। इस वजह से एक क्रेडिट कार्ड बंद होता तो वह दूसरा ले लेता था। इस तरह से उस पर करीब आठ लाख रुपये का कर्ज हो गया। बिल का भुगतान न कर पाने के कारण बैंक उस पर भुगतान के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। इससे वह परेशान था।

गत रविवार रात को सुरेश ने पत्नी से आत्महत्या करने की बात की। आधी रात करीब तीन बजे सुरेश सोती हुई बेटी तान्या को लेकर चौथी मंजिल की छत पर जाने लगा। पीछे-पीछे मंजीत भी चली गई। छत पर पहुंचकर वह बेटी को गोद में लेकर नीचे कूद गया। इसके बाद मंजीत ने भी पीछे से छलांग लगा दी। आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी बाहर निकले तो तीनों खून से लथपथ पड़े थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तीनों को हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद सुरेश का शव उसके परिवार को सौंप दिया। बुधवार को मंजीत के होश में आने पर पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया।

तीन दिन से मां-बेटी ने एक-दूसरे को नहीं देखा : जीटीबी अस्पताल में मंजीत और तान्या अलग-अलग विभाग में भर्ती हैं। तान्या हड्डी रोग विभाग में आइसीयू में है। उसके दोनों पैरों में फैक्चर था। इसका ऑपरेशन कर दोनों पैरों में रॉड लगाया गया है। उधर, मां मेडिसीन विभाग में भर्ती हैं। उनके सिर में चोट आई है। इसकी वजह से उन्हें बार-बार उल्टी आ रही है। घटना के बाद मां-बेटी ने एक-दूसरे को नहीं देखा है। उनकी देखभाल के लिए मंजीत के भाई गुरदीप सिंह अस्पताल में ही मौजूद हैं।

यमुना प्राधिकरण ने दो बिल्डरों के भूखंड आवंटन किए रद

जासं, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। यमुना प्राधिकरण ने गुरुवार को दो बिल्डरों का भूखंड आवंटन निरस्त कर दिया। दोनों बिल्डरों पर प्राधिकरण का करोड़ों रुपया बकाया था। नोटिस के बाद भी बिल्डरों ने प्राधिकरण का बकाया नहीं जमा किया है।

सीईओ अरुणवीर सिंह ने दो बिल्डरों को आवंटित ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया। दोनों का सबलीज कराया गया था। उन्होंने बताया कि लोटस बिल्ड मार्ट व स्वीकृति इंफ्राकॉन का आवंटन निरस्त किया गया है। लोटस बिल्ड मार्ट को 2011 में सेक्टर-22 डी में 10332 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित हुआ था। बिल्डर पर प्राधिकरण का छह करोड़ नब्बे लाख बकाया हो चुका है। बिल्डर ने अभी तक न तो नक्शा पास कराया और न ही बुकिंग कर निर्माण शुरू किया था। स्वीकृति इंफ्राकॉन का भी 22 डी में 25 हजार वर्गमीटर का भूखंड आवंटन निरस्त किया गया है। इस पर प्राधिकरण का 15 करोड़ रुपया बकाया है। प्राधिकरण बकायेदार बिल्डरों की सूची तैयार कर रहा है, जिसमें कोई परियोजना लांच नहीं हुई है।

स्वच्छता का पाठ कोई इनसे सीखे

स्वच्छता के असली ब्रांड एंबेसडर तो मासूम बच्चे ही होते हैं। इन्हें कोई पब्लिसिटी की जरूरत नही। इंडिया गेट लॉन में परिजन के साथ आए एक मासूम को वहां बिखरे कचरे को डस्टबिन में डालते देख उपस्थित लोग निहारते रह गए। संजय

कामयाबी

डॉक्टरों की दो टीमों ने साढ़े पांच घंटे की सर्जरी में दोनों अंगों से निकाले ट्यूमर, अस्पताल का दावा- दुनिया में पहली बार इस तरह की सर्जरी की गई

स्तन कैंसर और दिल का ट्यूमर एक साथ निकाला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों ने स्तन कैंसर और दिल में ट्यूमर की बीमारी से जूझ रही महिला मरीज की एक ही बार में दो सर्जरी करने में कामयाबी हासिल की है। मरीज को बेहोश करने के बाद दो अलग-अलग डॉक्टरों की टीम ने साढ़े पांच घंटे की सर्जरी में दोनों अंगों से ट्यूमर निकाले। अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि दुनिया में पहली बार इस तरह की सर्जरी की गई है। सर्जरी के बाद बिहार के गोपालगंज की रहने वालीं रेणु श्रीवास्तव (47) के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं।

अस्पताल के आंकोलॉजी विभाग के डॉ. मनदीप मल्होत्रा ने बताया कि जब मरीज को अस्पताल लाया गया था, तब वह स्तन कैंसर से पीड़ित थीं। उनके दाएं स्तन में कैंसर का ट्यूमर था, जो की तीसरे स्टेज में पहुंच चुका था। चेस्ट की सीटी स्कैन जांच में पता चला कि उनका फेफड़ा बिल्कुल ठीक था, लेकिन दिल के बाएं एट्रियम में ट्यूमर था। इसलिए बाद में 2डी इकोकार्डियोग्राफ, एंजियोग्राफी व एक अन्य जांच की गई, जिससे यह पता चला कि दिल में एट्रियल मायक्सोमा नामक बिनाइन ट्यूमर था। यह कैंसर नहीं था, लेकिन इसके कारण मरीज को ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा था। इसलिए दोनों ट्यूमर को सर्जरी कर निकालना जरूरी था। इसलिए डॉक्टरों ने एक साथ दोनों सर्जरी करने का फैसला किया।

रेणु श्रीवास्तव की एक साथ दो सर्जरी की गई। अब वह स्वस्थ हैं। फोटो सौजन्य : डॉक्टर

एक साथ दो सर्जरी थी चुनौतीपूर्ण : डॉक्टर कहते हैं कि एक साथ दो सर्जरी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि इससे मरीज को जोखिम था, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता और दोनों ट्यूमर निकालने के लिए दो बार सर्जरी करनी पड़ती। यह मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि स्तन कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच गया था। इसलिए उसकी जल्द सर्जरी जरूरी थी। यदि पहले स्तन कैंसर की सर्जरी की जाती तो मरीज के दिल की सर्जरी के लिए स्वस्थ होने में समय लगता। कैंसर की सर्जरी के बाद मरीज को कीमों और रेडियोथेरेपी भी देनी होती है। ऐसी स्थिति में मरीज का दिल कमजोर हो जाता। इसलिए ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता। यदि पहले ओपन हार्ट सर्जरी कर दिल से ट्यूमर निकाला जाता तो मरीज को स्तन कैंसर की सर्जरी के लिए काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता। ऐसे में कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता था। इसलिए दोनों सर्जरी एक साथ करने का फैसला किया गया। कार्डिक सर्जन डॉक्टरों की टीम ने ओपन हार्ट सर्जरी कर पहले मरीज के दिल से ट्यूमर निकाला। मरीज की हालत स्थिर होने के बाद सर्जिकल आंकोलॉजी के डॉक्टरों ने स्तन कैंसर का ट्यूमर निकाला।

बुजुर्गों के लिए छुट्टी के दिन भी सेवा देंगे डॉक्टर

रणविजय सिंह, नई दिल्ली : रविवार को इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहती है। इसलिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए भी रविवार आराम का दिन होता है, लेकिन केंद्र सरकार के सफदरजंग अस्पताल में हर रविवार को बुजुर्गों के लिए विशेष जेरियाट्रिक क्लीनिक चलेगा। इस रविवार से ही तीन घंटे की ओपीडी शुरू होगी, जहां डॉक्टर बुजुर्गों का इलाज करेंगे। देश में पहली बार सरकारी अस्पताल में इस तरह की पहल की गई है।

अस्पताल प्रशासन ने बकायदा इसके लिए आदेश जारी कर संबंधित विभागों के डॉक्टरों को सूचित कर दिया है। अस्पताल के डॉक्टर भी इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पायलट परियोजना के तहत सफदरजंग अस्पताल में जेरियाट्रिक क्लीनिक शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका फायदा यह होगा कि बुजुर्गों को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद है कि शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सफदरजंग अस्पताल में इस क्लीनिक का शुभारंभ करेंगे।

नोएडा में फर्जी लोन कंपनी का भंडाफोड़, 33 आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

नोएडा के सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र में ठगी के लिए चलाई जा रही फर्जी लोन कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित लोन देने के नाम पर लोगों को फोन करते थे और फाइल चार्ज के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे, जबकि पीड़ित को किसी तरह का कोई लोन नहीं दिया जाता था। यह काम कॉल सेंटर के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा पीड़ितों को फोन कराकर संचालित किया जा रहा था। पिछले सात महीने से यह फर्जी कंपनी चल रही थी। आरोपित करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं। कंपनी का खाता पुलिस ने फ्रिज कर दिया है। खाते में मोटी रकम मौजूद है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र में फर्जी लोन कंपनी संचालित होने की शिकायत मिली थी। मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई। सेक्टर तीन स्थित ई 54 में छापेमारी कर ठगी करने वाली कंपनी कॉमरेड फिनोकॉन का भंडाफोड़ किया गया। मौके पर 33 लोगों को पकड़ा गया। इनमें कर्मचारी और प्रबंधक शामिल हैं। कंपनी का मालिक फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। आरोपित पूरे देश के लोगों को फोन कर पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन व एग्रीकल्चर लोन आदि देने का झांसा देते थे। उसके बाद फाइल चार्ज व अन्य खर्च के नाम पर मोटी रकम कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा लेते थे। खाते के अलावा आरोपित पेटीएम, फोन पे, गूगल पे में भी रकम ट्रांसफर करवाते थे। आरोपित प्रबंधक संजय से पूछताछ के दौरान पता चला है कि कंपनी की शाखा अलीगढ़ में भी है। कंपनी मालिक अनुज, शुभम व अजय फरार हैं। मौके से पुलिस ने एक डेस्कटॉप, 18 मोबाइल, तीन मुहर और 95 फार्म बरामद किए हैं।

ग्राहकों को फोन करने के लिए फर्जी लोन कंपनी ने मोबाइल कंपनी से समझौता किया हुआ था। ग्राहकों का मोबाइल नंबर मोबाइल कंपनी से ही आरोपितों तक पहुंचता था।

7 अगस्त तक के लिए संसद सत्र को बढ़ा दिया गया है। विधेयक पारित कराने की लंबी सूची को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में सत्र की अवधि बढ़ाने का एलान किया। 17वीं लोकसभा का मौजूदा बजट सत्र पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 26 जुलाई तक चलने वाला था।

ये थे कारगिल के शेरशाह

कैप्टन विक्रम बत्रा

जन्म : 9 सितंबर, 1974, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
शहीद हुए : 7 जुलाई, 1999 (24 वर्ष)
यूनिट : 13 जेएंडके रायफल

शौर्य गाथा : इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पासआउट होने के बाद 6 दिसंबर, 1997 को लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर रायफल 6 जून को द्रास पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को प्वाइंट 5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पोजीशन पर कब्जा किया। उनका अगला अभियान था 17,000 फीट की ऊंचाई पर प्वाइंट 4875 पर कब्जा करना। पाकिस्तानी फौज 16,000 फीट की ऊंचाई पर थीं और बर्फ से ढ़कीं चट्टानें 80 डिग्री के कोण पर तिरछी थीं। 7 जुलाई की रात वे और उनके सिपाहियों ने चढ़ाई शुरू की। अब तक वे दुश्मन खेमे में भी शेरशाह के नाम से मशहूर हो गए थे। साथी अफसर अनुज नायर के साथ हमला किया। एक जूनियर की मदद को आगे आने पर दुश्मनों ने उनपर गोलियां चलाईं, उन्होंने ग्रेनेड फेंककर पांच को मार गिराया लेकिन एक गोली आकर सीधा उनके सीने में लगी। अगली सुबह तक 4875 चोटी पर भारत का झंडा फहरा रहा था। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जरा याद करो कुर्बानी...

तीन तलाक बिल पर तीखी बहस

तकरार ▶ विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

ओवैसी ने कहा, पति जेल जाएगा तो पत्नी को मुआवजा कहां से देगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पर सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। विपक्ष ने बिल को लेकर सरकार की जल्दबाजी का हवाला देते हुए मंशा पर सवाल उठाए। लंबी बहस के बाद जब विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ, तब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने सदन से वाकआउट किया। बहस के दौरान विपक्ष की ओर से बिल के औचित्य पर ही सवाल खड़ा किया गया। विपक्ष का कहना था कि जब कोर्ट के फैसले के बाद तीन तलाक गैरकानूनी हो गया है, तो फिर सरकार को इसके लिए कानून बनाने की जरूरत ही क्या है।

थरूर ने बिना तलाक पत्नी को छोड़ने का मुद्दा उठाया : कांग्रेस के शशि थरूर ने बिना तलाक लिए भी पत्नी को छोड़ देने के मामले में किसी सजा का प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया। राजनीतिक मंशा का भी सवाल उठाया गया। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के प्रेमचंद्रन ने मॉब लिंचिंग मामले में कानून नहीं बनाने और तीन तलाक पर तत्परता दिखाने पर कहा, भाजपा अपना एजेंडा लागू कर रही है। यह बिल मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा नहीं, पतियों के उत्पीड़न के लिए है।

लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक समुदाय के ही अन्य धर्मों में तलाक में सजा का प्रावधान नहीं होने का हवाला देते हुए बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया। ओवैसी ने कहा, पति को सजा होने की स्थिति में वह पत्नी को मुआवजा कहां से देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम में शादी जन्मों का साथ नहीं बल्कि कांट्रैक्ट है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग करना चाहती है। मुस्लिमों की तुलना में हिंदू महिलाओं को ज्यादा संख्या में तलाक दिया जा रहा है।

नकवी बोले, कांग्रेस के पाप का नतीजा भुगत रहा देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **कहा, 1986 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए बिल लाई थी**
- **बोले- मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए बिल लाई है**

मुख्तार अब्बास नकवी फाइल फोटो

तीन तलाक बिल का विरोध कर रही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि साल 1986 में कांग्रेस ने जो पाप किया उसका नतीजा देश को भुगतना पड़ा है। शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने वाले विधेयक का हवाला देते हुए नकवी ने कहा कि 5 मई, 1986 को कांग्रेस की सरकार ने इसी सदन में उस विधेयक को पारित कराया था।

नकवी ने लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा, 'कांग्रेस ने कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया। उस दिन के बाद से आज तक उसे सजा के तौर पर देखा जाता है।' नकवी ने कहा कि यह बिल सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता का परिचायक है जिसका लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना है, जबकि कांग्रेस उस वक्त संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए बिल लाई थी। नकवी ने कहा 'हमारा देश शरीयत और धार्मिक कानून से नहीं चलता। इस देश में चाहे कोई मुस्लिम हो या हिंदू संविधान की नजर में सभी समान है। हमारा संविधान लैंगिक समानता की भावना पर चलता है। क्या हम इसे भूल सकते हैं?' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई इस्लामिक देशों ने भी तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया है। जबकि भारत को इसे खत्म करने में 70 साल लग गए। '70 साल बाद जब मोदी सरकार इसे समाप्त करने का काम कर रही है तब आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं।'

संसद सत्र

पहले चरण में 2.2 करोड़ लोगों को मिलेंगे ई-पासपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि सरकार ई-पासपोर्ट की शुरुआत की दिशा में काम कर रही है। मंत्रालय की योजना लोगों को चिपयुक्त अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधा वाले ई-पासपोर्ट उपलब्ध कराने की है। पहले चरण में इसे 2.2 करोड़ लोगों को जारी किया जाएगा।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि आवेदक के बारे में सभी जानकारियां चिप में दर्ज होंगी। अगर चिप में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो इसकी पहचान की जा सकेगी। परिणामस्वरूप पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाएगी।

जयशंकर ने कहा कि मंत्रालय निविदा प्रक्रिया के अंतिम दौर में है। इसके दो पहलू हैं- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू। सरकार ने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस (आइएसपी) नासिक को ई-पासपोर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण (इलेक्ट्रानिक कांटैक्टलेस इनलेज) की खरीद की अनुमति दे दी गई है। साथ ही उसे तीन स्तरीय वैश्विक निविदा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। निविदा व खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-पासपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होगा।

एस. जयशंकर फाइल फोटो

पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा राज्यसभा में उठा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा गुरुवार को संसद में उठा। राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय की लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि इस पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाना चाहिए।

- **भाजपा सदस्य ने कहा, पाकिस्तान में 1947 में 31 फीसद हिंदू थे जो घटकर 1.2 फीसद रह गए**

शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा के किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले बढ़े हैं। करीब एक हजार लड़कियों का इस तरह धर्म परिवर्तन किया गया है। भाजपा सदस्य ने कहा कि पड़ोसी देश के अस्तित्व में आने के 71 साल बाद वहां हिंदुओं की आबादी घटकर 1.2 फीसद रह गई है जो 1947 में 31 फीसद थी।

उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि भारत सरकार को पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोका जा सके। मीणा ने कहा 'जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा गया और सिखों को गुरुद्वारों से बाहर निकाला गया। मीणा ने कहा कि मानवाधिकारों के नजरिये से पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं है और वहां की इमरान सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

धोखेबाज बिल्डरों को मिले फांसी की सजा

नई दिल्ली, आइएएनएस : लालची बिल्डरों द्वारा घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की तुलना दुष्कर्म से करते हुए भाजपा सांसद विजय गोयल ने उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। राज्यसभा में शून्य काल के दौरान उन्होंने ऐसे बिल्डरों की आवासीय परियोजना का विज्ञापन करने वाली चर्चित हस्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।

गोयल ने कहा कि लाखों घर खरीदारों ने फ्लैट बुक कराने में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है। लेकिन लालची बिल्डरों ने उनके साथ धोखा किया है। बिल्डरों ने ऐसे घर खरीदारों के साथ धोखा और ठगी की है। ऐसे लालची बिल्डरों को मौत की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया है वह दुष्कर्म से कम नहीं है। गोयल ने कहा कि कुछ हस्तियां भी ऐसे बिल्डरों से जुड़ी हैं। घटिया उत्पाद साबित होने की दशा में उसका विज्ञापन करने वाली हस्तियों के लिए दंड का प्रावधान है। ऐसे में बिल्डरों के ब्रांड एंबेसडर को भी दंड मिलना चाहिए।

गौतम गंभीर ने प्रदूषण पर जताई चिंता

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने गुरुवार को लोकसभा में पहला भाषण दिया। इसमें उन्होंने भारतीय शहरों के प्रदूषण पर चिंता जताई। उन्होंने दिल्ली के गाजीपुर लैंडफील्ड का मुद्दा खासतौर पर उठाया।

शून्यकाल के दौरान गंभीर ने कहा कि लोगों ने दिल्ली सरकार से उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए वह केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि समस्या के विकराल और अनियंत्रित होने से पहले इसके समाधान के प्रयास किए जाएं। केंद्र को इसके लिए नीति बनानी चाहिए। गंभीर ने कहा कि प्रदूषण के कारण हर साल स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ती हैं। विश्व के 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। पर्यावरण प्रदूषण गहरी चिंता का विषय है और यह सभी को प्रभावित करता है। गाजीपुर लैंडफील्ड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वी, मध्य व पुरानी दिल्ली का कूड़ा यहां फेंका जाता है। आलम यह है कि अब इसकी ऊंचाई 65 मीटर हो गई है।

लोगों को परेशान करने वाले 58 और पुराने कानून खत्म होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार लोगों को परेशान करने वाले और 58 पुराने कानूनों को समाप्त करने जा रही है। लोकसभा में गुरुवार को इन कानूनों को समाप्त करने के लिए विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कानून लोगों के लिए असुविधा के कारण बने हुए हैं। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि सरकार सांसदों को विषय पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिए बगैर विधेयक पेश कर रही है।

प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 1,458 पुराने कानून को निष्प्रभावी कर चुकी है। उसी प्रयास के तहत अब 58 और को समाप्त करने जा रही है। उन्होंने विपक्ष के इस दावे को भी खारिज किया कि सदस्यों को विधेयक का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। कानून मंत्री ने कहा कि दो दिनों का नोटिस दिया गया था। सदस्य इस पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि यह अभी पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में विधेयक पर पर्याप्त रूप से चर्चा की जा चुकी है। इसमें सभी बड़ी पार्टियों के सदस्य मौजूद थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगल सत्र से वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि विधेयक पेश होने से पहले उसका अध्ययन करने के लिए सदस्यों को दो दिनों का समय मिले। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के कानून समाप्त किए जाने चाहिए और उसकी जगह नए कानून लागू होने चाहिए।

रविशंकर प्रसाद फाइल फोटो

- **लोकसभा में केंद्र सरकार ने विधेयक पेश किया**
- **कानून मंत्री बोले, ये कानून लोगों के लिए असुविधा के कारण बने हुए हैं**

कुछ सदस्यों ने कहा कि भारतीय दंड संहिता भी ब्रिटिश कालीन है। सत्ताधारी और विपक्षी सदस्यों के बीच हो रही बहस में बीजद के भर्तृहरि महताब सरकार के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में तय एजेंडा ठहर गया है। पिछली सरकार द्वारा पूरक एजेंडे के तहत सदस्यों के बीच विधेयक वितरित किया गया था। अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि वह विधेयक के विरोध में नहीं हैं लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जल्दबाजी में है।

आरटीआइ संशोधन विधेयक पर विपक्ष हुआ गर्म, जोरदार हंगामा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरटीआइ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों की मुख्य मांग इसे प्रवर समिति में भेजने को लेकर थी जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके लिए विपक्षी दलों के सदस्यों ने वेल में नारेबाजी करके दबाव बनाने की कोशिश भी की जो करीब डेढ़ घंटे तक जारी रही।

उपसभापति ने चर्चा के बाद विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग पर वोटिंग कराने का भरोसा दिया तब जाकर विपक्ष शांत हुआ। इसके बाद शुरू हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से पूछा कि आरटीआइ में सेवा शर्तों और वेतन-भत्तों को लेकर जो बदलाव किया जा रहा है, उसके पीछे क्या वजहें हैं? उन्होंने इस बदलाव के जरिये सूचना आयोग को सरकारी ऑफिस बनाने की बात कही। चर्चा में सपा सांसद जावेद अली खान, जदयू के रामचंद्र प्रसाद सिंह, बीजद के सस्मित पात्रा, भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला, कांग्रेस के जयराम रमेश आदि ने हिस्सा लिया। वहीं, सदन में नारेबाजी करने वाली पार्टियों में कांग्रेस के साथ द्रमुक, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल थी।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन चलाने की दिखाई नई कला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर चल रही तनातनी और खींचतान के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों पक्ष के हीरो बनकर उभरने लगे हैं। गुरुवार को ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष की ओर से उनके लिए मेज थपथपाई गई और एक मौका तो ऐसा आया जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आशा जताई कि बिरला कॉमनवेल्थ देशों के बेस्ट स्पीकर बनकर उभरें। वहीं एक अवसर पर जब सत्तापक्ष और विपक्ष में दोषारोपण चल रहा था तो बिरला ने सत्तापक्ष को हिदायत दी कि सदन केवल संख्याबल पर नहीं बल्कि सहमति से चलेगा। इस पर विपक्ष में बैठे कई सदस्यों ने मेज थपथपाई।

गुरुवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए गए। एक विधेयक अप्रासंगिक हो चुके ब्रिटिश कालीन 58 कानूनों को निरस्त करने से संबंधित था, दूसरा अंतरराज्जीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना से जुड़ा था। इसके जरिए देश के छह जल विवाद ट्रिब्यूनल को समाप्त कर एक ट्रिब्यूनल बनाने तथा दो साल के अंदर उसका समाधान करने से संबंधित था। तीसरा विधेयक कंपनी कानून में संशोधन से जुड़ा था। इसके माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के जरिए कुछ कंपनियों को भिन्न-भिन्न वित्तीय वर्ष रखने देने का अधिकार दिया गया है। इसमें कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई आरंभ करने के लिए पंजीयक को सशक्त करने की भी बात है।

विपक्ष का आरोप था कि संसद के नियमों के अनुसार सरकार को विधेयकों की पहले जानकारी देनी चाहिए थी। ताकि विपक्ष उस पर अपना मत तैयार कर सके। लोकसभा अध्यक्ष ने तत्काल भरोसा दिया कि अगले सत्र से इस नियम का पालन होगा।

आजम खां की टिप्पणी पर लोकसभा में बवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **स्पीकर के आसन पर बैठीं रमादेवी को लेकर की थी टिप्पणी**
- **भाजपा सांसदों ने कहा, माफी मांगे सपा सांसद आजम खां**

लोकसभा में सदन अध्यक्ष के आसन पर बैठकर कार्यवाही का संचालन करतीं भाजपा सांसद रमा देवी (बाएं)। उन्ही के बारे में आजम खां (दाए)की टिप्पणी को लेकर सत्तापक्ष ने सदस्यों ने विरोध जताया। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में हस्तक्षेप कर मामले का पटाक्षेप किया। प्रेट्र

लोकसभा में तत्काल तीन तलाक विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खां ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सदन में बवाल हो गया। आजम खां ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर से की, 'तू इधर-उधर की न बात कर...' लेकिन इसके बाद आजम खां की एक आपत्तिजनक टिप्पणी पर भाजपा की ओर से हंगामा शुरू हो गया। आजम खां के बोलने के वक्त स्पीकर के आसन पर भाजपा सांसद रमा देवी थीं और आजम की टिप्पणी सीधे उनसे संबंधित थी।

आजम खां ने जैसे ही बोलना शुरू किया, लोकसभा स्पीकर के आसन पर बैठीं रमा देवी ने उनसे उनकी तरफ देखकर बोलने को कहा। लेकिन उसके बाद आजम ने जो टिप्पणी की उस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध जताया। इसके बाद रमा देवी ने आजम खां के शब्दों को संसद की कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया। मामला इतने भर से शांत नहीं हुआ। भाजपा सांसदों ने आजम खां की माफी की मांग रखी। इस पर आजम के समर्थन में सपा के अखिलेश यादव भी उतरे। अखिलेश और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस भी हुई। अखिलेश के एक शब्द को लेकर भी भाजपा सांसदों ने आपत्ति की। मामला तूल पकड़ता देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सदन में आना पड़ा।

बिरला ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि स्पीकर के आसन की मर्यादा रखनी चाहिए। आसन पर कोई भी बैठा हो, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मर्यादा भंग होती हो। इस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दोनों सदनों में आज तक किसी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर अखिलेश ने कहा कि किसी का अपमान नहीं हुआ और संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया।

हालांकि बाद में स्पीकर के समझाने पर आजम खां ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला हो जो सदन की कार्यवाही के लिए गलत हो तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इतना कहने के बाद आजम खां सदन छोड़कर चले गए। उनके जाने से पूर्व बसपा सांसद दानिश अली ने भी सदन से वाकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि बसपा सांसद के बोलने पर भी सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत अधिक टोकाटाकी हुई। यह गलत है।

एनसीडब्लू अध्यक्ष बोलीं, अयोग्य ठहराए जाएं आजम : आजम की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आजम खां को संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। वहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसी टिप्पणी के लिए आजम को जेल भेज दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आजम खां विवादित बयान देने के लिए पहले से ही काफी चर्चित हैं।

विदेश से लौटे राहुल, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक जल्द

नई दिल्ली, एएनआइ: कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी गुरुवार सुबह देश लौट आए हैं। उनके स्वदेश लौटने के साथ ही अब कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक जल्द होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक जल्द होने की संभावना है और इसकी तारीखों की घोषणा एक या दो दिनों में कर दी जाएगी। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रभारी (संगठन) केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अब सभी की निगाहें कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पर लगी हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में पार्टी के अगले अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनावों में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने कांग्रेस कार्यसमिति की 25 मई को होने वाली बैठक में अपने इस्तीफे का प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष का पद लगभग दो माह से रिक्त होने के बावजूद अब तक इस मुद्दे पर कार्यसमिति की बैठक ना होने को लेकर पार्टी की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। जब राहुल विदेश में थे तो पार्टी को एक बड़ा झटका तब लगा जब कर्नाटक में जदएस-कांग्रेस सरकार विश्वासमत साबित करने में विफल रही।

इशरत मामले में वंजारा व आमीन की रिहाई को चुनौती नहीं देगी सीबीआइ

अहमदाबाद, प्रेट्र : सीबीआइ ने गुरुवार को यहां एक कोर्ट को सूचित किया कि वह इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस आयुक्त डीजी वंजारा और एनके आमीन की रिहाई को चुनौती नहीं देगी। सीबीआइ के वकील आरसी कोडेकर ने यह जानकारी सीबीआइ के विशेष जज आरके चूड़ावाला को लिखित रूप में दी। इस मामले की अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।

राज्य सरकार द्वारा मुकदमे की कार्यवाही की अनुमति नहीं दिए जाने पर सीबीआइ कोर्ट ने दो मई को वंजारा और आमीन को रिहा कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 197 के तहत सरकारी सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि अब बाकी चार आरोपित- जीएल सिंघला, तरुण बारोट, अनाजु चौधरी और जेजी परमार रिहाई की मांग करते हुए सीबीआइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आइपीएस अधिकारी सिंघला फिलहाल गांधीनगर स्थित कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में आइजी हैं। राज्य आरक्षित पुलिस के कमांडो चौधरी भी इस समय सेवारत हैं, जबकि बारोट और परमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वंजारा और आमीन से भी पहले कोर्ट ने पूर्व आइपीएस अधिकारी पीपी पांडे को रिहा कर दिया था।

15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस ने मुंबई के करीब स्थित मुंब्रा निवासी इशरत जहां (19), जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई, अमजदअली अकबरअली राणा और जीशान जौहर को मार गिराया था।

पहल

अपने कार्यकाल के दूसरे साल में हर दिन औसतन 23 लोगों से मिले राष्ट्रपति कोविंद, इनमें सैनिक, किसान, वैज्ञानिक से लेकर शिक्षाविद तक शामिल

राष्ट्रपति भवन से राज्यों की दूरी घटाने पर कोविंद का जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियों की व्यस्तताओं के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन की राज्यों से दूरी घटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर चुके राष्ट्रपति कोविंद प्रति दिन औसतन 23 लोगों से मुलाकात करते हैं। राष्ट्रपति से रोजाना मिलने वाले लोगों में सैनिक, किसान, वैज्ञानिक से लेकर शिक्षाविद शामिल हैं।

संवैधानिक भूमिका के दायरे में राष्ट्रपति की सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक साल में (25 जुलाई 2018 से 24 जुलाई 2019 के बीच) रामनाथ कोविंद ने 8,448 लोगों से मुलाकात की। राज्यों के दौरे और राष्ट्रपति भवन में व्यक्तिगत या छोटे समूहों में इतनी संख्या में लोगों ने कोविंद से संवाद किया। 25 जुलाई 2017 को देश के राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद अपने दो साल के कार्यकाल में संवैधानिक जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ-साथ कोविंद ने राज्यों के दौरे को अपनी प्राथमिकता में शामिल रखा। राष्ट्रपति भवन और राज्यों के बीच दूरी घटाने के अपने नजरिये के तहत रामनाथ कोविंद ने बीते एक साल में 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की है। इसमें सबसे अधिक छह बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तरप्रदेश की तो तमिलनाडु की चार यात्राएं की। वहीं वैश्विक कूटनीति में भारत की प्रभावी भूमिका निभाने की पहल के तहत राष्ट्रपति कोविंद ने 10 देशों की यात्रा की और आस्ट्रेलिया, बोलिविया और क्रोशिया का राजकीय दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जबकि एक वर्ष के दौरान 19 अलग-अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों से राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय वार्ता की और छह राष्ट्राध्यक्षों की रायसीना हिल्स में मेजबानी भी की। शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के मामले में भी राष्ट्रपति ने तत्परता दिखाई है और बीते एक साल में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों के साथ तमाम राज्यों के हाईकोर्ट के 205 जजों की नियुक्ति की। इन संवैधानिक दायित्वों के साथ राष्ट्रपति कोविंद ने पर्यावरण संरक्षण की पहल को लेकर अपनी पहल को और गति देते हुए राष्ट्रपति भवन में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अब राष्ट्रपति भवन की बैठकों और समारोहों के दौरान प्लास्टिक बोतल की जगह शीशे के ग्लास में पानी दिए जाते हैं।

रामनाथ कोविंद फाइल फोटो

कारगिल के शहीदों को आज श्रद्धांजलि देंगे

राज्य ब्यूरो, जम्मू : शहीदों की कर्मभूमि कारगिल में शुक्रवार को राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कारगिल विजय के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समय द्रास वार मेमोरियल में बड़े पैमाने पर देशभक्ति के कार्यक्रम चल रहे हैं।

कारगिल विजय दिवस पर द्रास वार मेमोरियल में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति अपने दौरे से लद्दाख में चीन और पाकिस्तान से लगते इलाकों में दुर्गम हालात में देश सेवा कर रहे सैनिकों का उत्साह बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के सुबह कारगिल पहुंचने पर थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल बीएस धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह स्वागत करेंगे। इससे ठीक पहले वीरवार को जनरल बिपिन रावत द्रास पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार, तीनों सेनाओं के चीफ राष्ट्रपति को कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी भी देंगे। इस बीच, कारगिल पहुंचे आर्मी चीफ ने गुरुवार को द्रास का दौरा कर कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया।

रावत विजय मशाल को अमर जवान ज्योति में करेंगे समाहित : दिल्ली से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रज्ज्वलित कर द्रास के लिए रवाना की गई कारगिल विजय मशाल का भी थलसेना अध्यक्ष बिपिन रावत शुक्रवार को द्रास में स्वागत करेंगे। वह यह मशाल स्वीकार कर उसे द्रास वार मेमोरियल में अमर जवान ज्योति में समाहित करेंगे। विजय मशाल को चौदह जुलाई को दिल्ली से रवाना किया गया था।

कह के रहेंगे माधव जोशी

24 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब स्कूली बच्चे पहले नाश्ता करेंगे। इसके बाद पढ़ाई करेंगे। नाश्ते के एक घंटा बाद मध्याह्न भोजन दिया जाएगा।

जैसा नाम वैसा ही किया काम

हवलदार यश वीर सिंह तोमर

जन्म : 04 जनवरी, 1960 सिरसाली, उत्तर प्रदेश

शहीद हुए : 13 जून, 1999

यूनिट : 2 राजपूताना रायफल

शौर्य गाथा : कारगिल युद्ध के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने का निर्देश मिला। ग्रेनेडियर्स के कई विफल प्रयासों के बाद राजपूताना रायफल की दूसरी बटालियन को हमले के लिए आगे किया गया। ग्रेनेडियर्स ने तीन प्वाइंट से राजपूताना को कवर दिया। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में 90 सैनिक अंतिम हमले के लिए आगे बढ़े। इसी पलटन में यश वीर भी शामिल थे। यह पलटन प्वाइंट 4950 को अपने कब्जे में लेने के आखिरी चरण में

जरा याद करो कुर्बानी...

थी। 12 जून को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी के बीच जब भारतीय सैनिक एक एक कर शहीद हो रहे थे, तो हवलदार यश वीर सिंह ने ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानी बंकरों पर धावा बोला। उन्होंने बंकरों पर 18 ग्रेनेड फेंके और दुश्मनों को मार गिराया। उनके साहस को देखकर दुश्मनों के छक्के छूट गए। उनके पैर उखड़ने शुरू ही हुए थे कि इस दौरान वे गंभीर रूप से जख्मी हुए और शहीद हो गए। जब उनका शरीर मिला तो उसके एक हाथ में रायफल और दूसरे में ग्रेनेड थे। तोलोलिंग फतह करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

सपा-बसपा शासन की 23 सड़कों की होगी जांच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- प्रयागराज और प्रतापगढ़ में बनीं इन सड़कों की तलाशी जा रही फाइलें
- सबसे ज्यादा यमुनापार में हुआ था सड़कों का निर्माण, ज्यादातर खराब

सड़कों का ब्योरा मांगा

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग हिमांशु मित्तल ने बताया कि वर्ष 2004 से लेकर 2012 तक प्रयागराज और प्रतापगढ़ में बनाई गई सड़कों का ब्योरा मांगा गया है। जल्द ही पूरी सूचना एसआइटी को दे दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा और मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार में मंडल के दो जिलों प्रयागराज व प्रतापगढ़ में बनाई गई 23 बड़ी सड़कों की जांच कराई जाएगी। यह जांच विशेष जांच प्रकोष्ठ (एसआइटी) करेगा। सड़क की गुणवत्ता से लेकर टेंडर और फर्म के बारे में छानबीन कराई जाएगी। फिलहाल प्रकोष्ठ की मांग पर फाइलें खंगाली जा रही है।

वैसे तो पूर्ववर्ती सरकारों में मंडल में दो सौ से ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुंदरीकरण और मरम्मतीकरण किया गया था। इसके अलावा स्टेट और नेशनल हाईवे भी बनवाए गए थे। शासन के निर्देश पर प्रयागराज की 17 और प्रतापगढ़ की छह सड़कें जांच के लिए चिह्नित की गई हैं। इनमें प्रयागराज के यमुनापार में मांडा रोड से भारतगंज-कोरांव, नारीबारी होते हुए लालापुर तक स्टेट हाईवे, सिरसा से कोरांव, रामपुर से कोहड़ार घाट, कोहड़ार घाट से कोरांव, मेजा रोड से खीरी, पचदेवरा से गौहनिया आदि सड़कें बनाई गईं थीं। इसी तरह गंगापार में झूंसी के चक से छिबैया, जमुनीपुर होते हुए हनुमानगंज, सैदाबाद से असढ़िया, हंडिया से फूलपुर, हंडिया से धनूपुर, फूलपुर से सोरांव, फाफामऊ से सहसों होते हुए हनुमानगंज की सड़कें बनी थीं। इन सड़कों से संबंधित फाइलें विशेष जांच प्रकोष्ठ (एसआइटी) ने मांगी है। अफसर फाइलें तलाश करा रहे हैं।

बताते हैं कि इन सड़कों के निर्माण में करोड़ों रुपये का घपला हुआ था। सड़कों के निर्माण में ज्यादा धनराशि खर्च करने से लेकर गुणवत्ता की भी शिकायतें आई थीं। इनमें कई ऐसी सड़कें हैं जो कुछ समय में ही क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनकी दोबारा मरम्मत कराई गई।

कर्नाटक में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। जदएस-कांग्रेस गठबंधन के सभी बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिए जाने के कारण भाजपा फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश करने के मूड में नहीं है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता जी. मधुसूदन ने बताया, 'बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार या अस्वीकार करने में अगर स्पीकर ज्यादा समय लेते हैं तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करना चाहते।' उन्होंने आगे कहा, 'जब तक इस्तीफे स्वीकार नहीं हो जाते, विधानसभा की सदस्य संख्या 225 (मनोनीत समेत) बनी रहेगी और साधारण बहुमत का आंकड़ा 113 होगा। ऐसी स्थिति में दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बावजूद हमारे पास बहुमत से छह विधायक कम रहेंगे। अगर स्पीकर बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं तो विधानसभा की सदस्य संख्या घटकर 210 रह जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 106 होगा।'

इस बीच, राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में कोई भी स्थिर सरकार नहीं दे सकता। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्दरमैया ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्होंने ही बागी विधायकों को इस्तीफा देने के लिए उकसाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्दलीय विधायकों को याचिका वापस लेने की मंजूरी दी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश को उनकी याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी। याचिकाओं में राज्य विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार को कुमारस्वामी सरकार द्वारा पेश विश्वास मत पर 'तत्काल' शक्ति परीक्षण कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पीकर और कार्यवाहक मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलों पर गौर किया कि उन्हें याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

दो बागी कांग्रेस विधायक और एक निर्दलीय अयोग्य करार

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस के दो बागी विधायकों रमेश जर्किहोली व महेश कुमाताहल्ली और एक निर्दलीय विधायक आर. शंकर को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दे दिया। तीनों विधायक विधानसभा के शेष कार्यकाल यानी 2023 तक सदन की सदस्यता के अयोग्य रहेंगे। स्पीकर ने कहा कि वह शेष 14 मामलों में भी दो दिनों में फैसला ले लेंगे। स्पीकर ने कहा कि वह इस बात से आश्वस्त हैं कि उपरोक्त तीनों सदस्यों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे। उन्होंने बताया, 'उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसीलिए उन्हें अयोग्य ठहराया गया है।' आर. शंकर के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने उन्हें बताया था कि शंकर की पार्टी केपीजेपी का कांग्रेस में विलय हो गया था और उसके बाद ही उन्हें मंत्री बनाया गया था। लिहाजा वह कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य थे।

मकोका पर भाजपा व कांग्रेस शासित राज्यों के दिखे अलग-अलग सुर

सख्त रुख ▶ नशे की समस्या पर अंतरराज्यीय कांफ्रेंस में सात राज्य राष्ट्रीय नीति बनाने पर सहमत

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मकोका जैसे कानून के पक्ष में, पंजाब को कानून के दुरुपयोग की आशंका

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

नशे से निपटने के लिए चंडीगढ़ में आयोजित अंतरराज्यीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिभुवन सिंह रावत (बाएं से दाएं)। प्रेट्र

नशे की समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की तर्ज पर कानून बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुर गुरुवार को अलग-अलग रहे। भाजपा शासित हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इस तरह के कानून के हक में दिखे तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसे कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधे रखी।

नशे की समस्या पर पंजाब की मेजबानी में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई दूसरी अंतरराज्यीय कांफ्रेंस में सात राज्य राष्ट्रीय नीति बनाने पर सहमत हुए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली व जम्मू-कश्मीर के अधिकारी नशे की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति पर पंजाब के साथ खड़े नजर आए। मकोका जैसे कानून पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हकोका और मकोका की तर्ज पर कानून संबंधी विचार कर रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने संगठित अपराध रोकने को हकोका (हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) बनाने के लिए सभी रास्ते साफ कर लिए हैं। 2 अगस्त को शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं, अलबत्ता राष्ट्रीय नीति का समर्थन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मकोका का विरोध नहीं किया, वे चुप रहे। उन्होंने जागरुकता पर विशेष जोर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मौजूदा कानून एनडीपीएस एक्ट को ही और मजबूत करने की बात की। उन्होंने मकोका जैसे कानून में सावधानी बरतने पर जोर देते हुए आशंका जताई कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग हो सकता है।

ठाकुर बोले-हिमाचल में नशा तस्करी करने वाले 40 फीसद पंजाबी : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करी करने वाले जितने भी युवा पकड़े जाते हैं उनमें 40 फीसद पंजाब से हैं, जबकि 26 फीसद हरियाणा के हैं। हिमाचल के युवा केवल दो फीसद हैं।

गहलोत ने कहा-राजस्थान में अफीम की खेती सरकारी नियंत्रण में : कैप्टन अमरिंदर ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से राज्य में अफीम की खेती पर पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सीमा से पंजाब में भारी मात्रा में अफीम की तस्करी हो रही है। इस पर गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अफीम की खेती सरकारी कंट्रोल में है और जितनी भी उपज होती है वह सारी सरकार खरीदती है। इसलिए वहां से तस्करी नहीं हो सकती।

अपनी कमजोर कड़ियों पर कांग्रेस की निगाह

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में बदले राजनीतिक हालात के बाद भाजपा की ओर से होने वाले संभावित पलटवार से कमलनाथ सरकार आशंकित है। यही वजह है कि वह सतर्क भी हो गई है। हार्स ट्रेडिंग से विधायकों को बचाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी के बाद कांग्रेस ने अपनी कमजोर कड़ियों की निगरानी बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कांग्रेस और भाजपा में सियासी प्रबंधन के रणनीतिकार भोपाल से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं। विधायक दल की कमजोर कड़ियों को चिह्नित कर फोकस किया जा रहा है। निजी चर्चा में भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी और ब्यौहारी विधायक शरद कोल का असंतोष वह समझ नहीं पाए और धीरे-धीरे वह कांग्रेस के पाले में चले गए, लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों विधायकों द्वारा कमलनाथ सरकार को समर्थन देने का एलान करने से फिलहाल दलबदल जैसी कोई स्थिति नहीं है। उधर, पाला बदलने के बाद सरकार ने दोनों विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

कांग्रेस का दावा-भाजपा के पांच विधायक और संपर्क में : कांग्रेस संगठन के दिग्गज नेता और मंत्रिगण गुरुवार को यह दावा करते रहे कि विधानसभा में मत विभाजन के जरिये हुआ फ्लोर टेस्ट (दो विधायकों की टूट) तो ट्रेलर मात्र है, अभी भाजपा के पांच अन्य विधायक भी उनके लगातार संपर्क में हैं। हालांकि, सतर्कता का माहौल कांग्रेस में भी है। निर्दलीयों के अलावा पार्टी के कुछ असंतुष्ट विधायकों पर नजर रखी जा रही है।

कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद ही मप्र में कांग्रेस सरकार को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई थी। भाजपा नेता कहते रहे हैं कि कर्नाटक से चली हवा अब मप्र तक पहुंचेगी। दो विधायकों के टूटने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भी एलान किया था कि खेल कांग्रेस ने शुरू किया खत्म हम करेंगे। कांग्रेस की घबराहट का कारण दरअसल नरोत्तम मिश्रा का यह बयान भी है। पार्टी नेता मान कर चल रहे हैं कि भाजपा चुप नहीं बैठेगी। कुछ न कुछ जरूर करेगी।

ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे कमलनाथ जिससे भाजपा नेतृत्व से टकराव दिखे

नईदुनिया, भोपाल

कमलनाथ फाइल फोटो

मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के दो विधायकों को अपने पाले में लाने के बावजूद मुख्यमंत्री कमलनाथ फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। वे अपने एक्शन, बयान और हाव-भाव से ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहते, जिससे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से टकराव दिखाई दे। एक दिन पहले सदन में उन्होंने भाजपा के एक नंबर और दो नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर बेहद संतुलित जवाब दिया और गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से यह संदेश दिया कि इतना सब होने के बावजूद वे प्रदेश को दलगत राजनीति में नहीं बांटना चाहते।

कमलनाथ ने ट्वीट किया कि हम प्रदेश को विकास की दृष्टि से देश में शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं। प्रदेश हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम प्रदेश को दलगत राजनीति में बांटना नहीं चाहते हैं। हम विपक्ष से भी शुरू से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में हमें सहयोग करे। हमें जनादेश मिला है। विपक्ष उसका सम्मान करे। हम अभी भी विपक्ष से प्रदेश हित में प्रदेश के विकास के लिए सहयोग की उम्मीद व अपेक्षा करते हैं। भाजपा इसे कमलनाथ का भय मानती है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि बुधवार का घटनाक्रम और गुरुवार का उनका ट्वीट यह बताता है कि वे कितनी घबराहट में हैं। उधर, प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनके मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा कहते हैं कि भाजपा के दो विधायकों को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए मुख्यमंत्री ने न तो प्रलोभन दिया और न ही कोई वादा किया। वे भाजपा में दुखी थे, इसलिए कांग्रेस के साथ हो लिए।

वहीं, भाजपा मप्र विधानसभा में हुए घटनाक्रम से बेहद नाराज है। बागी विधायकों के खिलाफ पार्टी अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लेकिन परोक्ष रूप से उन्हें चेतावनी दे दी है कि वे बिना भाजपा के चुनाव जीतकर दिखा दें। कांग्रेस के संपर्क वाले दूसरे विधायकों को भी पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर भाजपा से दगा करने की गलती उन्होंने की तो मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें।

अब गाय के ऑक्सीजन छोड़ने के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासत

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट द्वारा नदी के पत्थर द्वारा आसान प्रसव को लेकर दिए गए बयान पर मचा घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ है। वहीं, अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेने के साथ ही ऑक्सीजन छोड़ती भी है। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि गाय के संपर्क में रहने से टीबी जैसे रोग दूर हो जाते हैं।

गुरुवार को सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री यह कहते दिख रहे हैं कि पीपल का पेड़ प्राणवायु छोड़ता है। ऐसे ही पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है तो ऑक्सीजन छोड़ता है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो गाय की मालिश करने से यह तकलीफ दूर हो जाती है। टीबी जैसी बीमारी भी गाय के संपर्क में आने से दूर हो जाती है। गाय के गोबर और गौमूत्र में काफी ताकत है। शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे स्किन, हार्ट और किडनी आदि के लिए ये काफी फायदेमंद हैं।

सोशल मीडिया में इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालयों की मानें तो यह वीडियो तकरीबन पांच माह पुराना है और इसे जानबूझ कर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जो कहा गया है वह प्रदेश में अभी तक चल रही मान्यताओं के आधार पर ही कहा गया है। इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में भी विपक्षी विधायक कांग्रेस के संपर्क में

नईदुनिया, रायपुर: मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने भाजपा खेमे में हलचल बढ़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दावा किया है कि दो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जकांछ) के कई विधायक कांग्रेस के आला-नेताओं के लगातार संपर्क में हैं।

त्रिवेदी का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कामकाज से विपक्षी दलों के कई विधायक प्रभावित हैं। इस कारण वह कांग्रेस में आने की इच्छा जता रहे हैं। भाजपा और जकांछ के ऐसे विधायकों का स्वागत है, लेकिन उनके कांग्रेस में प्रवेश पर पार्टी नेतृत्व को फैसला लेना है। वैसे उन्होंने यह भी कहा कि 90 सदस्यीय विधानसभा में 68 विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस सरकार को दूसरे दल के विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं है।

आप में बगावत, जयहिंद पर ब्राह्मणवाद फैलाने के आरोप, बागियों को पार्टी से निकाला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंचकूला व सोनीपत के नेताओं ने खोला नवीन जयहिंद के खिलाफ मोर्चा, दबंगई के आरोप जड़े

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पंडित नवीन जयहिंद के खिलाफ कुछ पदाधिकारियों ने बगावत का झंडा उठा लिया। उन पर ब्राह्मणवाद फैलाने और दबंगई दिखाने के आरोप लगाए गए हैं। फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव जयहिंद ने अपने नाम के आगे पंडित शब्द लगाकर लड़ा था। जयहिंद का यह फैसला पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को नागवार गुजरा और उन्होंने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए।

आप के अंबाला लोकसभा सीट के प्रभारी व पंचकूला के अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा समेत कुछ पदाधिकारियों ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवीन जयहिंद की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इन पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी नाराजगी न तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से है और न ही हरियाणा मामलों के प्रभारी गोपाल राय और सह प्रभारी सुशील गुप्ता से है, लेकिन नवीन जयहिंद को लेकर नाराजगी है।

उन्होंने कहा कि खुद की जाति हिंदुस्तान का नारा देने वाले नवीन जयहिंद ने लोकसभा चुनावों के दौरान पंडित नवीन जयहिंद लिखना शुरू कर जातिवाद को बढ़ावा दिया। यह सारी बातें पार्टी आलाकमान को पहुंचाई गई थीं, मगर हाईकमान ने कुछ नहीं किया। राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि समस्या केवल संवाद की कमी की है और नवीन जयहिंद के साथ मतभेद गंभीर प्रकृति में नहीं आते।

नवीन जयहिंद ने अपने विरुद्ध योगेश्वर शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी के प्रति बगावत व अनुशासनहीनता माना है। आप की हरियाणा इकाई के सह संगठन मंत्री अजय गौतम ने बताया कि अनुशासनहीनता के कारण पंचकूला के योगेश्वर शर्मा और सोनीपत के अनिल तुषीर को पार्टी से निकाल दिया गया है। दोनों ही पिछले कई माह से पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे थे। उन्हें कई बार चेतावनी दी गई, मगर उन्होंने अपनी आदत में सुधार नहीं किया। अजय गौतम के अनुसार अनिल तुषीर को पहले भी निष्कासित किया गया था, लेकिन व्यवहार में सुधार का भरोसा दिलाने पर उन्हें बहाल कर दिया गया था। अब फिर अनिल तुषीर और योगेश्वर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रति खुली बगावत की है, जिस कारण दोनों को निकाल दिया गया है।

डैमेज कंट्रोल की कवायद

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

ब्यौहारी विधायक शरद कोल और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के पाला बदलने पर पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह को भोपाल भेजा। उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की पर उन्हें आंशिक सफलता भी नहीं मिली। इस दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी प्रदेश कार्यालय में दिग्गजों के साथ सक्रिय रहे।

भाजपा में सब कुछ सामान्य होने का दावा : भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है। तनाव में कांग्रेस है और वह जबरिया अपनी ताकत दिखाने के लिए उल्टे-सीधे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो पहले सरकार गिराने के पक्ष में थी और न उसका ऐसा कोई इरादा है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है।

दो टूक

शीर्ष अदालत में तुरंत सुनवाई के मुकदमों के सूचीबद्ध नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई

कोर्ट की रजिस्ट्री में कुछ बुनियादी गड़बड़ी है : सीजेआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। तुरंत सुनवाई के मुकदमों के सूचीबद्ध नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सीजेआइ ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री में 'बुनियादी रूप से कुछ गड़बड़ी है।'

मुख्य न्यायाधीश गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि रोजाना ऐसे वकीलों की लंबी कतार लगी होती है जो चाहते हैं कि उनका मामला सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे कार्यसूची से हटा दिया गया है। तीन अक्टूबर, 2018 को देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालने के दिन से न्यायमूर्ति गोगोई ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वकीलों को शीघ्र सुनवाई के लिए अपने मामले का उल्लेख नहीं करना पड़े और उनके मुकदमे एक निश्चित अवधि के भीतर अपने आप सूचीबद्ध हो जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'रोजाना मामले सूचीबद्ध कराने के लिए वकीलों की लंबी कतार लगी रहती है। निश्चित ही इसमें (रजिस्ट्री) कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। सर्वश्रेष्ठ

रंजन गोगोई फाइल फोटो

प्रयासों के बावजूद, मैं इससे (मामले सूचीबद्ध कराने) निबटने में असमर्थ हूं।'

मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस समय की जब एक वकील ने अपने एक मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे कार्यसूची से निकाल दिया गया है। पीठ ने इसके बाद इस तथ्य का उल्लेख किया कि हाई कोर्ट में एक सप्ताह में करीब छह हजार नए मामले दायरे होते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस अवधि में करीब एक हजार मामले दायर होते हैं लेकिन इसके बाद भी शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री प्रभावी तरीके से इनका निबटारा करने में असमर्थ है।

कोलेजियम नहीं, न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे चिंता का विषय : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली कोलेजियम की कार्यशैली नहीं बल्कि निचली अदालतों में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों के पदों की रिक्तियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे न्यायपालिका के लिए चिंता का विषय है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने देश में बच्चों से दुष्कर्म मामलों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि से संबंधित मामले पर विचार के दौरान अपनी नाराजगी जताई और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से दूर के स्थानों पर न्यायिक अधिकारियों को बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।

पीठ ने सवाल किया, 'त्रिपुरा, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वास्तविकता क्या है? मध्य प्रदेश जैसे राज्य अभी भी आरोपी और पीड़ित के बीच कोर्ट में एक पर्दा डालकर काम करने में यकीन करते हैं।' पीठ ने कहा, 'साकेत की अदालत में आपके पास गवाह के लिए कक्ष हो सकता है, लेकिन हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां ये सुविधाएं नहीं हैं। हमारे यहां ऐसे स्थान भी हैं जहां मजिस्ट्रेट चार फुट के कमरे में बैठते हैं। हमने यह देखा है और अदालतों की यही हकीकत है।' शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में न्यायिक अधिकारियों के पांच हजार से अधिक पद रिक्त हैं और विधायिका एक के बाद दूसरा नया कानून बना रही है। न्यायाधीश पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है और तमाम कानूनों में प्रावधान किया जाता है कि इससे संबंधित मामलों में छह महीने या एक साल के भीतर निर्णय हो।

पीठ ने कहा, 'कोई भी न्यायिक सुविधाओं और संरचनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो न्यायपालिका के लिए अधिक चिंताजनक हैं न कि कोलेजियम।'

भाजपा ने मिजोरम में बनाया क्रिश्चियन मिशनरी सेल

आइजल, आइएएनएस : ईसाई बहुल मिजोरम में कमल खिलाने की तैयारी के मद्देनजर पार्टी ने पहली बार राज्य में क्रिश्चियन मिशनरी सेल की स्थापना की है। बुधवार से इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई। राज्य की 40 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी का एकमात्र विधायक है। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या 1,091,014 है। कुल आबादी के 87 फीसद लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं।

भाजपा की मिजोरम इकाई के अध्यक्ष जेवी लूना ने कहा कि पांच सदस्यीय इस सेल का प्रमुख हरीथेरेंगा छांगटे को बनाया गया है जबकि जूली वनपारी को इसका सचिव बनाया गया है। छांगटे ने कहा कि सेल की स्थापना राजनीतिक दलों और चर्च के उस आरोप के खिलाफ की गई है, जिसमें वह भाजपा को ईसाई विरोधी बताते हैं। खनन इंजीनियर से राजनेता बने 54 वर्षीय छांगटे ने कहा कि शुरू में हम मिजो लोगों के बीच सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत करेंगे और धीरे-धीरे इसका विस्तार करेंगे।

- ईसाई बहुल राज्य में कमल खिलाने की तैयारी में पार्टी

छांगटे ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि अध्ययन, नौकरी और चिकित्सा उपचार के लिए जब मिजो लोग अन्य राज्यों में जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। यह सेल इस तरह की शिकायतों को दूर करने में मदद करेगा। सेल की 24 घंटे की एक हेल्पलाइन भी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरी के दौरान मैंने गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, असम सहित देश के कई हिस्सों में काम किया है। कुल मिलाकर मेरा निष्कर्ष यह है कि भाजपा सबसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मिजोरम में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़े छांगटे ने कहा कि यह झूठ कांग्रेस ने फैलाया है कि भाजपा ईसाई विरोधी है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि पार्टी सत्ता में आए। बता दें कि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट भाजपा नीत नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस का एक घटक है, लेकिन दोनों पार्टियों ने विस और लोस चुनाव अलग-अलग लड़े थे।

39 फीसद कम बारिश हुई है उत्तराखंड में। सात जिलों में औसतन 45 फीसद कम बारिश दर्ज की गई है। पौड़ी में यह आंकड़ा सबसे अधिक 61 रहा। ऊधमसिंहनगर इकलौता ऐसा जिला है जहां सामान्य से चार फीसद अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई।

दुश्मन की मौत बन मंडराए

स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा

जन्म : 22 मई, 1963 कोटा, राजस्थान
शहीद हुए : 27 मई 1999
यूनिट : गोल्डन ऐरोज, स्क्वाड्रन नंबर 17

शौर्य गाथा : नेशनल डिफेंस एकेडमी से पासआउट होने के बाद 14 जून, 1985 को फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायु सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा के इस तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर लांच किया गया। इसमें शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के मिग-27एल विमान के इंजन में आग लगने के बाद वह उसमें से बाहर कूदे। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा अपने मिग-21एमएफ विमान में दुश्मन की पोजीशन के ऊपर उड़ान भरते

जरा याद करो कुर्बानी...

रहे ताकि बचाव दल को नचिकेता की लोकेशन की जानकारी देते रहें। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दुश्मन कभी भी उन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दाग सकता है। हुआ भी ऐसा ही, कुछ ही देर में उनके विमान पर एमआइएम-92 स्ट्रिंगर से वार हुआ। वे अपने विमान से बाहर कूदे। अब वायु सेना को एक नहीं दो बचाव अभियानों को अंजाम देना था। लेकिन वायु सेना को उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिली। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। उनके पार्थिव शरीर पर कई गंभीर घावों के निशान दिखे। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ शिवसेना के हुए सचिन अहीर

राज्य ब्यूरो, मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मुंबई अध्यक्ष सचिन अहीर गुरुवार को शिवसेना में शामिल हो गए। अपने समर्थकों के साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर उनकी उपस्थिति में ही अहीर ने शिवसेना में प्रवेश किया।

सचिन अहीर की पहचान मिल मजदूर नेता की रही है। वह मुंबई के वरली क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव शिवसेना के सुनील शिंदे से हार गए थे। इस बार भी शिवसेना-भाजपा गठबंधन की संभावना को देखते हुए उनकी जीत की उम्मीद कम ही थी, इसलिए अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना का दामन थामने का निर्णय किया। संभावना है कि अगला विधानसभा चुनाव वह शिवसेना के टिकट पर भायखला क्षेत्र से लड़ेंगे। यह सीट पिछली बार एआइएमआइएम के खाते में गई थी और पार्टी के वारिस पठान यहां से विधायक हैं। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सचिन अहीर की कलाई पर शिवबंधन बांधकर उन्हें शिवसेना में शामिल किया।

माफिया सरगना अरुण गवली के भांजे हैं अहीर : सचिन के आने से खासतौर पर मध्य एवं दक्षिण मुंबई में जहां शिवसेना की ताकत बढ़ेगी, वहीं शरद पवार की राकांपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगेगा। सचिन अहीर स्वयं तो जनाधार वाले नेता हैं ही, वह रिश्ते में भायखला क्षेत्र में ही प्रभाव रखनेवाले माफिया सरगना अरुण गवली के भांजे भी हैं। गवली फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके प्रभाव का लाभ सचिन को मिलने से इन्कार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर राकांपा मुंबई में पहले से कमजोर रही है। मुंबई की छह लोकसभा सीटों में वह सिर्फ एक उत्तर-पूर्व मुंबई की सीट पर ही चुनाव लड़ती है। उसे भी शिवसेना की तरह सिर्फ मराठी जनाधार वाली पार्टी माना जाता है, जबकि कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों का जनाधार बहुभाषी है। उद्धव ठाकरे ने कहा, 'शिवसेना लोगों के दिलों को जीतने की राजनीति करती है। सचिन अहीर अपनी इच्छा और खुशी के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। अहीर ने कहा कि शरद पवार उनके दिल में रहेंगे, लेकिन आदित्य व उद्धव ठाकरे को अपने शरीर की ताकत बनाते हुए शिवसेना का विस्तार करेंगे।

सचिन के शिवसेना में जाने पर राकांपा की ओर से तीखी व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट किया- 'जो जिंदा होते हैं वह प्रवाह के विरुद्ध तैरते हैं, मुर्दा लोग पानी के साथ बह जाते हैं। साथियों, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद।'

गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रांत के अध्यक्ष सचिन अहीर शिवसेना में शामिल हो गए। इस दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। एएनआइ

भुजबल ने शिवसेना में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज

नासिक, प्रेट्र : वरिष्ठ राकांपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल ने गुरुवार को मीडिया की उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिसमें विधानसभा चुनाव से पूर्व उनके शिवसेना में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी। एक कार्यक्रम से इतर यहां मीडिया को संबोधित करते हुए भुजबल ने कहा कि इन रिपोर्ट में कोई दम नहीं है।

समुद्री हवाई क्षेत्रों पर उड़ने वाले विमानों की हो सकेगी सटीक निगरानी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) जल्द ही भारतीय हवाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महासागरों पर उड़ान भरने वाले विमानों की सटीक निगरानी शुरू करेगा। इसके लिए एक नई प्रणाली को तैनात किया जाएगा। वर्तमान में अंतरिक्ष आधारित ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्राडकास्ट (एडीएस-बी) डाटा सर्विसेज का प्रयोग होता है। यह हवाई क्षेत्र के साथ ही महासागरीय क्षेत्र की बहुत सीमित निगरानी कर सकता है।

गुरुवार को प्राधिकरण ने 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के समुद्री हवाई क्षेत्रों की अंतरिक्ष आधारित हवाई यातायात निगरानी के लिए एरोन एलएलसी से समझौता किया। वर्ष के अंत तक इस प्रणाली को तैनात किए जाने की उम्मीद है।

प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस प्रणाली के उपयोग से दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत, मध्य-पूर्व और यूरोप के बीच के व्यस्त मार्गों पर हवाई यातायात की सटीक निगरानी की दक्षता को बढ़ाएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष गुरुप्रसाद महापात्र ने कहा कि एएआइ इस तकनीक को लागू करने वाला क्षेत्र का पहला एयर नेवीगेशन सेवा प्रदाता होगा।

न्यूज गैलरी

विभिन्न हाई कोर्ट में जजों के लिए 20 नामों की सिफारिश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 20 नामों की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्तावों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने कुल 35 नामों पर विचार किया और 20 की सिफारिश की। कोलेजियम ने जयतोष मजूमदार, अमितेश बनर्जी, राजा बसु चौधरी, लापिता बनर्जी और शाक्य सेन को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की सिफारिश की है। इसके अलावा कौशिक चंदा के नाम की भी सिफारिश की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए महेंद्र गोयल और फरजंद अली के नामों की सिफारिश की गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जसगुरप्रीत सिंह पुरी, सुवीर सहगल, गिरीश अग्निहोत्री, अलका सरीन और कमल सहगल के नामों की सिफारिश की गई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आर रघुनंदन राव, बद्दू देवानंद, डी रमेश और एन जयसूर्या के नामों की सिफारिश की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए टी विनोद कुमार, ए अभिषेक रेड्डी और के लक्ष्मण के नामों की सिफारिश की गई है। (प्रेट्र)

प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर थाने का दीवान निलंबित

कानपुर : कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर छेड़छाड़ पीड़िता से अमर्यादित भाषा बोलने वाले कानपुर स्थित नजीराबाद थाने के दीवान को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। प्रियंका के ट्वीट में कानून के रखवालों पर सवाल उठाए जाने के बाद मामले में विभागीय जांच बैठा दी गई थी। पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। नजीराबाद के सरोजनीनगर में 21 जुलाई को दो पक्षों में मारपीट के दौरान एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस पर दीवान तारबाबू ने युवती के पहनावे को लेकर सवाल खड़े कर अभद्रता की थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो महकमे में खलबली मच गई। इस मामले में आरोपित दीवान को निलंबित कर दिया गया है। (जासं)

जनमत

मुद्दा

क्या जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहां वे भी अल्पसंख्यकों की सहूलियतों-सुविधाओं के हकदार हैं?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

हुड्डा पर कसा ईडी का शिकंजा

बढ़ीं मुश्किलें ▶ मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में हुई पूछताछ, लंच करने की मिली छूट

करीब दस घंटे की पूछताछ के बाद रात नौ बजे लौटे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं पर शिकंजा कस गया है। हिसार के पूर्व सांसद एवं आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब दस घंटे पूछताछ की। हुड्डा चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे पहुंचे और रात को नौ बजे लौटे।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 10 घंटे की पूछताछ में हुड्डा को दोपहर करीब ढाई से तीन बजे लंच करने की अनुमति दी। इसके लिए वह अपने सरकारी फ्लैट पर आए और दस मिनट आराम करने के बाद वापस प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में चले गए। उनके समर्थक और विधायकों का ईडी कार्यालय और सरकारी आवास पर आना-जाना लगा रहा।

सूत्रों के अनुसार हुड्डा से ईडी ने मानेसर जमीन घोटाले में पूछताछ की है। उनसे जमीन अधिग्रहण से लेकर उसे रिलीज किए जाने से जुड़े करीब 150 सवालों के जवाब पूछे गए। हुड्डा ने ईडी अधिकारियों को जानकारी दी है कि गुरुग्राम के तत्कालीन सांसद के प्रस्ताव पर ही जमीन के अधिग्रहण और रिलीज की कार्रवाई को अमल में लाया गया था। हुड्डा से शुक्रवार को भी पूछताछ हो सकती है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल फोटो

एजेएल प्लाट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआइ की विशेष अदालत में हुड्डा की शुक्रवार को पेशी है। खबर लिखे जाने तक हुड्डा ईडी की जांच से वापस नहीं लौटे थे। समर्थक देर रात तक सरकारी फ्लैट पर उनका इंतजार करते रहे। हुड्डा को उम्मीद थी कि पूछताछ जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उन्हें कई निजी समारोह में शामिल होना था, लेकिन सारा प्रोग्राम धरा रह गया।

क्या है मानेसर जमीन घोटाला : मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआइ ने हुड्डा सहित 34 अन्य के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने सरकार में उच्च स्तर पर बैठे लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गावों के किसानों और भूस्वामियों से अधिग्रहण के नाम पर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी। कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डरों को बेचा गया। हालांकि कांग्रेस लगातार सीबीआइ और ईडी की कार्रवाई को सियासी रंजिश का नाम देती आ रही है।

हुड्डा के विरुद्ध चल रही विभिन्न जांच

पंचकूला में इंडस्ट्रीयल प्लॉट आवंटन

2013 में 14 लोगों को प्लॉट आवंटित। हुड्डा, एक आइएएस, एक रिटायर्ड अफसर और प्लॉटधारकों समेत 17 लोगों पर एफआइआर। विजिलेंस जांच में दोषी। हुड्डा और उनके समर्थकों पर एक साथ 20 स्थानों पर सीबीआइ की छापेमारी।

गुरुग्राम के मानेसर में जमीन अधिग्रहण मामला

भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में टाउनशिप के लिए 912 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई

वर्ष 2004 से 2007 के बीच 400 एकड़ भूमि खरीद में धांधली का आरोप। दिल्ली और हरियाणा में हुड्डा और उनके साथियों के दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। किसानों और भू-मालिकों का करीब 1500 करोड़ के नुकसान का दावा। इस मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया।

पंचकूला का एजेएल प्लॉट आवंटन मामला

नेशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व वाली कंपनी को प्लॉट का रि-अलॉटमेंट - 2016 में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच में दोषी ठहराए जाने के बाद सीबीआइ जांच की सिफारिश। अब ईडी को मिली केस चलाने की इजाजत।

गेहूं में करनाल बंट नामक बीमारी की रोकथाम के लिए रैक्सील दवा घोटाला

आइएएस अधिकारी अशोक खेमका ने यह मामला उठाया था। केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो से जांच कराने का निर्णय। हाई कोर्ट में भी चल रही कार्रवाई।

वाड्रा व डीएलएफ कंपनियों को गुरुग्राम में जमीनों के लाइसेंस का मामला

मामले की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 2016 से हाई कोर्ट में चल रहा है केस।

कोर्ट से इंदिरा जयसिंह और ग्रोवर को मिली बड़ी राहत

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआइ को इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर सहित इनके एनजीओ लायर्स कलेक्टिव के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने ग्रोवर और लायर्स कलेक्टिव के खिलाफ विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था।

याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सीबीआइ द्वारा एनजीओ और ग्रोवर के खिलाफ जून में दर्ज की गई एफआइआर को खारिज करने की मांग की। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने एफसीआरए उल्लंघन के सभी आरोपों का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि प्राथमिकी और गृह मंत्रालय की शिकायत सत्ता के दुरुपयोग के बेहतरीन उदाहरण हैं। दरअसल, एफसीआरए प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआइ ने मई में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में इंदिरा जयसिंह का नाम बतौर आरोपी शामिल नहीं किया गया था। सीबीआइ ने आरोप लगाया कि एनजीओ को 2009 से 2015 के बीच विदेशी फंड मिला, लेकिन वह इसका स्रोत बताने में असफल रहा।

सीबीआइ के वकील और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह ने विदेशी फंड का प्रयोग अपने निजी हितों के लिए किया। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय की शिकायत के मुताबिक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहने के दौरान भी इंदिरा जयसिंह ने एनजीओ से पारिश्रमिक लेना जारी रखा। यह पैसा वास्तव में एनजीओ को मिले विदेशी फंड का ही हिस्सा था। इसका विरोध करते हुए चिनॉय ने कहा कि एनजीओ को मिलने वाले जिस कथित अज्ञात विदेशी धन की बात कही जा रही है वह दान या अनुदान नहीं था, बल्कि एक विशेष कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक था और यह धन एफसीआरए अधिनियम के तहत नहीं आता है। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि इंदिरा जयसिंह ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहते हुए लायर्स कलेक्टिव से पारिश्रमिक लेने की कानून मंत्रालय से अनुमति ले ली थी।

19 अगस्त तक केंद्रीय जांच ब्यूरो नहीं कर सकेगी किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई

बांबे हाई कोर्ट फाइल फोटो

चुनावी प्रक्रिया में सुधार को ममता ने मोदी को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, कोलकाता :

- लोकसभा चुनाव में बेतहाशा चुनावी खर्च पर बंगाल की सीएम ने जताई चिंता
- सर्वदलीय बैठक बुलाने, बढ़ते भ्रष्टाचार व अपराधीकरण की प्रवृत्तियों की ओर भी दिलाया ध्यान

बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पिछले लोकसभा चुनाव में बेतहाशा चुनावी खर्च पर चिंता जताई है। पत्र में उन्होंने कहा है कि भारत में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए तत्काल चुनावी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। उन्होंने इसे लेकर प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी सलाह दी है। राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की प्रवृत्तियों की ओर भी पीएम का ध्यान आकृष्ट किया है।

अपने पत्र में ममता ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्च को लेकर जारी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव था। 2019 में हुआ चुनावी खर्च 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए कुल खर्च का दोगुना है। रिपोर्ट के हवाले से ममता ने बताया कि हालिया चुनाव में कम से कम 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस खर्च की ऊपरी सीमा अभी भी अज्ञात है और यह और भी ज्यादा हो सकती है।

तृणमूल अध्यक्ष ने चुनाव में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए पीएम से चुनावी पब्लिक फंडिंग के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि यह बैठक भारत में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बुलाई जाए। अंत में ममता ने इस बात पर जोर दिया कि हमें तत्काल चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, जिसमें चुनाव के लिए सरकारी फंडिंग की व्यवस्था शामिल है।

बिश्नोई के घर तीसरे दिन भी जारी रहा आयकर सर्वे

जागरण संवाददाता, हिसार

- घर में नजरबंद मां जसमा की तबीयत अचानक बिगड़ी
- चिंतित समर्थकों ने अस्पताल ले जाने को कहा, पुलिस का इन्कार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई के यहां सेक्टर-15 स्थित आवास पर आयकर विभाग की जांच गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। दोपहर में कुलदीप की मां जसमा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका रक्तचाप बढ़ने पर टीम ने तुरंत बाहर खड़े समर्थकों से दवा मंगवाई। इस दौरान समर्थकों ने दवा देने के साथ डॉक्टर से इलाज कराने की मांग की, मगर टीम ने मनाकर दिया। कहा कि अभी सिर्फ दवा की जरूरत है। जसमा देवी की उम्र 72 साल है और लंबे समय से उच्च रक्तचाप की मरीज हैं। वहीं तीसरे दिन भी जसमा देवी और कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को घर में ही नजरबंद रहना पड़ा। दोनों के फोन भी तीन दिन से बंद हैं और अधिकारियों की जांच जारी है।

नहीं जाने दिया अंदर : पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर के सामने की सड़क को पूर्ण रूप से बंद कर रखा है। सड़क पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। गेट की तरफ कोई नहीं जा सकता। यहां तक की घर के अंदर न तो कोई बाहर आ रहा न ही अंदर जा रहा है। इस कारण अंदर की कोई बात भी बाहर नहीं आई है।

यूं शुरू हुई थी कार्रवाई

आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह साढ़े सात बजे सेक्टर-15 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर सर्वे शुरू किया था। उस समय जसमा देवी, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को टीम ने घर में बुला लिया था। भव्य बिश्नोई को आदमपुर की दुकान के ऊपर बने घर पर ही टीम ने रोक लिया था। टीम आदमपुर में जांच करने के बाद मंगलवार रात 11 बजकर पांच मिनट पर भव्य बिश्नोई को हिसार स्थित आवास पर लेकर आई थी। उसके बाद से वह किसी को दिखाई नहीं दिए हैं।

राकांपा विधायक के घर और कारखाने पर आयकर छापे

राज्य ब्यूरो, मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक एवं पूर्व मंत्री हसन मुश्रिफ के विभिन्न ठिकानों पर गुरुवार को आयकर विभाग ने छापामारी की। यह छापामारी कोल्हापुर जिले में विधायक के आवास और चीनी मिल पर की जा रही है। चीनी मिल के अकाउंट बुक में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। राकांपा ने सरकार पर विपक्ष को परेशान करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

हसन मुश्रिफ राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के करीबी हैं। कई चीनी मिलों का नियंत्रण उनके हाथ में है। वह कोल्हापुर की कागल विधानसभा सीट से विधायक हैं। पूर्व की कांग्रेस-राकांपा सरकार में वह मंत्री भी रहे हैं। गुरुवार सुबह 5.30 बजे कागल स्थित उनके बंगले और पुणे स्थित उनके पुत्र के आवास सहित उनके कारखानों और रिश्तेदारों के घरों पर एक साथ आयकर विभाग ने छापामारी शुरू कर दी। विभाग ने छापों का कारण स्पष्ट नहीं किया है।

राकांपा ने आरोप लगाया है कि मुश्रिफ ने भाजपा में जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया इसके बाद ही उन पर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कोल्हापुर की एक सार्वजनिक सभा में मुश्रिफ को भाजपा में आने का न्योता दिया था। जिसे ठुकराते हुए विधायक ने भाजपा से पूछा था कि उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, जिसके दम पर कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है।

बोले कौशिक

बांग्ला फिल्म अभिनेता हैं कौशिक सेन, उन्होंने बताया कि उन्हें असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।

पीएम को पत्र लिखने के बाद मिली जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

असहिष्णुता, मॉब लिंचिंग व जय श्रीराम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल बांग्ला फिल्म अभिनेता कौशिक सेन ने गुरुवार को उन्हें धमकी भरा फोन आने की शिकायत दर्ज कराई है। सेन ने कहा कि पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें फोन नंबर भेज दिया है। सेन ने बताया-'मुझे अज्ञात नंबर से एक कॉल आया, जिसमें मुझे पीट-पीटकर मार डालने और असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। मुझसे कहा गया कि अगर मैं अपना तरीका नहीं बदलता हूं तो मेरी हत्या कर दी जाएगी।'

सेन ने आगे कहा-'ईमानदारी से कहूं तो मैं इस तरह के कॉल को लेकर चिंतित नहीं हूं। मैंने कॉल के बारे में पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य लोगों को भी सूचित कर दिया है और उन्हें भी फोन नंबर भेज दिया है।'

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

इससे पहले फिल्म निर्माताओं, लेखकों और अभिनेताओं सहित 49 प्रतिष्ठित हस्तियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश में मॉब लिंचिंगऔर पीट-पीट कर हत्या की हालिया घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी।

49 हस्तियों ने लिखा है खुला खत

प्रधानमंत्री को संबोधित इस चिट्ठी में लिखा गया है कि देशभर में लोगों को जय श्रीराम के नारे के आधार पर उकसाने का काम किया जा रहा है। साथ ही दलित, मुस्लिम और दूसरे कमजोर तबकों के खिलाफ मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। चिट्ठी में अपर्णा सेन, कोंकणा सेनशर्मा, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप, शुभा मुद्गल जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गजों के हस्ताक्षर हैं।

नुसरत जहां ने कहा, उन्मादियों ने राम नाम को हत्या की चीख में बदल दिया है

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

असहिष्णुता पर 49 हस्तियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे खुले पत्र के समर्थन में तृणमूल सांसद नुसरत जहां भी उतर आई हैं।

नुसरत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है-'आज जहां हर कोई सड़क, बिजली, विमान जैसे मुद्दों पर बात करने में व्यस्त है, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सिविल सोसाइटी ने एक बहुत ही बुनियादी मुद्दा उठाया है, इंसान की जिंदगी। मुझे हमारे नागरिकों से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वे अपनी आवाज उठाएंगे और हमारा काम करेंगे। नफरत के अपराध और मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। 2014 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं अनुसूचित जाति, मुसलमानों और पिछड़ों के साथ हुई हैं। 2019 में अब तक 11 ऐसी घटनाएं और चार हत्याएं हो चुकी हैं और सारे पीड़ित अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय से थे। उन्मादी भीड़ ने राम के नाम को हत्या की चीख में तब्दील कर दिया है।' नुसरत ने इस बाबत तबरेज, अखलाक, पेहलू खान का जिक्र किया।

नुसरत आगे लिखा-'सिर्फ इंसानियत के नाते गाय के नाम पर, भगवान के नाम पर, किसी की दाढ़ी पर तो किसी की टोपी पर ये खून-खराबा बंद करें। भगवान राम के नाम पर हत्याएं की जा रही हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को रोकने का आदेश दे चुका है, लेकिन सरकार खामोश है।' नुसरत ने अंत में इकबाल की रचना 'सारे जहां से अच्छा' की कुछ लाइनें लिखी हैं।

बंगाल में भाजपा सांसद के घर पर फायरिंग व बमबाजी

जागरण संवाददाता, बैरकपुर

लोकसभा चुनाव से बंगाल में भाजपा और तृणमूल के बीच शुरू हुई राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के बाद एक बार फिर उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में अशांति व्याप्त है। बुधवार देर रात भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बड़ा हमला हुआ। सांसद अर्जुन सिंह के परिवार का कहना है कि उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने बीती रात बम से हमला किया है। इसके अलावा आवास पर कई राउंड फायरिंग भी की गई है। हालांकि, इस बमबाजी व गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सिंह के परिवार ने इस घटना के बाद राज्य की सतारुढ़ तृणमूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमले के विरोध में भाजपा समर्थकों ने इलाके में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं घटना के बाद तत्काल मौके पर पुलिस आयुक्त समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच गए थे। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पिछले दो माह से इस क्षेत्र के भाटपाड़ा, काकीनाड़ा समेत कई इलाकों में दुकानें, बाजार, स्कूल बंद है।

उत्तर 24 परगना जिले के जगदल थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद सांसद के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह भाजपा से विधायक भी है। सिंह परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अर्जुन सिंह के परिवार ने इसे एक जानलेवा हमला बताते हुए इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है।

जिस वक्त यह घटना हुई, अर्जुन सिंह अपने घर पर नहीं थे। वह दिल्ली में संसद सत्र में भाग लेने दिल्ली गए हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद अर्जुन के घर के बाहर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

1300 कमांडो वीआइपी ड्यूटी से मुक्त हो गए हैं केंद्र की तरफ से बड़ी संख्या में देश भर के नेताओं और सांसदों की सुरक्षा हटाए जाने के बाद। इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने करीब 350 गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 26 जुलाई 2019

दुश्मन को छका चोटी मुक्त कराई

मेजर राजेश सिंह अधिकारी

जन्म : 25 दिसंबर, 1970 नैनीताल, उत्तराखंड
शहीद हुए : 30 मई, 1999 (उम्र 28 वर्ष)
यूनिट : 18 ग्रेनेडियर्स

शौर्य गाथा : इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 11 दिसंबर, 1993 को सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान 30 मई को उनकी यूनिट को 16,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह पोजीशन भारतीय सेना के लिए बेहद अहम थी क्योंकि यहीं पर भारतीय सेना बंकर बनाकर टाइगर हिल पर बैठे दुश्मनों पर निशाना साध सकती थी। जब मेजर अधिकारी अपने सैनिकों के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे तो दुश्मनों ने दो बंकरों से उनपर हमला करना शुरू किया। उन्होंने

जरा याद करो कुर्बानी...

बिना देर किए रॉकेट लांचर डिटैचमेंट को बंकर की तरफ मोड़ा और बंकर के अंदर घुसकर दो दुश्मनों को मार गिराया। इसके बाद अपने मीडियम मशीन गन को एक पत्थर से बांधकर दुश्मन को उसमें उलझा दिया और खुद दूसरे बंकर की तरफ बढ़े। खुद बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी बंकर में घुसकर एक पाकिस्तानी सैनिक को मौत के घाट उतारा। इसके बाद खुद भी शहीद हो गए। उनके इस साहस और सूझबूझ की बदौलत तोलोलिंग चोटी भारत के कब्जे में आई जिसके बाद प्वाइंट 4590 पर कब्जा करना आसान हुआ। उन्हें सेना का दूसरा सर्वोच्च मेडल महावीर चक्र प्रदान किया गया।

पाक कारगिल जैसी हिमाकत करेगा तो भुगतेगा गंभीर परिणाम : रावत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने पर मुख्य समारोह में हिस्सा लेने गुरुवार को द्रास पहुंचे थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वह दोबारा 1999 जैसा दुस्साहस न करे। करगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तान का एक बड़ा दुस्साहस था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है वह ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा और अगर करेगा तो भुगतेगा। उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम उसे पूरी तरह खदेड़ देंगे।

द्रास में पत्रकारों से बातचीत में जनरल रावत ने कहा कि 1999 में पाकिस्तान ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षाबलों की इच्छा और सद्भावना का सम्मान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि हम उसे खदेड़ देंगे। वह जिस भी ऊंची चोटी और पहाड़ी पर कब्जा कर ले, हम हमेशा उसे वहां से खदेड़ देंगे। बेहतर यही है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की हिमाकत न करे। पाकिस्तानी सेना को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हम भी इस तरह की कार्रवाई करने में पूरी तरह समर्थ हैं। आज हमारे

थलसेना प्रमुख बिपिन रावत फाइल

- द्रास पहुंचे थलसेना प्रमुख जनरल रावत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी
- किसी भी ऊंची चोटी पर कब्जा कर ले पाकिस्तान, हम हमेशा खदेड़ देंगे

हथियार, साजो सामान पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बहुत मजबूत है, हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ हैं। भविष्य में अगर युद्ध हुआ तो वह दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा विनाशकारी और उसकी सोच से परे होगा। हम किसी भी समय किसी भी स्थिति में दुश्मन को खदेड़ सकते हैं।

हम इमरान खान के बयानों के बहकावे में नहीं आने वाले

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पुलवामा हमले के संदर्भ में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हम सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे खुफिया तंत्र ने हर बात साबित की है। इसलिए हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दावों और बयानों के बहकावे में नहीं आने वाले।

घुसपैठ में कमी आई

घुसपैठ संबंधी सवाल के जवाब पर जनरल रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरहद पार से घुसपैठ में दो कारणों से कमी आई है। पहला- हमारे जवान पूरी तरह सजग और सतर्क हैं। दूसरा हमने अपने घुसपैठरोधी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अतिरक्त बल तैनात किए हैं, ताकि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि अगर वह नियंत्रण रेखा के करीब भी पहुंचे तो फिर उनकी लाश ही उठेगी।

आगरा में ईसाई समाज की पहल, एक परिवार-एक कब्र

जागरण संवाददाता, आगरा

- जगह की कमी देख ईसाई समाज खुलवाने लगा दशकों पुरानी कब्रें
- प्रार्थना सभा में अनुयाइयों को समझाया जा रहा इसका महत्व

जीते जी तो परिवार के साथ रहते ही हैं, ईसाई समाज का मिशन है कि दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी पूरा परिवार एक कब्र में साथ ही रहे। इस मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए दशकों पुरानी कब्रों को खुलवाना शुरू कर दिया गया है। प्रार्थना सभा में अनुयाइयों को इस मिशन के महत्व को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है।

ईसाई समाज की संस्था आगरा ज्वाइंट्स सिमेट्रीज कमेटी (एजेएससी) ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आगरा में गोरों का कब्रिस्तान और तोता का ताल कब्रिस्तान आता है। कमेटी के चेयरमैन फादर मून लाजरस बताते हैं कि तमाम ऐसी कब्रें हैं, जहां पर अरसे से कोई मोमबत्ती जलाकर अपनों की याद करने नहीं आया है। ऐसी कब्रों का ब्योरा जुटाने के बाद अब ये खुलवाई जाने लगी हैं, ताकि भविष्य के लिए इंतजाम किया जा सके।

एक कब्र में सात तख्ता : एक कब्र में सात तख्ते डाले जाएंगे। एक शव दफनाने के बाद एक तख्ता डाल दिया जाएगा और कब्र पर सबसे ऊपर पत्थर रख दिया जाएगा। यही प्रक्रिया आगे भी अपनाई जाएगी। वे कहते हैं कि दक्षिण भारत में कई जगह एक परिवार-एक कब्र का सिलसिला चल रहा है। वहां के लोगों को इस बात का भी सुकून है कि दुनिया छोड़ने के बाद भी परिवार हमेशा के लिए साथ-साथ तो है।

ऐसी होगी व्यवस्था : प्रार्थना सभा में अनुयाइयों को इस व्यवस्था के बारे में लगातार बताया जा रहे हैं। मिशन का महत्व भी समझाया जा रहा है। 27 अक्टूबर को पादरियों की बैठक में इस पर निर्णय हो जाएगा और दो नवंबर को कब्र पर्व यानी 'ऑल सोल्स डे' पर लागू कर दिया जाएगा।

एजेएससी कहती है कि आगरा के छावनी क्षेत्र में गोरों व लोहामंडी में तोता का ताल कब्रिस्तान, लखनऊ में माल एवेन्यू व गोरा कब्रिस्तान, मेरठ में लेखानगर कब्रिस्तान, बरेली में जनकपुरी और सहारनपुर के मिशन कंपाउंड कब्रिस्तान में इसी तरह की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

बिहार के औरंगाबाद में हुई मुठभेड़, तीन नक्सली ढेर

कार्रवाई ▶ दो इंसास, दो एके-47 सहित आठ हथियार बरामद

तकरीबन दो घंटे तक होती रही मुठभेड़, दोनों ओर से पांच सौ राउंड गोली दागे जाने की सूचना

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद

बिहार के औरंगाबाद के जंगल में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया। सतनदिया के पास पहाड़ पर दिन के उजाले में तकरीबन दो घंटे तक मुठभेड़ हुई। नक्सलियों के ठिकाने से आठ अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र, काफी मात्रा में कारतूस, काली वर्दी, छाते, बैग, तिरपाल आदि बरामद हुए हैं। बरामद आग्नेयास्त्रों में दो इंसास, दो एके-47 और पुलिस की रायफल शामिल है। आइजी सुशील एम खोपड़े ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से पांच सौ चक्र फायरिंग हुई है। सुरक्षा बलों के अनुसार हताहत होने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है।

दंतेवाड़ा में दो नक्सली गिरफ्तार

नईदुनिया, राजनांदगांव: दंतेवाड़ा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की टीम ने गुरवार को कटेकल्याण थाना क्षेत्र के बड़ेलखापाल-पटेलपारा इलाके से दो नक्सलियों की गिरफ्तार किया है। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि उनकी पहचान तोयलंका पटेलपारा निवासी आयतु पुत्र पांडू सोढी और पांडू पुत्र हिड़मा सोढी के रूप में हुई। दोनों जनमिलिशिया सदस्य हैं।

जंगल में मिला नक्सलियों का छिपाया बम बनाने सामान: छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा के दूतागढ़ जंगल से पुलिस ने गुरवार सुबह नक्सली सामग्री बरामद किया है। इसे प्लास्टिक के ड्रम के अंदर छिपाकर रखा गया था। पुलिस मौके से आइइडी बनाने के उपयोग में लाने वाला सामान बरामद किया।

टीम जैसे ही नक्सलियों के ठिकाने के पास पहुंची कि पहाड़ में छुपे नक्सली फायरिंग करने लगे। सुरक्षाबलों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने आइईडी विस्फोट भी किया। जवानों ने चार नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। नक्सलियों की ओर से फायरिंग बंद होने के एक घंटे बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसी दौरान नक्सलियों के ठिकाने से हथियार आदि बरामद हुए। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा।

सप्ताह भर पहले अंबा में हुई थी मुठभेड़: गौरतलब है कि 18 जुलाई को अंबा थाना क्षेत्र में संडा गांव के पास बटाने नदी पर निर्माणाधीन पुल को उड़ाने पहुंचे नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। अपने को घिरता देख नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले थे। भागने के दौरान वे अपनी तीन बाइक छोड़ गए, जो जब्त कर ली गई । घटनास्थल से एके-47 के 28 और एसएलआर के आठ खोखे बरामद किए गए थे। नक्सलियों का नेतृत्व कमांडर अभिजीत यादव उर्फ बनवारी कर रहा था।

23 साल पहले बम कांड का आरोपित बनाकर जेल भेजा, नहीं मिले सुबूत

जागरण संवाददाता,जयपुर: राजस्थान के दौसा में 23 साल पहले 1996 में रोडवेज बस में हुए विस्फोट के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने दो लोगों की सजा बरकरार रखते हुए सात अन्य को बरी कर दिया है। इनमें एक उत्तर प्रदेश के आगरा का ईस बेग भी है, जिसे 1997 में इस मामले में आरोपित बना कर जेल भेज दिया गया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने राज्य सरकार तथा अभियुक्तों की अपीलों पर उक्त आदेश दिया। ईस व अन्य सभी को मंगलवार को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने मामले में डॉ. अब्दुल हमीद की फांसी व पप्पू उर्फ सलीम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

गौरतलब है कि 22 मई 1996 को राजस्थान रोडवेज की बस आगरा से बीकानेर जा रही थी। इसमें करीब 50 यात्री सवार थे। दौसा में महुआ से करीब चार किलोमीटर आगे समलेटी में बस में विस्फोट हो गया, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई। मामले में 12 लोगों को आरोपित बनाया गया। 29 सितंबर 2014 को बांदीकुई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अब्दुल हमीद को फांसी की सजा सुनाई। अन्य आरोपितों ईस बेग, जावेद खान जूनियर, लतीफ अहमद बाजा, मोहम्मद अली भट्ट, मिर्जा निसार हुसैन व अब्दुल गोनी, पप्पू उर्फ सलीम को उम्रकैद की सजा मिली। सभी ने अपनी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने जावेद खान, लतीफ अहमद, मोहम्मद अली भट्ट, मिर्जा निसार हुसैन, अब्दुल गोनी व ईस बेग को बरी कर दिया।

सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी ने अपनी भूमिका से किया इन्कार

सोनभद्र हिंसा मामला

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

- जमीन की वैधता साबित करने के सभी कागजात मौजूद होने का दावा
- पत्नी और बेटी ने 144 बीघा जमीन 50 लाख रुपये में यज्ञदत्त को बेची थी
- बिहार कैडर के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी हैं प्रभात मिश्रा

बिहार कैडर के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी प्रभात मिश्रा ने सोनभद्र के उभ्भा गांव में नरसंहार की वजह बने भूमि कब्जे के आरोपों से इन्कार किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास जमीन की वैधता साबित करने के लिए सभी कागजात मौजूद हैं।

उनके ससुर महेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा ने 1951 में आदर्श सहकारी कृषि समिति उभ्भा-सपही का गठन किया था। वहां के राजा आनंद ब्रह्मशाह से महेश्वर सिन्हा और उनके परिवार के चार सदस्यों के नाम से भूमि खरीदी गई थी। इसमें कुल 12 सदस्यों ने सामूहिक रूप से 1400 बीघा जमीन ली थी। इसमें अन्य सात सदस्य भी थे। महेश्वर प्रसाद उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण के बड़े भाई थे। महेश्वर प्रसाद अप्रैल 1952 से दो अप्रैल 1956 तक सोशलिस्ट पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी रहे।

प्रभात मिश्रा के अनुसार उनकी महेश्वर सिन्हा की बेटी आशा से 1951 में शादी हुई। समिति का एक सदस्य होने के नाते जमीन का बड़ा हिस्सा उसके नाम पर था। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के बाद समिति के 12 सदस्यों में से प्रत्येक के पास 72 बीघा जमीन बची थी, जिसमें आशा और महेश्वर सिन्हा की पत्नी पार्वती देवी भी शामिल थीं। 1978 में महेश्वर प्रसाद के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को सदस्यों द्वारा समिति का अध्यक्ष चुना गया।

1985 में महेश्वर प्रसाद की पत्नी की मृत्यु हो गई और उनकी इच्छा के अनुसार मेरी बेटी विनीता शर्मा को भी 72 बीघा जमीन मिली। पत्नी आशा और बेटी विनीता ने उभ्भा और सपही गांव की कुल 144 बीघा जमीन को 50 लाख रुपये में यज्ञदत्त भूर्तिया को बेच दी। पचास लाख रुपये पत्नी ने शिरडी साईं श्राइन बोर्ड को दान कर दिया।

उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता नित्यानंद द्विवेदी ने उनके दावों को खारिज कर दिया और समाज की वैधानिकता की लड़ाई लड़ी। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत वह उत्तर प्रदेश में एक समिति को पंजीकृत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे बिहार के निवासी हैं। प्रभात कुमार ने कहा कि नरसंहार मामले में उनका नाम घसीटा जा रहा है, जो सही नहीं है। वह मीरजापुर में तैनात भी नहीं थे। उन्होंने अपनी भूमिका से इन्कार किया है।

कोयला घोटाले में नवीन जिंदल पर आरोप तय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल और चार अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत ये आरोप तय किए हैं। अब विशेष अदालत में 30 सितंबर से ट्रायल शुरू होगा।

विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के अर्टन नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित मामले में नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप प्रबंध निदेशक आनंद गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत गुजराल और कंपनी के अधिकृत अधिकारी डीएन अबरोल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सीबीआइ की तरफ से दायर आरोप पत्र के अनुसार, आरोपितों ने मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए धोखाधड़ी और साजिश रची थी। स्क्रीनिंग कमेटी को जनवरी 2007 में किए गए आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत किए थे। अनुचित तरीके से लाभ पाने के लिए कोयला मंत्रालय को धोखे में रखा गया और अक्टूबर 2009 में कंपनी को आवंटन पत्र जारी करवा लिया गया था। आरोप पत्र में जांच से संबंधित 60 दस्तावेज और 64 व्यक्तियों के नाम अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर शामिल हैं। वहीं, झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितताओं के मामलों में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव व झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, नवीन जिंदल भी आरोपित हैं।

निर्भयाकांड के दोषी की तस्वीर मामले में तहसीलदार निलंबित

जागरण न्यूज नेटवर्क, चंडीगढ़

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के दोषी का फोटो चुनाव आयोग के बैनर पर लगाने के मामले में होशियारपुर के तहसीलदार (मतदान) करनैल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही बैनर बनाने वाले आनंद प्रिंटिंग प्रेस के मालिक तेजिंदर सिंह निवासी होशियारपुर पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित पर यह मामला धारा 71ए व 72ए (इन्फार्मेशन व टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग करने) के तहत दर्ज किया गया।

जिला उपायुक्त ईशा कालिया की तरफ से दी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीप प्रोजेक्ट के तहत जिला चुनाव कार्यालय की तरफ से अलग-अलग तरह के कई बैनर बनवाए गए थे। उन सभी में यह इकलौता बैनर था। प्रिंटिंग प्रेस वाले ने संबंधित अधिकारी के मौखिक कहने पर पुरुष का फोटो लगा दिया। तीनों फोटो के नीचे किसी का नाम नहीं दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार बैनर में लगी तस्वीर जानबूझकर नहीं लगाई गई थी। यह लापरवाही से लगी थी। चुनाव आयोग के निर्देशों पर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए बैनर व पोस्टर छापे गए थे। इन पर महिला, पुरुष व थर्ड जेंडर की फोटो लगाई जानी थी। होशियारपुर जिला प्रशासन की तरफ से छपवाए गए ऐसे बैनर पर एक फोटो निर्भया कांड के दोषी की छाप दी गई। कई महीनों तक इस फोटो के बारे में पता नहीं चला। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के व्यक्ति ने पोस्टर को देखा और दोषी की फोटो लगाने पर एतराज जताया। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. करुणा राजू ने मामले की जांच करवाई तो फोटो दोषी की ही निकली। उसके बाद तहसीलदार करनैल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। करनैल अपनी बेटी के विवाह समारोह में विदेश गए हुए हैं। भारत लौटते ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई।

इसलिए नहीं की जिला चुनाव अधिकारी पर कार्रवाई

मुख्य चुनाव अफसर एस. करूणा राजू का कहना है कि भले ही जिले का चुनाव अफसर डिप्टी कमिश्नर होता है, लेकिन उन्होंने अलग-अलग काम विभिन्न ब्रांचों को बांटे होते हैं। बैनर छपवाने का काम तहसीलदार को सौंपा गया था। उन्हीं की जिम्मेवारी बनती थी कि वह बैनर को पहले जांच लें।

झारखंड में स्थानीय से ज्यादा बाहरी शिक्षकों की नियुक्ति पर हंगामा

राज्य ब्यूरो, रांची : हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में झारखंड के 11 जिलों के सामान्य पदों में अधिसंख्य दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नियुक्त हो रहे हैं। पलामू तथा देवघर में अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र से यह मामला सामने आया है। संभावना है कि अन्य नौ जिलों में भी इसी तरह दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। इसे लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों में रोष है। गुरुवार को मामला सदन में भी उठा। झामुमो ने इस मसले पर जमकर हंगामा किया और नियुक्तियों की सीबीआइ जांच की मांग की।

पलामू में अंग्रेजी विषय में सामान्य पद 20 थे जिनमें 17 पदों पर दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के अभ्यर्थी चयनित हुए। इसी तरह, गृह विज्ञान में 46 पद सामान्य श्रेणी के थे। इनमें 27 पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी चयनित हुए। बताया जाता है कि अन्य विषयों में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ है। इसी तरह, देवघर में शारीरिक शिक्षा विषय में सामान्य के 20 पदों में 19 दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। स्थानीय नीति के तहत राज्य के अनुसूचित 13 जिलों में होनेवाली नियुक्तियों को संबंधित जिलों के उम्मीदवारों आरक्षित तो किया गया, लेकिन 11 जिलों को खुला रखा गया था।

एक ने दूसरे श्वान को रक्त देकर बचाई जान

नईदुनिया, नरसिंहपुर

रक्तदान से एक इंसान के दूसरे इंसान की जान बचाने के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक श्वान (डॉग) द्वारा रक्तदान कर दूसरे श्वान की जान बचाने का अनूठा मामला सामने आया है। नरसिंहपुर से सटे ग्राम रौंसरा में जर्मन शेफर्ड नस्ल के जिमी नाम के एनीमिक (खून की कमी) श्वान की जीवन रक्षा करने के लिए उसी नस्ल के लियो नाम के श्वान ने रक्तदान गया। दो निजी पशु चिकित्सकों की देखरेख में हुए इस रक्तदान के बाद लियो स्वस्थ है। साथ ही जिमी की कमजोरी भी दूर हो रही है।

वंदना जाटव ने बताया कि छह वर्षीय जर्मन शेफर्ड नस्ल का उनका श्वान करीब एक माह से बीमार था। वह काफी कमजोर हो गया था। पशु चिकित्सकों ने उसे दवाइयां देने के साथ रक्त चढ़वाने की सलाह दी। यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि जर्मन शेफर्ड नस्ल के श्वान का ही रक्त हो। देशी नस्ल के श्वान का रक्त भी चढ़वा सकते हैं। इस संबंध में जब कोसमखेड़ा निवासी महेंद्र प्रताप सिंह से चर्चा की गई तो वह इसी नस्ल के अपने पालतू श्वान का रक्त देने के लिए राजी हो गए। उनके घर में ही दो निजी चिकित्सकों ने श्वान से रक्तदान कराया। पशु धन संजीवनी केंद्र के डॉ. रोशन चौधरी ने बताया कि रक्तदान करने वाला श्वान स्वस्थ है।

बीमार जर्मन शेफर्ड नस्ल के श्वान के लिए दूसरे श्वान से रक्तदान कराते चिकित्सक। नईदुनिया

एक ही नस्ल का रक्त ज्यादा अच्छा : पशु चिकित्सक डॉ. संजय कुमार मांझी ने बताया कि जिमी में मात्र छह प्रतिशत हीमोग्लोबिन था, जबकि 12 से 13 प्रतिशत होना चाहिए। श्वान के लिए यूं तो किसी भी नस्ल के श्वान का रक्त लिया जा सकता है, लेकिन एक ही नस्ल का रक्त ज्यादा अच्छा होता है। आमतौर पर श्वान हर श्वान से साल में तीन से चार बार रक्तदान कराया जा सकता है। किसी भी श्वान का रक्त दूसरे श्वान को दो से तीन बार बिना ब्लड ग्रुप मैच किए चढ़ाया जा सकता है।

श्वान में होते हैं 12 ब्लड ग्रुप : डॉ. मांझी के अनुसार, श्वान में 12 ब्लड ग्रुप होते हैं। में हीमोग्लोबिन कम होने का कारण यही रहता है कि वह ठीक से खाते नहीं हैं। अन्य बीमारियां भी रहती हैं और उम्र का असर भी होता है।

ग्रामीणों के हमले में घायल बाघिन को नहीं मिला इलाज, मौत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे घुंघचाई गांव में हमले के बाद ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हुई बाघिन की मौत हो गई। वह घंटों घायल होकर पड़ी रही लेकिन, उसे इलाज नहीं मिला। इससे बुधवार रात उसकी मौत हो गई। इस मामले में दो मुकदमे दर्ज किए जाने की तैयारी हो रही है।

टाइगर रिजर्व के दियोरिया रेंज से सटे घुंघचाई गांव में मटेहना कॉलोनी निवासी श्याम मोहन बुधवार शाम अपने खेत में बाड़ लगा रहे थे। तभी झाड़ियों में छिपी बैठी बाघिन ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने के लिए ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने बाघिन पर डंडों से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बाघिन के हमले में नौ ग्रामीण घायल हुए। बाघिन को भी गंभीर चोट आई थी। किसी तरह बाघिन जंगल में चली गई। घायल बाघिन जंगल में पचास मीटर दूर जाकर ही बेसुध हो गई। सात बजे के बाद टाइगर रिजर्व की टीम वहां पहुंची। ग्रामीणों ने उसे घेरकर हंगामा किया। फील्ड डायरेक्टर एच राजामोहन ने बताया कि बाघिन की उम्र करीब सात साल है। उसके गर्भवती होने की भी संभावना है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज किया जा रहा है।

पहल

बुंदेलखंड के बांदा में तालाब-कुआं जियाओ अभियान के तहत जल संरक्षण की चल रही मुहिम, जल शक्ति मंत्रालय ने लिया जायजा, मिल रही सराहना

जल संरक्षण

पीएमओ तक पहुंचीं बुंदेलियों की जल चौपालें

विमल पांडेय, बांदा

जल है तो कल है, यह बात अब बुंदेलियों के जेहन में उतर चुकी है। बांदा में गांव-गांव आयोजित हुईं जल चौपालें इस बात की गवाह हैं। इसके तहत तालाब-कुआं जियाओ अभियान ने भी गति पकड़ ली है। जल संरक्षण की इस अनूठी पहल की गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गई। जिसके बाद जल शक्ति मंत्रालय ने इस अभियान का जायजा लिया।

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांदा, उप्र की जनसभा में कहा था कि अब बारी है बुंदेलखंड में पानी की समस्याओं से निपटने की। प्रधानमंत्री के इस कथन ने बुंदेलियों में जोश भर दिया। चुनाव बाद ही यहां जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया। पहले चरण में गांव-गांव जल चौपालें आयोजित की गईं, फिर दूसरे चरण में तालाब-कुआं जियाओ अभियान शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किया जिलाधिकारी हीरा लाल ने। गत दिनों भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर अभियान की जानकारी ली।

रंग लाई मेहनत: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लबालब एक जलाशय। अभियान के तहत छोटे-बड़े जलस्रोतों को सहेजा जा रहा है। जागरण

कुएं-तालाबों का पूजन और दीपदान : जिला प्रशासन ने पहले चरण में भूजल बढ़ाओ, पेयजल बचाओ अभियान के तहत छह ब्लाकों में जल चौपालों का आयोजन किया। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के बाद दूसरा चरण 10 मई से शुरू किया गया। इसे कुआं-तालाब जियाओ नाम दिया गया। अभियान में गांव-गांव तालाबों और कुओं का पूजन शुरू कराया गया। जिले की 471 ग्राम सभाओं में दीपदान कार्यक्रम हुआ। बांदा शहर के नवाब टैंक तालाब में प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त वेंकेटेश्वर लू ने दीपदान किया था।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

अभियान का यूं पड़ा असर

बड़ोखर ब्लाक के खहरा ग्राम निवासी किसान पंकज सिंह ने खुद के संसाधन से एक बीघा में तालाब का निर्माण कराया।

उन्नतशील किसान प्रेम सिंह ने 10 बिस्वा में तालाब खोदवाया।

बड़ोखर ब्लाक में मुड़ेरी गांव के किसान सोवरन सिंह ने एक बीघे में तालाब का निर्माण कराया।

महुआ ब्लाक के पड़ुई ग्राम के नवल किशोर ने एक बीघे में तालाब का निर्माण कराया है।

बांदा जिले के लोगों की जागरूकता निश्चित ही प्रेरक है। अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। जल्द ही यहां पेयजल समस्याओं का ठोस निस्तारण देखने को मिलेगा।

-हीरा लाल, जिलाधिकारी, बांदा

अभियान के तहत हुए कार्य	
पुराने तालाब	2200
खोदवाए गए तालाब	356
कुओं की संख्या	7500
साफ किए गए कुएं	3488
तालाबों में दीपदान	2145

साध्वी प्राची के बयान पर डीजीपी ने तलब की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, बागपत : साध्वी प्राची द्वारा बुधवार को दिए गए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ गया है। डीजीपी ने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए बागपत, उप्र पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। मामले की जांच एएसपी कर रहे हैं। साध्वी के बयान संबंधी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। बागपत के दाहा गांव में भंडारे के उद्घाटन के दौरान साध्वी प्राची ने बयान दिया था कि मुस्लिम कारीगरों के हाथ से बनी राखी व कांवड़ न खरीदें और खुद ही कांवड़ तैयार करें। उन्होंने कहा था कि सपा विधायक नाहिद हसन के भाजपाई दुकानदारों से सामान न खरीदने संबंधी बयान की प्रतिक्रिया में वह यह अपील कर रही हैं।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर में तथा हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। राजस्थान के मध्यम भागों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के शेष भागों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

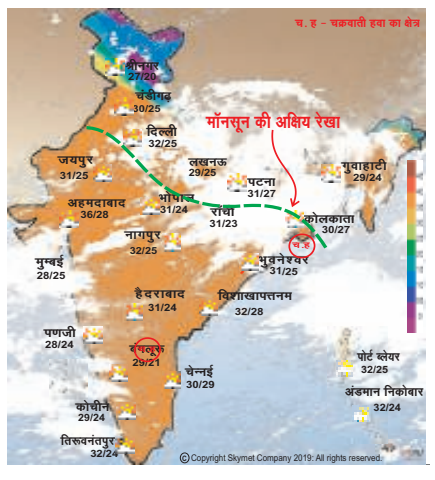

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/25/व	अहमदाबाद	33/26/व
कोलकाता	33/25/आंबा बड़ोदा		30/25/व
चेन्नई	35/25/व	नागपुर	31/25/व
हैदराबाद	29/23/व	इन्दौर	29/24/व
बंगलूरु	31/20/व	रांची	31/25/व
विशेन्द्रम	33/25/व	पटना	36/28/व
गुवाहाटी	30/24/व	जमशेदपुर	29/25/आंबा
गंगटोक	16/11/व	पुणे	24/22/व

2022 तक सिक्किम की राजधानी गंगटोक को सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों से जोड़ दिया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां आपस में रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।

अभिमन्यु की तरह लड़े

कैप्टन अनुज नायर

जन्म : 28 अगस्त, 1975 दिल्ली
शहीद हुए : 7 जुलाई, 1999 (24 वर्ष)
यूनिट : 17 जाट रेजीमेंट

जरा याद करो कुर्बानी...

शौर्य गाथा : इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पासआउट होने के बाद जून, 1997 में जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनका पहला अभियान था प्वाइंट 4875 पर कब्जा करना। यह चोटी टाइगर हिल की पश्चिमी ओर थी और सामरिक लिहाज से बेहद जरूरी। इसपर कब्जा करना भारतीय सेना की प्राथमिकता थी। अभियान की शुरुआत में ही नैयर के कंपनी कमांडर जख्मी हो गए। हमलावर दस्ते को दो भागों में बांटा गया। एक का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया और दूसरे का कैप्टन अनुज ने। कैप्टन अनुज की टीम में सात सैनिक थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने दुश्मन पर चौतरफा वार किया। कैप्टन अनुज ने अकेले नौ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और तीन दुश्मन बंकर ध्वस्त किए। चौथे बंकर पर हमला करते समय दुश्मन ने उनकी तरफ रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड फेंका जो सीधा उनपर गिरा। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वे बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। शहीद होने से पहले उन्होंने आखिरी बंकर को भी तबाह कर दिया। दो दिन बाद दुश्मन सेना ने फिर से चोटी पर हमला किया जिसका जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने दिया। कैप्टन नायर को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया।

अपना देस : कांवड़िया बन शिव का जलाभिषेक करता रहमान

जागरण विशेष

राज नारायण शुक्ल, प्रतापगढ़

हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आपस में सब भाई-भाई...। और, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा...। ये बस कोरी बातें नहीं हैं। रहमान अली का उदाहरण सामने है। प्रतापगढ़ निवासी रहमान पिछले छह साल से अपने हिंदू दोस्तों संग बैजनाथ धाम की कांवड़ यात्रा पर जाते हैं।

सावन का महीना है और चारों तरफ रंगबिरंगे कांवड़ उठाए शिवभक्तों की टोलियां नजर आ रही हैं। ऐसे में रहमान अपने हिंदू दोस्तों के साथ कांवड़ यात्रा पर जाकर सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। रहमान की अपने धर्म के प्रति पूर्ण आस्था है, लेकिन हिंदू धर्म और भारत की मिश्रित संस्कृति के प्रति भी उनकी श्रद्धा देखते ही बनती है। रहमान के जज्बे को देख अब तो उनके हिंदू दोस्त भी उनके बिना कांवड़ यात्रा पर नहीं निकलते। पिछले छह साल से रहमान अपने हिंदू दोस्तों के साथ कांवड़ लेकर बाबा बैजनाथ धाम जाते आ रहे हैं। पत्नी ने भी पूरा साथ दिया और दोस्तों को भी उन पर गर्व है।

पेशे से बिजली मैकेनिक रहमान भेदभाव में यकीन नहीं रखते।

उनके विचारों से प्रभावित होकर कई हिंदू भी उनके दोस्त बन गए। दोस्ती का यह सिलसिला बढ़ता चला गया। रहमान भी अपने हिंदू दोस्तों की शिवभक्ति से बेहद प्रभावित हुए। सावन में अपने दोस्तों को कांवड़ उठाकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जाते देख उनके मन में भी कांवड़ियां बनने की इच्छा पैदा हुई। दोस्तों से अपनी इच्छा बताने के बाद पत्नी से भी राय ली। पत्नी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। छह साल पहले वह पहली बार कांवड़ लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम, झारखंड गए। रहमान के दोस्त राजेश कुमार, यादवेंद्र कुमार, संजय, नीलेश आदि उनकी इस सोच पर गर्व करते हैं। वह कहते हैं कि रहमान ने अपना धर्म बदले बिना दूसरे की आस्था और संस्कृति से प्रेम और सम्मान करके दिखाया है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

यात्रा में कांवड़ लिए रहमान (दाएं) सामाजिक समरसता की पेश कर रहे हैं मिसाल। फाइल फोटो

मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग यहां आकर देखें कि कैसे इस मुल्क में राम-रहमान साथ रहते हैं। देखें कैसे अजान और पूजा साथ-साथ होती है। सोच बदलकर देखना होगा। लड़ाने वालों की चालों को समझना होगा। **-रहमान अली।**

पहली ही भेंट में हम तो रहमान की सोच व विचारधारा के कायल हो गए। वह कहने लगे कि इबादत का यह भी एक तरीका है। वह कांवड़िया का भेष रख हमारे साथ जाते हैं। सच है कि ऐसी बड़ी सोच कम लोगों की होती है।

-दिनेश प्रजापति (रहमान के दोस्त)

हम लोगों ने नवयुवक कांवड़िया संघ बनाया है। पड़ोस में रहने आए रहमान हमारे मित्र बने तो कांवड़ यात्रा से भी जुड़ गए। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम लोग उन्हें साथ में ले गए। अब तो वह हमारी टोली के चहेते सदस्य हैं।

-प्रभात चौधरी (रहमान के दोस्त)

बेशक यह पहल एक पैगाम है उन लोगों को, जो मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं, लड़ाई कराते हैं। हिंदू-मुस्लिम एकता की यह मिसाल प्रतापगढ़ के लिए किसी शान से कम नहीं। मैं तहेदिल से रहमान भाई की सोच की तारीफ करता हूं।

-नियाज प्रतापगढ़ी, शायर

हमारा मुल्क गंगा-जमुनी विचारधारा का है। लोग मिलकर रहते हैं। हिंदू दोस्तों की खुशी में शामिल होना बहुत अच्छी बात है। मैं रहमान के इस कदम को सही मानता हूं। कम से कम वह एकता करके दिखा रहे हैं, लोग केवल कहते ही हैं।

-मो. इश्तियाक, अधिवक्ता

न्यूज गैलरी

सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने श्रीनगर में डटे एनएसए डोभाल

श्रीनगर : आतंकी व अलगाववादी तत्वों के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्ती के जमीनी असर और राज्य के मौजूदा आंतरिक-बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल दो दिन से ग्रीष्मकालीन राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने इस दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों और सिविल सोसायटी के लोगों से अलग-अलग बैठकें कीं। अनुच्छेद-35ए पर अगले महीने केंद्र सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिए जाने की अटकलों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की कश्मीर में मौजूदगी ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि वह अनुच्छेद 35ए की समाप्ति का रोडमैप तैयार करने और इसे भंग किए जाने की स्थिति में कश्मीर के हालात से निपटने की योजना की तैयारी के लिए आए हैं। (राब्यू)

फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए ममता के भतीजे

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी गुरुवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए। दिल्ली की विशेष अदालत ने अभिषेक के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें 25 जुलाई को अदालत में हाजिर होने को कहा था। मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। (जेएनएन)

विकट हालात ▶ नेपाल में भारी बारिश, बिहार में कोसी-सीमांचल की नदियों में बढ़ा पानी

टूट रहे बांध, डूब रहे गांव, आठ और की मौत

उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी, जनजीवन अस्तव्यस्त

जागरण टीम, मुजफ्फरपुर/ पूर्णिया

उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल बाढ़ नए इलाकों में लोगों की मुश्किल बढ़ाने लगा है। उत्तर बिहार में गुरुवार को भी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त रहा। नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी रही। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। रक्सौल में त्रिवेणी नहर का तटबंध टूट गया। इससे कई गांवों में पानी फैल गया है। सीतामढ़ी में राहत को लेकर लोगों ने हंगामा किया। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित 14 प्रखंडों और शहरी क्षेत्र में बागमती, जीवछ व कमला बलान के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी रहा। जाले में बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड प्रमुख -उप प्रमुख को बंधक बनाए रखा। बाढ़ के पानी में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। एक लापता है। बाढ़ के पानी में डूबने से पूर्णिया में दो, सहरसा में दो और अररिया-किशनगंज में एक-एक मौत हुई है।

पश्चिम-पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी के नए इलाके डूबे : पश्चिम चंपारण जिले में दोन के 22 गांवों का सड़क संपर्क तीसरे दिन भी भंग रहा। रामनगर प्रखंड की गुदगुदी पंचायत के गांवों को मसान नदी के कहर से बचाने के लिए बना पायलट चैनल और पारको पाइन बांध का नामोनिशान मिट गया है। एनएच- 727 पर सिरौना व पचफेड़वा गांव के बीच डेढ़ फीट पानी बह रहा है।

सिकटा व मैनाटांड प्रखंड मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यालय का संपर्क भंग हो गया है। पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी का पानी सुगौली शहर में प्रवेश कर गया है। बंगरी नदी के दबाव से रामगढ़वा प्रखंड के बेलहिया गांव के पास त्रिवेणी नहर का तटबंध करीब तीस फीट तक टूट गया है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कोसी, भुतही बलान व कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी रही। समस्तीपुर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी रहा। सीतामढ़ी जिले में जारी मूसलाधार बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। सीतामढ़ी शहर के कई मोहल्ले बाढ़ के पानी की गिरफ्त में हैं। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित 14 प्रखंडों और निगम क्षेत्र के मोहल्लों में बागमती, जीवछ व कमला बलान के जलस्तर में कमी आई है। वहीं, सदर प्रखंड में जीवछ के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। कुशेश्वरस्थान की 14 पंचायतों में स्थिति गंभीर बनी है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा और औराई प्रखंड के दर्जनों गांव पानी से घिरे हैं।

पूर्णिया में महानंदा, परमान, कनकई आदि नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन नदियों में पानी बढ़ रहा है। सुपौल में कोसी के जलस्राव में उतार-चढ़ाव जारी है। सहरसा में भी कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में केले के थंब की नाव ग्रामीणों के आवागमन की सहारा बनी। जागरण

भूस्खलन के चलते गंगोत्री हाईवे दो दिन से बंद

जासं, देहरादून : बारिश और भूस्खलन से उत्तरकाशी के बड़ेथी में गंगोत्री हाईवे दो दिन से बंद है। वैकल्पिक मार्ग के जरिए यात्रियों को गंगोत्री भेजा जा रहा है। साथ ही मार्ग को खोलने का काम जारी है। यमुनोत्री हाईवे उत्तरकाशी के डाबरकोट और केदारनाथ मार्ग पर रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में भी यातायात सात घंटे के लिए बाधित रहा।

उत्तराखंड में बारिश के चलते मलबा गिरने से 50 से अधिक संपर्क मार्ग बंद हैं। वहीं, यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट के पास रुक-रुककर मलबा गिर रहा है। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में मलबा आने से बंद केदारनाथ हाईवे को सात घंटे बाद वाहनों के लिए खोला जा सका। थल-पिथौरागढ़ मार्ग पर मलबा आने से घंटों यातायात प्रभावित रहा। वहीं, धारचूला से आगे कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग गस्कू के पास मलबा आने से 18 घंटे बंद रहा।

कुमाऊं मंडल में सीमांत पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर-तवाघाट हाईवे पर लखनपुर के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया। इससे यह करीब 16 घंटे बंद रहा।

कुलभूषण जाधव के लिए पाकिस्तान के संपर्क में भारत

- काउंसलर एक्सेस पर मंजूरी के लिए पाकिस्तान का काम करने का दावा
- पाक में कैद पूर्व नौसैनिक का परिवार सुषमा स्वराज से मिला

नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को भारत उन्हें काउंसलर एक्सेस दिलवाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में है। पूर्व भारतीय नौसैनिक और कारोबारी 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है जिसकी अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) ने समीक्षा करने को कहा है। साथ ही जाधव को विएना कंवेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस भी देने का निर्देश दिया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आप सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत के पक्ष में फैसला आया है। हम उम्मीद करते हैं कि जाधव को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। इसके तहत वह भारतीय दूतावास से अपना केस लड़ने में मदद ले सकेंगे। साथ ही पाकिस्तान अब विएना कनवेंशन के तहत भी काम करेगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह कूटनीतिक जरिए से पाकिस्तानी प्रशासन के संपर्क में हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में पाकिस्तान से हुई बातचीत का कोई भी ब्योरा देने से इंकार कर दिया। प्रेट्र के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैजल ने बताया कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मंजूर करने की दिशा में पाकिस्तान काम कर रहा है। समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक इससे पूर्व दिन में कुलभूषण जाधव के परिवार ने नई दिल्ली में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। स्वराज ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने उनसे मिलने आए कुलभूषण जाधव के परिवार से मुलाकात की है। मैं उन्हें सब अच्छा होने की दुआ देती हूं।

उल्लेखनीय है कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहते हुए इस परिवार के संपर्क में थीं। उन्होंने पाकिस्तान में जाधव को काउंसलर एक्सेस दिलाने के लिए खासे प्रयास किए थे। साथ ही उन्होंने जाधव की फांसी रुकवाने के लिए आइसीजे के फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वकील हरीश साल्वे को धन्यवाद दिया था।

कुलभूषण जाधव फाइल

चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत पर भारत को रखनी होगी निगाह : नौसेना प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने गुरुवार को कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की अन्य शाखाओं से उसकी नौसेना में काफी संसाधन झोंके गए हैं, लिहाजा भारत को उस पर बेहद सावधानी से निगाह रखनी होगी। नौसेना प्रमुख ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब एक दिन पहले ही चीनी रक्षा मंत्रालय ने अपने सैन्य विकास पर श्वेत पत्र जारी किया है।

'नए युग में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा' शीर्षक से जारी श्वेत पत्र में भारत, अमेरिका, रूस और अन्य देशों की तुलना में चीन के सैन्य विकास के विभिन्न पहलुओं को छुआ गया है। करमबीर सिंह ने यहां एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार से इतर संवाददाताओं से कहा, 'यह महज चीनी श्वेत पत्र नहीं है, बल्कि अतीत में भी ऐसा कहा गया है। वैश्विक ताकत बनने के इरादे से (पीएलए की) अन्य इकाइयों से पीएलए नौसेना को काफी सारे संसाधन दिए गए हैं। हमें इसे सावधानीपूर्वक देखना होगा और इस बात पर गौर करना होगा कि हम अपने बजट और दायरे में किस तरह इसका जवाब दे सकते हैं।'

दूसरे स्वदेशी विमानवाहक पोत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नौसेना प्रमुख ने कहा, ''हमारी योजना इलेक्ट्रिकल प्रणोदन और 'कैटोबार' के साथ 65,000 टन का जहाज बनाना है।'' कैटोबार (सीएटीओबीएआर) एक ऐसी प्रणाली है जिसका इस्तेमाल किसी विमानवाहक पोत पर किसी विमान के 'लॉच या रिकवरी' में किया जाता है।

सितंबर-अक्टूबर में नौसेना में शामिल होगी दूसरी स्कॉर्पीन पनडुब्बी : नौसेना प्रमुख ने बताया कि भारत की दूसरी कलवारी श्रेणी की स्कॉर्पीन पनडुब्बी सितंबर-अक्टूबर तक नौसेना में शामिल हो जाएगी। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी आइएनएस खंदेरी जनवरी, 2017 में नौसेना में शामिल की गई थी।

नई दिल्ली में सेमिनार में 'टेक्निकल पेपर्स का एक सार संग्रह' रिलीज करते नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह (बीच में), पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा और फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी। एएनआइ

बांबे हाई कोर्ट ने गडकरी और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

नागपुर, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नितिन गडकरी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को करेगा।

जस्टिस एएस चंदूरकर की एकल पीठ ने यह नोटिस कांग्रेस नेता नाना पटोले, वंचित बहुजन अगाड़ी (वीबीए) प्रत्याशी मनोहर डबरेस और एक अन्य नफीस खान की याचिका पर जारी किए हैं। इन लोगों ने चुनावा प्रक्रिया के दौरान धांधली का आरोप लगाया है। बता दें कि पटोले और डबरेस लोकसभा चुनाव में गडकरी के खिलाफ प्रत्याशी थे। चुनावों में गडकरी ने पटोले को 1.97 लाख वोटों से हराया था। पटोले ने दावा किया कि राज्य चुनाव आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जबकि डबरेस ने आरोप लगाया है कि मतदान के दौरान खराब ईवीएम का प्रयोग किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की बात सुनने के बाद जस्टिस चंदूरकर ने गडकरी, चुनाव आयोग और जिलाधिकारी (उस समय के नागपुर के रिटर्निंग अधिकारी) को नोटिस जारी करके आरोपों पर हलफनामा दायर करने को कहा है।

पायल तड़वी केस में सुनवाई की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग

- बांबे हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग को आवश्यक इंतजाम करने का दिया निर्देश

मुंबई, एएनआइ: डॉ. पायल तड़वी खुदकशी मामले में गिरफ्तार की गईं तीनों महिला डॉक्टरों की जमानत याचिका पर सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। गुरुवार को इस संबंध में बांबे हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री विभाग को व्यवस्था करने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीएस नायडू ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) की धारा 15 (ए) (10) में कहा गया है कि इस मामले में सभी प्रकार की कार्यवाही का संबंधित अदालत द्वारा वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

इस प्रावधान का उल्लेख पायल की मां की तरफ से पेश वकील गुनारतन सदावर्ते ने कोर्ट के समक्ष किया था। सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे ने इसे नीतिगत मामला बताया जबकि आरोपियों की पैरवी कर रहे वकील अबाद पोंडा ने कहा कि यह प्रावधान केवल मुकदमे की कार्यवाही के लिए है, न कि जमानत की सुनवाई के लिए। इस पर जस्टिस नायडू ने कहा कि कार्यवाही का मतलब सभी न्यायिक कार्यवाही से है। जस्टिस नायडू ने कहा कि मैं वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। हालांकि मैं इस तथ्य से अच्छी तरफ वाकिफ हूं कि इस प्रक्रिया से आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई में देरी होगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाए।

बता दें कि अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पायल मुंबई के बीवाईएल नायर हास्पिटल में परास्नातक की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसी अस्पताल में डॉ. भक्ति मेहरे, डॉ. हेमा आहूजा और डॉ. अंकिता खंडेलवाल उसकी सीनियर थीं। आरोप है कि तीनों डॉक्टर उस पर जातीय टिप्पणी करती थीं, इससे व्यथित होकर 23 मई को पायल ने अपने छात्रावास के कमरे में खुदकशी कर ली। परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने 29 मई को तीनों महिला डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया था।

राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र कर गांव की गलियों में घूमाया

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में राजसमंद जिले की ओडन ग्राम पंचायत में एक विधवा महिला के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके बाद उसको निर्वस्त्र कर गांव की गलियों में घुमाया। फिर घसीटते हुए अपने घर में ले जाकर बंद कर दिया गया। सूचना मिलने पर नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजसमंद के पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया और तीन महिलाओं सहित अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, लज्जाभंग और जातिगत अपमान का मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार ओडन में कीर समाज की युवती को पीड़िता का बेटा (गमेती समाज का युवक) घर से भगाकर ले गया था। युवती के परिजनों ने नाथद्वारा पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। युवती का 15 दिन तक पता नहीं चलने पर उसके परिजनों ने आरोपित युवक की विधवा मां से उसके बेटे के बारे में जानकारी मांगी। इन्कार करने पर न मारपीट की और निर्वस्त्र कर गलियों में घुमाया भी।

आगरा के चर्च में छापेमारी, भागे बिशप और सचिव

जासं, प्रयागराज : अरबों के जमीन घोटाले की जांच कर रही प्रयागराज सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने गुरुवार को आगरा के एक चर्च में छापेमारी की। हालांकि, वहां मौजूद आरोपित पकड़ में नहीं आए। छापेमारी के दौरान चर्च के बिशप और सचिव वहां से भाग निकले। इंडियन चर्च ट्रस्ट्रीज डायोसिस ऑफ लखनऊ के अधीन आने वाली 100 अरब की जमीन बेचकर पैसे हड़पने का मुकदमा पिछले हफ्ते सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया था। डायोसिस ऑफ लखनऊ के मेट्रो पॉलिटन चर्च ऑफ इंडिया के बिशप जॉन अगस्टीन की शिकायत पर लिखे गए केस में पीसी सिंह, पीसी मरांडी, पीके समंतो राय, एल्वान मसीह, जयंत अग्रवाल, पाल दुपहरे, पीपी हाविल, पीटर बलदेव, सुरेश जेकब, राजीव चंद, एआर स्टीफन, एच आर मल, मार्विन मेसी, प्रेम मसीह, अशोक विश्वास, प्रबल दत्ता, शशि प्रकाश और अन्य अज्ञात पर ट्रस्ट की जमीनों को फर्जी तरीके से बेचकर अरबों रुपये का बंदरबांट करने का आरोप है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क बताएगा दिल्ली में है कितना वायु प्रदूषण

जागरण संवाददाता, कानपुर

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आइआइटी ने एक कदम और बढ़ाया है। सेंसर युक्त प्रदूषण मापक यंत्र बनाने के बाद आइआइटी कानपुर अब दिल्ली के वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी) का नेटवर्क विकसित करने जा रहा है। इसके लिए दूरसंचार उपकरण बनाने वाली स्वीडन की कंपनी एरिक्सन इंडिया के साथ आइआइटी का करार हुआ है। दोनों छह महीने के अंदर यह नेटवर्क स्थापित करेंगे।

आइआइटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. सच्चिदानंद त्रिपाठी ने बताया कि हवा में घुलने वाले हानिकारक कणों का डाटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उसका विश्लेषण कर भविष्य में वायु प्रदूषण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हवा की गुणवत्ता बताने वाले ऐसे सेंसर तैयार किए जाएंगे जो पर्यावरण का डाटा बताने के साथ पीएम-1 पीएम-2.5, पीएम-10 की स्थिति बताएंगे। एरिक्सन इंडिया के प्रमुख नितिन बंसल ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बड़ा मुद्दा है।

इस पर नजर रखने की जरूरत है, जिससे इसका समाधान आसानी से किया जा सकता है। आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर इंटरनेट आफ थिंग्स आधारित नैरो बैंड सेंसर लगाए जाएंगे। ये स्वचालित सेंसर शहर में कई स्थानों पर जगहों पर लगाए जाएंगे। सेंसर एक निश्चित समय अंतराल पर प्रदूषण के स्तर का आंकड़ा व उसके कारण भी बताएंगे।

भविष्यवाणी के लिए मॉनीटरिंग सेंसर : आइआइटी प्रोफेसर डॉ. सच्चिदानंद त्रिपाठी ऐसे मॉनीटरिंग सेंसर विकसित कर चुके हैं जो पीएम-2.5, पीएम-10 के साथ ओजोन व नाइट्रोजन ऑक्साइड का डाटा भी रिकार्ड कर सकते हैं। इसके जरिए साल भर में रिकार्ड डाटा का विश्लेषण कर प्रदूषण की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका ट्रायल चल रहा है।

इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के तहत कानपुर में ऐसे आधुनिक सेंसरयुक्त 60 मॉनीटरिंग सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। यह मशीन लर्निंग के तहत काम करेगी जिससे दिन में कई बार रिकार्ड डाटा की मदद से दूसरे दिन के प्रदूषण की स्थिति बताई जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणविद् व आइआइटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को प्रिंसिपल इंवेस्टीगेटर नियुक्त किया गया है।

पत्नी के रहते दूसरी शादी की, आइआरएस अफसर को देने होंगे 50 लाख

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में आइआरएस (भारतीय राजस्व सेवा) अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना महंगा पड़ा। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को त्रिपाठी को पहली पत्नी अपर्णा त्रिपाठी को छह सप्ताह के अन्दर बतौर क्षतिपूर्ति 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की दूसरी पत्नी एडीएम श्वेता मिश्रा को भी दो सप्ताह के अन्दर अपर्णा को 10 लाख रुपए देना है।

आरोप है कि इस आइआरएस अधिकारी ने अपनी पहली पत्नी अपर्णा त्रिपाठी के रहते हुए श्वेता मिश्रा से विवाह कर लिया। यह घटना तब की है, जब श्वेता छपरा में डिप्टी कलेक्टर पदस्थापित थी। इस घटना के पूरे मामले की जांच हुई। श्वेता को कार्मिक एवं सुधार विभाग द्वारा जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। इस बर्खास्तगी के आदेश को उन्होंने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई। हालांकि, कोर्ट पहले ही श्वेता की बर्खास्तगी को असंवैधानिक बता चुकी है। इस आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।

खाप पंचायत ने अनुसूचित जाति के परिवार का किया बहिष्कार

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान में चूरू जिले के गिरवरसर गांव के अनुसूचित जाति का एक परिवार पानी को तरस गया है। दरअसल, खाप पंचायत के फरमान पर उसका बहिष्कार कर दिया गया है। ऐसे में परिवार ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इसमें उसने कहा है कि गांव में लोग आटा चक्की पर उसका आटा नहीं पीसते। परिवार के सदस्यों को किसी भी घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इतना ही नहीं सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हें पानी भी निकटवर्ती गांवों से मंगवाना पड़ता है।

ज्ञापन में पीड़ित टोडरमल वाल्मीकि व उसके पुत्र राधेश्याम वाल्मीकि ने कहा है कि वर्ष 2017 में नौ अप्रैल को खाप पंचायत बुलाकर माइक से गांव में ऐलान करा दिया गया था कि हमारे परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। इसलिए इनसे कोई व्यवहार न रखे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अब हमारे घर के सदस्यों से गांव में कोई बोलचाल नहीं करता है। इसके साथ ही अगर गांव का कोई व्यक्ति हमारे परिवार से व्यवहार करता है तो उसके लिए 11 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है ज्ञापन में पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने व सामाजिक प्रतिष्ठा से परिपूर्ण जीवन वापस दिलाए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है।

बहिष्कार का कारण भी नहीं बता रहे

पीड़ितों का कहना है कि वह खाप पंचायत के प्रमुख लोगों से बहिष्कृत करने का कारण कई बार जानने का प्रयास कर चुके, लेकिन वह लोग बात करने को तैयार नहीं है।

किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिला कलेक्टर से मामले की रिपोर्ट मंगवाएंगे।

- भंवरलाल मेघवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 26 जुलाई 2019

दैनिक जागरण
समाधान के लिए जरूरी है कि पहले हम समस्या को समझें

विशेष अदालतों का गठन

बाल यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देकर सही किया कि उन जिलों में विशेष अदालतों का गठन करके ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाए जहां इस तरह के सौ से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कहना कठिन है कि ऐसे जिले कितने हैं, लेकिन इसे लेकर संदेह नहीं कि बालक-बालिकाओं से दुष्कर्म की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसे इस आंकड़े से अच्छे से समझा जा सकता है कि इसी वर्ष एक जनवरी से 30 जून तक देश भर में बच्चों से दुष्कर्म की 24 हजार से अधिक घटनाओं को एफआइआर के रूप में दर्ज किया जा चुका है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के खर्च पर गठित होने वाली विशेष अदालतें साठ दिन के अंदर काम शुरू कर दें इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि ऐसा होगा, लेकिन उचित यह भी होगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये अदालतें फैसले देने में तत्परता का परिचय दें। यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि हर बार विशेष अदालतें भी धीमी गति से काम करती हुई दिखती हैं। निःसंदेह यह भी आवश्यक है कि निचली अदालतों के फैसलों की सुनवाई में देर न हो। इन मामलों का अंतिम स्तर पर जल्द निस्तारण करके ही यौन अपराधियों को कोई सही संदेश दिया जा सकता है।

कई राज्यों ने बाल दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान कर रखा है। इसका उद्देश्य कठोर दंड के जरिये दुष्कर्मी तत्वों के मन में भय का संचार करना है। इसकी जरूरत केंद्र सरकार ने भी महसूस की और इसीलिए यौन उत्पीड़न से बच्चों को संरक्षण देने वाले अधिनियम अर्थात पोक्सो को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों से दुष्कर्म के गंभीर मामलों में फांसी की भी सजा दी जा सकती है। इसके पहले दुष्कर्म रोधी कानून को भी संशोधित कर मौत की सजा का प्रावधान किया जा चुका है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश को दहलाने वाले निर्भया कांड के गुनहगारों को दी गई फांसी की सजा पर अमल अभी तक नहीं हो सका है। कठोर कानूनों का महत्व तभी है जब उन पर अमल भी किया जाए। यह केवल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र अथवा राज्यों सरकारों के लिए ही नहीं समाज के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है कि बाल दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोशिश केवल इसकी ही नहीं होनी चाहिए कि बाल दुष्कर्म के दोषियों को जल्द सजा मिले, बल्कि इसकी भी होनी चाहिए कि ऐसे घृणित अपराध होने ही न पाएं।

राज्य के नाम की खातिर

पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करना चाहती हैं। पिछले वर्ष इस बाबत विधानसभा में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव भी पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार नाम परिवर्तन को तैयार नहीं है। इसका एक उदाहरण बुधवार को तब देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा-'किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत होती है। फिलहाल इस मामले में संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।' वहीं नाम बदलने की मांग को लेकर बुधवार को ही तृणमूल के 12 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग की। राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ'ब्रायन के मुताबिक पहले से ही पश्चिम बंगाल की सीएम केंद्र सरकार को इस बारे में 2011 से 2019 तक कई बार लिख चुकी हैं। जुलाई में ही गृह मंत्रालय ने सदन की बैठक में जवाब में कहा था कि नाम बदलना संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। वहीं तृणमूल का कहना है कि ये टालने वाली बात हो गई है, क्योंकि उसको भी पता है कि ओडिशा की ही तरह इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। अब पार्टी चाहती है कि इसी सत्र में या फिर अगले सत्र में इस संशोधन को लाया जाए। दरअसल बंगाल विधानसभा में पहले ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो चुका है। राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की थी कि संसद के मानसून सत्र में ही पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला किया जाए। 26 जुलाई, 2018 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया था, परंतु आज तक नाम परिवर्तन नहीं हो सका है। पिछले वर्ष पहली बार प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। इससे पहले भी दो बार प्रस्ताव केंद्र को विधानसभा में पारित कर भेजा जा चुका है। ममता चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल नाम बदल जाए, पर केंद्र की भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं।

26 जुलाई, 2018 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया था, परंतु आज तक नाम परिवर्तन नहीं हो सका है

कारगिल संघर्ष के सही सबक

सी उदयभास्कर

ऐसी उम्मीद थी कि कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों से बेहद जरूरी खुफिया सुधारों की राह खुलेगी, लेकिन बीते 20 वर्षों में ऐसा हो नहीं पाया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में देश कारगिल में शहीद हुए सैनिकों का पुण्य स्मरण करने जा रहा है। इस अवसर पर देश उन सभी सैनिकों को भी याद करेगा जिन्होंने आजादी के बाद से ही तिरंगे की आन-बान-शान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 26 जुलाई की तारीख का खास महत्व है। कारगिल में इसी दिन भारत को निर्णायक जीत हासिल हुई थी जब हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूरी तरह खदेड़ दिया गया था। मोदी सरकार की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उसने देश को एक नेशनल वार मेमोरियल यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की सौगात दी है। यह काफी समय से लंबित था। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास बने इस स्मारक में 16 दीवारों पर 35,942 सैनिकों के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं। यह बीते 72 वर्षों में देश के लिए भारतीय फौजियों के मानवीय बलिदान को श्रद्धांजलि है। इनमें कारगिल के वीर शहीदों के नाम भी शामिल हैं जो भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य एवं साहस के प्रतीक हैं।

शहीदों की स्मृति में तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए की गई पहल सर्वथा उचित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव अभियान में भी जिस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया उससे भी इस पहलू के राजनीतिक निहितार्थ प्रत्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही युद्ध स्मारक का निर्माण सुनिश्चित किया। इसी वर्ष 25 फरवरी को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था। यहां मोदी इसलिए भी सराहना के पात्र हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसे युद्ध स्मारक की मांग तबसे हो रही थी जब सत्ता के शीर्ष पर नेहरू विराजमान थे। इंडिया गेट जैसा प्रभावशाली स्मारक ब्रिटिश राज में शहीद होने वाले उन जवानों की स्मृति में बना था जिन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। सैनिकों की बहादुरी और पराक्रम की अपनी सर्वव्यापी स्वीकार्यता है, लेकिन इसके राजनीतिक आवरण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र भारत के लिए अपने युद्ध स्मारक की आवश्यकता स्पष्ट थी, लेकिन भारतीय परिदृश्य में शुरुआती दशकों की प्राथमिकताएं अलग थीं। नेहरू के दौर में राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य कमांडरों के बीच अपेक्षाकृत नाजुक संबंधों का भी इसमें योगदान था। 1962 में चीन के साथ युद्ध और कृष्णा मेनन प्रकरण ने भारत का मनोबल तोड़ दिया था। इसका परिणाम यह निकला कि भारत को अपना पहला युद्ध स्मारक हासिल करने के लिए 55 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

कारगिल शहीदों का स्मरण जहां भावनात्मक रूप से मर्मस्पर्शी है, लेकिन इसका एक व्यापक संस्थागत औचित्य भी है जिस पर ध्यान दिए जाने की दरकार है। कारगिल संघर्ष वास्तव में भारत के प्रतिरक्षा प्रबंधन में अक्षमता का परिणाम था। तब यही माना गया कि भारत इससे 'अवाक' रह गया था और एक आक्षेप यह लगा कि 'चौकीदार' लापरवाह था या फिर गायब।

इससे पहले 1962 में जब चीनी सेना ने भारत का मानमर्दन किया और फिर नवंबर 2008 में पाकिस्तान प्रायोजित निर्मम आतंकियों के जत्थे ने मुंबई में हिंसा का जैसा क्रूर चेहरा पेश किया तो दोनों ही मामलों में एक जैसी बातें की गईं। उनका सार यही था कि दुश्मन भारत को ऐसे वक्त में चौंकाने में सक्षम हुआ जब देश की खुफिया सूचनाएं जुटाने और उनके आकलन की क्षमता स्तरीय नहीं थी। कारगिल संघर्ष के बाद वाजपेयी सरकार ने के. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। वह मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता थे जिन्हें भारतीय सामरिक नियोजन का पितामह कहा जाता है। सुब्रमण्यम समिति के गठन का उद्देश्य उन कारणों की पड़ताल करना था जिनके चलते कारगिल में युद्ध जैसी स्थिति बनी। इस समिति को यह जिम्मा भी सौंपा गया कि भविष्य में ऐसे सैन्य टकराव टालने के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है? इसमें चार विशेष श्रेणियां चिन्हित की गईं और तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया। उनमें खुफिया विभाग एक प्रमुख मसला था। दुर्भाग्यवश अमेरिका में 9/11 हमला और संसद पर आतंकी हमले के चलते जरूरी सुधार ठंडे बस्ते में चले गए और मनमोहन सिंह सरकार की प्राथमिकताएं कुछ अलग थीं।

यह एक हकीकत है कि बीते 20 वर्षों के दौरान संसद में कारगिल संघर्ष के बाद जरूरी समझे जाने वाले सुधारों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई और हालिया चर्चा में भी खुफिया सुधारों की जरूरत पर ही बात हुई। भारत को खुफिया ब्यूरो यानी आइबी औपनिवेशिक परंपरा से विरासत के रूप में मिली और 1966 तक यही देश की इकलौती प्रमुख खुफिया एजेंसी बनी रही। 1966 में बाहरी खुफिया जरूरतों के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की गई। आरएन काउ भारत की खुफिया इकाई के सबसे मशहूर जासूस मुखिया माने जाते हैं। उनका प्रभाव इतना था कि उनके शुरुआती शागिर्दों को 'काउ-बॉयज' तक कहा गया। बी रमन भी उनमें से एक थे जिनके साथ मेरा लंबा पेशेवर जुड़ाव रहा। रमन देश के सबसे काबिल खुफिया अधिकारियों में से एक थे और खुफिया तंत्र की कमियों से भलीभांति परिचित भी। बीते कई दशकों के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने खुफिया तबके की पेशेवर क्षमताओं को कुंद किया है। इसमें आइबी का काम मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने तक सीमित हो गया है। पेशेवर प्रतिबद्धता के अभाव और कमजोर नेतृत्व के चलते आइबी और रॉ क्षेत्राधिकार को लेकर कड़वाहट भरे संघर्ष में उलझकर रह गई हैं। ऐसी उम्मीद थी कि कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों से बेहद जरूरी खुफिया सुधारों की राह खुलेगी, लेकिन बीते 20 वर्षों में ऐसा हो नहीं पाया। खुफिया सुधारों के आलोक में रमन की यह टिप्पणी खासी उल्लेखनीय है कि 'किसी संकट के आधार पर समीक्षा में अतीत की ही पड़ताल होती है कि आखिर क्या गलत हुआ और उसे कैसे रोका जा सकता था? वहीं आवश्यकता के आधार पर होने वाली समीक्षा भविष्योन्मुखी होती है। इसमें भविष्य की जरूरतों के लिहाज से आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।'

अफसोस कि कारगिल के दो दशक बाद भी भारत के नाजुक खुफिया ढांचे को दुरुस्त करने को कोई ठोस कवायद नहीं हुई है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कारगिल की स्मृति में कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद मोदी-शाह-डोभाल की तिकड़ी इस मोर्चे को प्राथमिकता के आधार पर साधेगी। रमन इससे खासे कुपित रहते थे कि हमारे नीति निर्माता खुफिया क्षमताओं में सुधार के बजाय उन्हें और बिगाड़ रहे हैं। अब इस पर विराम लगाकर वास्तविक सुधारों की शुरुआत होनी चाहिए।

(लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक एवं सोसायटी फॉर पालिसी स्टडीज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

राम नाम को बांटने की कोशिश

प्रो. निरंजन कुमार

इससे विचित्र और कुछ नहीं कि जिस बंगाल में सबसे अधिक राम कथाएं रची गईं वहीं राम को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है

सांस्कृतिक विमर्श कैसे राजनीति का शिकार हो सकते हैं, इसकी एक मिसाल है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का बयान। इसकी दूसरी मिसाल है 49 बुद्धिजीवियों की वह चिट्ठी जिसमे असहिष्णुता, भीड़ की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जयश्रीराम नारे के सहारे हिंसा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कटु आलोचक सेन का कहना था कि जय श्रीराम बंगाली संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है और रामनवमी पूजा का बंगाल से खास संबंध नहीं। इस वक्तव्य के पार्श्व में बंगाल में चल रही ममता बनर्जी और भाजपा में शह-मात की राजनीतिक लड़ाई है, जो एक सांस्कृतिक युद्ध में बदल गई है। यहां विवाद का सांस्कृतिक-भूगोल बंगाल तो है, लेकिन विमर्श का परिप्रेक्ष्य बंगाल से निकलकर अखिल भारतीय हो गया है। सर्वप्रथम बंगाल और राम के संबंध को ही देखा जाए। राम को बंगाल के बाहर का अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंदीभाषी क्षेत्र का सांस्कृतिक पुरुष बताया जा रहा है, लेकिन यह जानना प्रासंगिक होगा कि भारतीय आर्यभाषा परिवार की भाषाओं में संस्कृत-अपभ्रंश के बाद सबसे पहली रामायण बंगाल में ही रची गई। बांग्ला में 'कृत्तिवास रामायण' या 'श्रीराम पांचाली' की रचना पंद्रहवीं शताब्दी के बंग-भाषा के आदिकवि कृत्तिवास ने की थी। तुलसीदास के 'रामचरित मानस' से लगभग सौ वर्ष पूर्व 'कृत्तिवास रामायण' लिखी जा चुकी थी। वाल्मीकि कृत 'रामायण' से प्रभावित होते हुए भी कृत्तिवास ने उसे कैसे बंगाली संस्कृति के अनुरूप ढाला, यह इससे स्पष्ट होता है: 'जब रावण से युद्ध करते समय श्रीराम निराश हो रहे थे तब राम ने शक्ति (दुर्गा) की आराधना की और रावण पर विजय पाई।'

कृत्तिवास द्वारा राम की शक्ति पूजा की कथा को बाद में अन्य भाषाओं के साहित्य में भी चित्रित किया गया। दुर्गा या राम को लेकर जो सांस्कृतिक अथवा वैचारिक भेद की दीवार खड़ी की जा रही है उसके पीछे कई वजहें हैं। एक तो प्रत्यक्ष कारण है-राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। दूसरा कारण है भारतीय चिंतन-दर्शन की आधी-अधूरी समझ, जिसमें विभिन्न देवी-देवताओं को अलग खांचों में बांटकर देखा जाता है। यह पश्चिम के एकेश्वरवादी चिंतन का प्रभाव है जो वैष्णव (विष्णु-राम-कृष्ण के आराधक), शाक्त (शक्ति या दुर्गा के उपासक) और शैव (शिव-पूजक) को एक-दूसरे का विरोधी तक मानते हैं। जबकि तुलसीदास ने लिखा है कि 'शिवद्रोही मम दास कहावा, सोई नर मोहि सपनेहु नहीं भावा।' अर्थात राम कहते हैं कि जो शिव का द्रोही है, वह मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है चाहे वह मेरा दास क्यों न हो।

उत्तर भारतीय जिस भाव से राम की पूजा करते हैं उसी श्रद्धा से कोलकाता के दक्षिणेश्वर में काली, गुवाहाटी में कामाख्या या जम्मू में वैष्णो देवी (सब दुर्गा के ही रूप) की आराधना करते हैं। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने तुलसी के आविर्भाव से पहले ही बंगाल में 'हरे रामा-हरे कृष्णा' को गुंजायमान कर दिया था। तब राम क्या सिर्फ उत्तर भारत के हैं? यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि तमिलनाडु के नेताओं-बुद्धिजीवियों ने भी कुछ इसी तरह का सवाल उठाया था। अयोध्या के श्रीराम ईश्वर तो हैं ही, लेकिन इसके अतिरिक्त वह एक सांस्कृतिक पुरुष भी हैं जिनसे पूरा भारत युगों-युगों से प्रभावित हुआ है। सभी क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों के लोगों ने अपने-अपने तरीके से अथवा रामकथा रची है। वाल्मीकि की 'आदि रामायण' के बाद व्यास रचित महाभारत में भी 'रामोपाख्यान' के रूप में यह कथा वर्णित हुई है। बौद्ध परंपरा में श्रीराम से संबंधित 'दशरथ जातक', 'अनामक जातक' और 'दशरथ कथानक' नामक तीन जातक कथाएं उपलब्ध हैं। जैन साहित्य में रामकथा संबंधी कई प्रमुख ग्रंथ हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में हिंदी में 11, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12 और उड़िया में 6 रामायणें मिलती हैं। सबसे अधिक रामायण बंगाल में ही रची गईं। इसके अतिरिक्त गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, कश्मीरी, उर्दू, अरबी, फारसी, संथाली आदि भाषाओं में भी रामकथा लिखी गई है। पिछड़े-दलित और आदिवासियों ने भी राम को अपनी रचना का विषय बनाया। यही नहीं मुस्लिम रचनाकारों में भी श्रीराम लोकप्रिय रहे। अमीर खुसरो ने तुलसीदास से 250 वर्ष पूर्व लिखा 'वो हम सब का मालिक राम' तो तुलसी के समकालीन रहीम राम के आदर्श को नमन करते हुए लिखते हैं 'रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण/हिंदुआन को वेद सम, यवनहीं प्रकट कुरान'। 1623 में सादुल्ला मसीह की 'दास्ताने रामो-सीता' फारसी-भाषी जनता में लोकप्रिय हुई। इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपियां ब्रिटिश इंडिया म्यूजियम, एशियाटिक सोसायटी बंगाल आदि में सुरक्षित हैं। इकबाल जैसे शायर ने तो यहां तक कहा कि हिंद का प्याला सत्य से भरा हुआ है और जितने भी दार्शनिक मगरिब (पश्चिम) में हुए हैं, वे भारत के श्रीराम का विस्तार हैं।

विदेशों में भी 'तिब्बती रामायण', पूर्वी तुर्किस्तान की 'खोतानी रामायण', इंडोनेशिया की 'काकविन रामायण', जावा का 'सेरतराम', 'सैरीराम', 'रामकेलिंग', 'पातानी रामकथा', इंडो-चीन की 'रामकेर्ति', 'खमैर रामायण', म्यांमार की 'यूतोकी रामयागन', थाईलैंड की 'रामकियेन' आदि रामचरित्र का बखूबी बखान करती हैं। स्पष्ट है कि श्रीराम वह सांस्कृतिक पुरुषोत्तम हैं जो देश-काल से परे हैं। श्रीराम जिन जीवन मूल्यों, आदर्शों, मर्यादा और सामाजिक समरसता की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करते हैं वे भारतीयों के जीवन-संस्कृति में रचे-बसे हैं। इसीलिए हर भारतीय अपनी 'राम-कहानी (जीवन कथा)' सुनाता है। मिलने-जुलने पर 'राम-राम' या 'जय रामजी की' कहना एक धार्मिक अभिवादन के बजाय एक सांस्कृतिक-लौकिक अभिवादन है। 'जय श्रीराम' इसी की एक कड़ी है जो पॉपुलर कल्चर की देन है और रामायण सीरियल के माध्यम से आम जनमानस में और फैली। निःसंदेह जो कुछ अतिपंथी 'जय श्रीराम' के नाम पर हिंसा कर रहे हैं वे प्रभु श्रीराम का अपमान और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

जेएनयू के पूर्व शोधार्थी साकिब सलीम (2017) सही लिखते हैं कि 'हमें यह समझने की जरूरत है कि श्रीराम केवल हिंदू धर्म के भगवान नहीं हैं, बल्कि इस मिट्टी की धरोहर हैं। धरोहर को बांटना न तो मुमकिन है और न अक्लमंदी'। तथाकथित सेक्युलरिस्ट बुद्धिजीवियों और अतिवादियों को यह बात समझ लेनी चाहिए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय का महत्व

जीवन पल-पल के सौम्य धागों से बुना हुआ है। इसलिए समय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा अहसास होता है कि समयबद्ध जीवनशैली ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। अतः समय से संघर्ष करने वाला ही महान बनता है। कहा जाता है कि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सेना नायक को भोजन के लिए आमंत्रित किया। समय पर पहुंचने में उन्हें कुछ विलंब हो गया। नेपोलियन भोजन करने लगे। वह खाना समाप्त करके उठ ही रहे थे कि वह आ गए। उन्हें देखकर नेपोलियन ने कहा, 'भोजन का समय बीत चुका है, आइए अब अपना काम शुरू करें।' जाहिर है समय की महत्ता का पालन कर ही उन्होंने उच्च पद और लोकप्रियता अर्जित की। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है।

ग्लैडस्टोन सरीखे प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा अपनी जेब में एक छोटी-सी पुस्तक लेकर निकलते थे। उन्हें चिंता रहती थी कि कहीं कोई घड़ी व्यर्थ न चली जाए। उनके लिए समय अमूल्य धन था। वैसे धन मनुष्य कृत संचय होने के कारण इसे चोर चुराकर तो ले जा सकता है, परंतु समय ईश्वर प्रदत्त संपत्ति होने के कारण चोर इसे चुरा नहीं सकता। इसलिए हमें भी प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी विद्वान ने इस संदर्भ में उचित ही कहा है कि अतीत भविष्य की प्रयोगशाला है। अतीत में हुई अपनी कमियों एवं गलतियों से सबक लेने और भविष्य में उसे न दोहराने का प्लेटफॉर्म वर्तमान है। इसी को लक्षित करते हुए खलील जिब्रान ने कहा है, 'बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न है।'

अतः वर्तमान हमारे पास है। इसलिए प्रत्येक पल का सदुपयोग जीवन की सतह पर इस तरह आनंद से व्यतीत करना चाहिए, जिस प्रकार हरित पर्ण पर ओस की बूंदें नृत्य कर रही हों। जो समय चिंता में गया समझो कूड़ेदान में गया। जो समय चिंतन में गया समझो तिजोरी में जमा हो गया। अतः समय ही संपत्ति है, शृंगार एवं अमृततुल्य है। इसी के द्वारा हम जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। मार्क ट्वेन का कहना है कि हमें जो सबसे बहुमूल्य वस्तु मिली है, वह है समय। अतः उसे किफायत से खर्च करना चाहिए।

देवेंद्रराज सुथार

गंगा नहीं रहेगी तो देवी गंगा का क्या होगा

गोमुख हिमनद गंगा के जल का मुख्य स्रोत है। गंगोत्री से अठारह किलोमीटर ऊपर हिमालय में स्थित। यह हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से है, लगभग 27 घन किलोमीटर बड़ा। कुछ अध्ययन बताते हैं कि इसकी गहराई लगभग 200 मीटर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लेशियर तब बनते हैं जब लंबे समय तक हिम की परतें एक के ऊपर एक जमा हो जाती हैं। हिम की ये परतें कई सौ फुट मोटे हिमनदों का रूप ले लेती हैं। गंगोत्री हिमनद भी ऐसे ही बना होगा। हजारों वर्षों का इतिहास समेटे। मगर यहां लोगों के लिए यह सब सिर्फ किताबी बातें हैं।

कथित विकास की अंधी दौड़ में हमें टिकाऊ या सतत विकास के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। ग्लेशियर हैं तो नदियां हैं, नदियां हैं तो जल, जंगल, और मानव सभ्यता और जीवन है, लेकिन सच्चाई यही है कि गंगा के बेसिन में क्लास एक शहरों के रूप में वर्गीकृत 36 शहर नदी में जाने वाले अपशिष्ट में 96 फीसद गंदगी डालते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के किनारे बसे शहर रोजाना 2,723 मिलियन लीटर घरेलू सीवेज इस नदी में ही प्रवाहित करते हैं, लेकिन यह महज एक अनुमान है और वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह हो सकती है, क्योंकि बोर्ड का यह अनुमान शहरों में पानी की सप्लाई की मात्रा को लेकर की गई गणना पर आधारित है।

फिर से

गंगा के किनारे बसे शहर रोजाना 2,723 मिलियन लीटर घरेलू सीवेज इस नदी में ही प्रवाहित करते हैं

पर हर शहर में हैंडपंप और कुएं जैसे अलहदा साधन भी होते हैं। इस तरह गंगा में रोजाना करोड़ों लीटर सीवेज नालों के जरिए गिराया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि हमारे शहरों में इस सीवेज को उपचारित (ट्रीट) करने की क्षमता बेहद कम है। बेहद कम इसलिए, अगर हम दो तथ्यों पर ध्यान दें। पहली बात, सीवेज पैदा होने और उसके उपचार के बीच का अंतर हर साल 55 फीसद का है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि चाहे हम सीवेज ट्रीटमेंट में और अधिक क्षमता को जोड़ भी लें तो भी आबादी बढ़ोतरी की वजह से यह अंतर तो बना रहेगा।

आबादी में बढ़ोतरी और सीवेज डिस्चार्ज की वास्तविक मात्रा के अनुमान को साथ रखकर गणना की जाए तो पता चलता है कि हमारी ट्रीटमेंट की क्षमता और सीवेज उत्पादन के बीच का अंतर 80 फीसद तक बढ़ जाता है। मैदानी इलाकों में गंगा की मुख्यधारा और इसकी दो सहायक नदियों राम गंगा और काली नदी के साथ कम से कम 764 औद्योगिक इकाइयां हैं जो नदी में जहरीला अपशिष्ट उड़ेलती हैं।

गंगा के साथ दिक्कत यह है कि इसके किनारे स्थित अधिकतर शहरों में भूमिगत सीवेज सिस्टम भी नहीं हैं। खासकर प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों का 80 फीसद हिस्सा अभी भी सीवर की कवरेज में नहीं है। इन शहरों में अपशिष्ट तो पैदा हो रहा है, लेकिन वह ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंचता। नदियों को देवी के रूप में पूजने वाले देश में गोमुख के पास खड़े होकर यह सोचना कितनी पीड़ा की बात है कि यहां ग्लेशियर दिन ब दिन पीछे खिसक रहा है, और वहां मैदानों में हम अपने घरों और उद्योगों का पूरा कूड़ा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। जब नदी ही नहीं बचेगी तो देवी मान कर जिस गंगा की पूजा हम करते हैं, उसका क्या होगा?

(साभार : गुस्ताख ब्लॉग में मंजित ठाकुर)

मेलबाक्स

दल-बदल सत्तासुख का आकर्षण है

भाजपा के कांग्रेसीकरण का सवाल शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रदीप सिंह ने जिस दल-बदल की चर्चा की है वह भाजपा का कांग्रेसीकरण नहीं, अपितु सत्तासुख का वह आकर्षण है जो कांग्रेस के वर्चस्व के समय भी था और आज जब भाजपा का कमल खिल रहा है तब भी है। वस्तुतः सत्तासुख की मिठास राजनीति से जुड़े लोगों की दलीय निष्ठा को प्रभावित करती है। आज भाजपा की यही मिठास दूसरे दल के नेताओं को आकर्षित कर रही है। दरकती दलीय निष्ठा से राजनीति का जो चारित्रिक पतन हुआ है उससे आज कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। संघनिष्ठ भाजपा में भी यह वायरस है जिससे प्रभावित होकर विगत में भाजपा के एक समर्पित वरिष्ठ नेता ने सपा की लाल टोपी पहन ली थी, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ तो वह पुनः घर वापस आ गए। यद्यपि संघ प्रेरित भाजपा में अन्य दलों की अपेक्षा दल-बदल की बीमारी बहुत कम है, क्योंकि भाजपा में सक्रिय संघनिष्ठ नेता अपनी वैचारिक निष्ठा से समझौता नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे दलों से आने वाले उन नेताओं के प्रति भाजपा संगठन पर्याप्त सावधानी बरतता है, जिनका संघ शाखा से उपजी वैचारिक निष्ठा से कोई लेना देना नहीं होता। शायद इसीलिए भाजपा संगठन ऐसे नेताओं को तत्काल कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपता। भाजपा की संघनिष्ठ रीति-नीति में रच-बस जाने के बाद ही उन्हें संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भाजपा का यह स्वरूप ही उसको अन्य राजनीतिक दलों से अलग एक लोकतांत्रिक दल के रूप में स्थापित करता है। इस दृष्टि से सत्तासुख के वशीभूत अन्य दलों के नेताओं का भाजपा से जुड़ने को भाजपा का कांग्रेसीकरण बताना एक असंगत विचार है। हकीकत तो यह है कि एक परिवार के प्रति निष्ठाभाव रखने वाली कांग्रेस कभी भाजपा नहीं बन सकती और न ही अपनी संघनिष्ठ वैचारिकता से बंधी भाजपा का कभी कांग्रेसीकरण हो सकता है। भाजपा और कांग्रेस का यह विरोधाभास जगजाहिर है।

pandeyvp1960@gmail.com

इमरान का कबूलनामा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका में कबूल कर लिया कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकवादी मौजूद हैं। पुलवामा हमले को भी और उसमें जैश-ए- मोहम्मद के हाथ को भी उन्होंने कबूला। इससे भारत की बात को बल मिला है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। इमरान खान की भी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में इस बात को दिल से स्वीकार किया कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों का समूह सक्रिय है, लेकिन सिर्फ इससे ही बात नहीं बनेगी। इमरान खान को अब इन आतंकी संगठनों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि पाकिस्तान को लेकर दुनिया में जो धारणा है, वह बदले।

vijayt125@gmail.com

पाक में बढ़ती आत्महत्याएं

एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर दिन 15 से 35 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के गांवों की तुलना में शहरों में यह समस्या विकराल है। पाकिस्तानियों के अवसाद ग्रस्त होने की मुख्य वजहों में नौकरी न मिलना, नौकरी छूटना, आमदनी न होना शामिल हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी की स्थिति बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में शिक्षा की जो मौजूदा दर है उसमें 50 फीसद युवा उच्च माध्यमिक तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के बजाय पाकिस्तान आतंकवाद की खेती कर रहा है। आखिर कहां जा रहा है पाकिस्तान?

nisharathore243000@gmail.com

कैसा लोकतंत्र?

कोई सिद्धांत नहीं, कोई लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं। अपनी राजनीतिक वचनबद्धता का कोई मूल्य नहीं। दलीय चुनाव की कोई सार्थकता और औचित्य नहीं। यह सब देखने को मिल रहा है कर्नाटक में। क्या यही है लोकतंत्र? क्या इसी तरह लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? आखिर जो विधायक किसी पार्टी से चुनकर आते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ विधायक एक समूह में किसी और पार्टी के साथ खड़े दिखने लगते हैं? अगर इन्हें लगता है कि वह गलत पार्टी में हैं तो पार्टी और सदस्यता से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ें, न कि किसी और पार्टी की सरकार में मंत्री बन जाएं। ऐसे तो अयोग्य लोग मंत्री बनते रहेंगे और सुयोग्य बाहर रहेंगे।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

14 हजार की संख्या में अमेरिका की सेना मौजूद है अफगानिस्तान में, जिन पर अमेरिकी सरकार वार्षिक रूप से 36 अरब डॉलर खर्च करती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ट्रंप के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है।

आजकल

आसान नहीं आतंकी शिविरों का खात्मा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका में कई मसलों पर बेबाक राय रखी है। उन्होंने एक बड़ी स्वीकारोक्ति की है कि उनके देश में बड़ी संख्या में आतंकी शिविर हैं जिनके बारे में पूर्व सरकारों ने सही जानकारी नहीं दी है। हालांकि इससे पाकिस्तान की छवि को उन्होंने अपने तरीके से साफ-सुथरा करने की कोशिश की है, लेकिन उनके इस वक्तव्य के कई मायने हैं जिसमें प्रमुख पाक की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था है जिसे दुरुस्त करने के लिए कुछ मदद मिलने की उम्मीद से इमरान अमेरिका गए थे

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन

अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से स्वीकार किया कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकी हैं। उन्होंने इसके लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार भी ठहराया। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसे दिवालिया होने से बचने के लिए अमेरिकी मदद किसी भी हालत में चाहिए। अतः इमरान अपने देश की छवि को बचाना चाहते हैं जिस वजह से उन्होंने यह बयान दिया है।

दरअसल 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में सीआइए के नेतृत्व में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया था। इस दौर में ही पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह जिया-उल-हक ने भारत को तोड़ने के लिए एक रणनीतिक अभियान शुरू किया था। वहीं साम्यवाद के खिलाफ सीआइए के अभियान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और सऊदी अरब को सक्रिय साझेदार बनाया। तीनों ने मिलकर मुस्लिम देशों से स्वयंसेवकों का चयन, प्रशिक्षण और उन्हें हथियार देकर अफगानिस्तान भेजना शुरू किया। इसे जिहाद का नाम दिया गया और समूचे मुस्लिम संसार से कट्टरपंथी ताकतों को इस जिहाद में शामिल होने का आह्वान किया गया। यह जिहाद एक दशक तक चला और इस दौरान अमेरिका पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा। सोवियत रूस इस युद्ध में टिक नहीं पाया और उसे 1989 में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अमेरिकी मदद से मुजाहिदीनों ने एक अजेय समझी जाने वाली महाशक्ति को करारी शिकस्त दे दी थी।

इमरान खान ने अपने देश के आतंकियों के कश्मीर और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लेने का दावा तो किया है, लेकिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकी केंद्र हैं, यह स्वीकार करने से वे कन्नी काट गए। दरअसल कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता प्रभाव चिंताजनक है जिसके चलते पाकिस्तानी समाज संकीर्णता और अस्थिरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान में देवबंदी जेहादियों का ऐसा समूह बन गया है जिसे अलकायदा, तालिबान, हरकत उल अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी लाहौर में सैयद मौदूदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नामक एक संस्थान चलाता है। इसका काम इस्लामी चरमपंथियों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देना है। यहां पर सिकियांग के उइगर समेत उजबेक और तुर्क प्रशिक्षण लेते रहे हैं। चेचन्या में रूसी सेना से लड़ने वाले चरमपंथी यहीं से निकले हैं। इस्लामाबाद का इस्लामिक विश्वविद्यालय भी कट्टरपंथी ताकतों का बड़ा गढ़ है। वर्ष 1995 में इस्लामाबाद के मिस्र के दूतावास पर ट्रक बम से हमला कर 29 लोगों को मारने वाले अल-जिहाद और अलगामा अल इस्लामिया के आतंकी विश्वविद्यालय परिसर में ही रहते थे। कराची के न्यूटाउन क्षेत्र में मौलाना मोहम्मद युसूफ बिनौरी उपनगर मस्जिद क्षेत्र के जमायत-उल-उलूम-इल-इस्लामिया में दूसरे कई देशों से आए विद्यार्थी चरमपंथ और कट्टरपंथ का पाठ सीखते हैं। मुल्ला उमर समेत तालिबान के अधिकांश लड़ाके यहीं से निकले हैं।

मुजफ्फराबाद, अलियाबाद, कहुटा, हजीरा, मीरपुर, रावलकोट, रावलपिंडी समेत गुलाम कश्मीर में अनेक आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हैं। वर्ष 1993 में पाकिस्तान में बने आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार का मुख्यालय मुजफ्फराबाद में है। इसके साथ की इसका एक केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त में है। यह कश्मीर के अलावा बोस्निया और म्यांमार में भी सक्रिय है। कुख्यात आतंकी संगठन हरकत-उल- मुजाहिदीन का मुख्यालय पाकिस्तान के सेहसाणा में है। कारगिल युद्ध में पाक सेना के साथ इस आतंकी संगठन के आतंकी भी शामिल थे। हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र मुजफ्फराबाद में है। इस आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती के लिए जिहाद को केंद्र में रखकर नए रंगरूटों के लिए अखबारों में विज्ञापन सामान्य बात है।

पाकिस्तान के इन कुख्यात आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों में मसूद अजहर की खास भूमिका है। मसूद अजहर छह लाख आतंकियों की भर्ती का दावा करता है जिसमें से हजारों कश्मीर में जिहाद के लिए भर्ती किए गए हैं। इस आतंकी संगठन का तंत्र दक्षिण एशिया के साथ पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। इस संगठन का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक गोपनीय संचार केंद्र भी है। मसूद अजहर की शिक्षा कराची के एक मदरसे में हुई और 1989 में मजहबी तालीम में आलिमिया या स्नातकोत्तर की डिग्री ली। वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों और आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों पर अक्सर प्रशिक्षु जिहादियों को मजहबी तकरीर सुनाने जाता है।

कश्मीर का यह आतंकी भारत में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने लिए दुनियाभर में कुख्यात है। कट्टरपंथी विचारों वाले ऑडियो कैसेट कश्मीर घाटी में भेज कर यह युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। वर्ष 1999 में भारत की कैद से छूटने के कुछ महीनों बाद ही श्रीनगर में भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आत्मघाती हमला कर उसने अपने खतरनाक इरादों की झलक दे दी थी। 23 अप्रैल 2000 को हुए एक हमले में एक आतंकी ने विस्फोटक पदार्थों से भरी कार सेना के मुख्यालय के दरवाजे से टकरा कर कश्मीर घाटी में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी संगठनों में शुमार लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय लाहौर से 34 किलोमीटर दूर मुरीदके में है। यहां से निकलने वाले आतंकियों ने भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में कहर बरपाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने आतंकियों पर चिंता तो जताई, लेकिन जब तक वे कट्टरपंथी मदरसों और समाज पर उनके जानलेवा प्रभाव को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाते तब तक पाकिस्तान से आतंक के ढांचे को खत्म करना मुश्किल होगा। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर रहे और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अपने देश में चरमपंथ की सुरक्षित पनाहगाहों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो अमेरिका इस समस्या से अपने तरीके से निपटेगा। जाहिर है पाकिस्तान से आतंकवाद का ढांचा नष्ट करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा करने के स्थान पर स्वयं सामरिक प्रयास करने होंगे।

प्राथमिकताएं बदलने वाला अमेरिका

सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाइएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

अमेरिका की यह फितरत रही है कि वह अन्य देशों के साथ रिश्ते अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय करता है और खत्म भी करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बीते सोमवार को व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान कश्मीर पर मध्यस्थता वाली बात किसी के गले नहीं उतर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सभी अमेरिकी और भारत समेत दुनिया के कई देश जो कश्मीर मामले को अच्छी तरह से जानते हैं, वे केवल इसे भारत-पाक के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा मानते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं, आखिर वह इससे किसे खुश करना चाहते हैं। असल में कश्मीर पर निशाना लगाकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सियासी रोटी सेकने की फिराक में हैं।

गौरतलब है कि अगले साल नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होना है और ट्रंप वोट हथियाने के चलते अपने निजी एजेंडे कि- 'वे शांति के बड़े पैरोकार हैं' इस तथ्य को लेकर चतुराई भरा कदम उठा रहे हैं। जो ट्रंप पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में शांति बहाली के लिए खतरा बता रहे थे, आतंकियों का सरगना बता रहे थे, आतंकियों के नाम पर अरबों डॉलर गटकने वाला समझ रहे थे और यहां तक कहा कि पाकिस्तान ने बरसों से अमेरिका को बेवकूफ बनाया और आतंकियों का कारोबार करता रहा। और अब उसी पाकिस्तान को अपनी प्राथमिकता के आधार पर नया रंग दे रहे हैं।

अफगानिस्तान में 14 हजार अमेरिकी सेना वर्तमान में मौजूद है जिन पर सालाना खर्च 36 अरब डॉलर होता है। ट्रंप अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं और यह उनके चुनावी एजेंडे में भी था। और ऐसा पाकिस्तान की मदद से ही संभव है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ उनकी नरम और बदली परिस्थिति का कारण भी है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों अत्यंत खराब अर्थव्यवस्था के दौर से जूझ रहा है और उस पर यह आरोप है कि वह दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी दौरे में ही कहा है कि वे यहां कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं आए हैं। इमरान खान यह भी कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका के भीतर 30 से 40 आतंकी नेटवर्क सक्रिय हैं जिनमें 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं। बावजूद इसके अमेरिका कोई कठोर कदम उठाएगा, ऐसी स्थिति फिलहाल दिखती नहीं है। कुछ दिनों पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को छह अरब डॉलर कर्ज देने के लिए तैयार हुआ। संभव है कि यह बिना अमेरिका की सहमति के नहीं हुआ होगा। अमेरिका तो अपने निजी हितों को साधने की फिराक में पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है। चीन के साथ उसका ट्रेड वॉर अभी थमा नहीं है और भारत द्वारा बढ़ाई गई ड्यूटी के साथ रूस से एस-400 की खरीदारी भी उसके गले नहीं उतर रही। यहां भी कूटनीतिक संतुलन के चलते पाक के साथ अच्छा रवैया रखने का उसके पास बड़ी वजह है।

20 जनवरी 2017 से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी कुछ-कुछ झूठ वाली छवि पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन भारत को तो इन सबसे सावधान रहना ही होगा। मुख्यतः कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के ऊल-जलूल बयान से तो बिल्कुल किनारा करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि इस सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हो सकती है। इसके अलावा भारत-अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू' की वार्ता भी आयोजित होने की संभावना है। जाहिर है बयान का इस पर असर होगा। फिलहाल सवाल है कि क्या ट्रंप का बदला हुआ रुख इमरान के पक्ष में है। यदि अफगानिस्तान से सेना बाहर निकालने की यह ट्रंप की रणनीति है, तो इसका खुलासा तभी होगा जब तालिबान के साथ शांति वार्ता सफल होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका इस प्राथमिकता से बाहर निकल कर अपने नए निजी हित की खोज में आगे बढ़ेगा। स्पष्ट है कि पाक के प्रति उसका पहले गरम और अब नरम रुख उसकी अवसरवादिता है और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी भी है।

खरी-खरी

मैं नहीं बदला, मुझे बदल डाला

मोहनलाल मौर्य

'आप बदल गए हैं।' यह पत्नी का कहना था। घर में रहना है, तो पत्नी के कथन में हां में हां और ना में ना मिलाना ही पड़ता है। नहीं मिलाएं तो तू-तू, मैं-मैं होगा। इस सबसे तनाव होगा। तनाव होगा तो खींचतान होगी। खींचतान होगी तो प्रेम का धागा टूटेगा। एक बार धागा टूट गया तो वापस जोड़ने के लिए फिर गांठ ही लगती है। कई ऐसे भी धागे होते हैं, जिनमें गांठ भी नहीं लगती। उनकी कोर्ट में पेशी लगती है। अधिकांश पेशियों का परिणाम वही तीन बार बोलने वाला कुछ होता है, जिसके पीछे आजकल सरकार पड़ी है।

मुझमें ऐसा क्या बदलाव आ गया, जो मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा और पत्नी को दिख रहा है! न मोटा हुआ हूं, न दुबला। न स्वभाव बदला है, न रंग-रूप। मूंछें भी नापकर ही कटवा रहा हूं। सोचा पत्नी से ही पूछ लेता हूं। सो मैंने पूछ ही डाला।

वह बोली, 'देखिए जी! कई दिनों से देख रही हूं कि...'

मैंने बीच में ही टोक दिया, 'क्या देख रही हो?' वह फिर बोली, 'यही कि आप बदल गए हैं।'

अब मेरा गुस्सा होना नैतिक रूप से जायज था, मगर पत्नी के सामने कैसी नैतिकता। नैतिकता के सारे मानदंड पत्नियों के सामने ही तो टूटते हैं! इसलिए मैंने अपना गुस्सा लोकसभा स्पीकर की तरह पीते हुए मन व झक, दोनों मारकर कहा- 'हें...हें...हें... कहां बदला हूं पगली, वैसा का वैसा तो हूं। देख जरा! वही चाल-वैसा ही बेहाल!'

मेरी नकली मुस्कराहट को उसने वैसे ही लपक कर पकड़ लिया, जैसे दीवार पर छिपकलियां मासूम मच्छरों को धप से पकड़ लिया करती हैं। मुझे गिड़गिड़ाता देख उसने तुरुप का इक्का चल दिया, 'आजकल आप बहुत खिले-खिले रहते हो!'

मैं चौंका!... और तुरंत ही बोल पड़ा, 'तुम ही तो कहती थी, सूमड़े-सट्ट मत रहा करो, थोड़ा बोला-चाला करो, लोग पीठ पीछे आपको आलोकनाथ बोलते हैं। जब तुमने इतना सब कहा था तो अपन थोड़ा हंसने-बोलने लगे।'

'हां, हंसो-बोलो, मगर इतना खुश मत रहो कि लोग मुझ पर शक करने लगें?'

इस बार मुझे अपनी सगी पत्नी, पत्नी वाले रोल में दिखाई दी। वह पत्नी ही क्या, जो पति को खुश रह लेने दे! मैं उसकी यह पीड़ा समझ गया था कि मैं उसका पति होने के बावजूद पीड़ित जैसा क्यों नहीं लग रहा था! मैंने तुरंत अपना सॉफ्टवेयर बदला। उस दिन से मैं फिर सूमड़ा-सट्ट हो गया।

ट्वीट-ट्वीट

अपमानजनक! ये नजर-नजर मिलाने की हल्की बात करके आजम खान ने न सिर्फ एक महिला सांसद और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी का अपमान किया है, बल्कि उस अभद्र सोच का इजहार किया है जो आपको पूरे होशो-हवास में मजाक के नाम पर महिलाओं के साथ बेहूदगी करने की हिमाकत देती है!

अंजना ओम कश्यप@anjanaomkashyap

सांसद आजम खान लगातार उकसाने वाली बातें करते रहे हैं और फिर भी उनकी पार्टी उनका समर्थन करती है। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि अखिलेश यादव जी ऐसी महिला विरोधी टिप्पणी का समर्थन करते हैं। इससे पार्टी नेताओं की सामंती और पुरुषवादी सोच ही जाहिर होती है।

प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

बीजू जनता दल के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी आरटीआइ संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही विपक्ष का खेल खत्म समझिए।

शोभना के@SobhanaNair

राज्यनामा
झारखंड

हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा का मानसून सत्र

झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह चौथी विधानसभा का आखिरी सत्र था और लोगों को उम्मीद थी कि सभी दल मिलकर नजीर पेश करेंगे। लेकिन स्थिति नहीं बदली। देखा जाए तो लगातार सत्रों का बाधित होना झारखंड विधानसभा की नियति बन चुकी है। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल, सदन के भीतर बात-बात पर हंगामा खड़ा करने की प्रवृत्ति सोचने पर विवश कर देती है कि आखिरकार संसदीय परंपरा किस दिशा में जा रही है? जाहिर है विपक्ष पर हल्ला-हंगामा मचाने का आरोप लगता है। लेकिन सत्तापक्ष के स्तर से सुलह-समझौते की सकारात्मक पहल होती तो स्थिति बदल सकती थी। यह सत्तापक्ष का दायित्व है कि वह सभी विधायक दलों से संपर्क कर विधानसभा की सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करे।

उल्लेखनीय है कि एक बार विवाद ज्यादा बढ़ने की वजह से तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका तर्क था कि वे विपक्षी दलों के हंगामे का समाधान निकालने में असफल रहे। ऐसे में वे पद पर बने रहना नहीं चाहते। विधायी संस्थाएं समृद्ध परंपराओं के बल पर चलती हैं। जनप्रतिनिधि अगर अपना दायित्व भूलकर सिर्फ हंगामा करें, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। दुर्भाग्य से झारखंड विधानसभा बार-बार हंगामे की भेंट चढ़ता है। यहां एक बार विधायकों ने सदन के भीतर रंगीन स्प्रे का छिड़काव तक कर दिया था। रिपोर्टर टेबल तक गिरा दिए गए थे। इसे लेकर आसन ने कड़ी कार्रवाई भी की। ऐसा लगा था कि स्थिति सुधरेगी। लेकिन विधायकों की मनः स्थिति ऐसी नहीं दिखती। मानसून सत्र चौथी विधानसभा का अंतिम सत्र था। अब जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में जाएंगे। बजट सत्र में नए चेहरे विधानसभा में दिखेंगे। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों के आचरण का आकलन जनता अगर सख्ती से करे तो सदन में हंगामे की स्थिति नहीं आएगी। जनप्रतिनिधियों को भी शुचिता का अहसास होना चाहिए ताकि सदन का बहुमूल्य समय हंगामे में बर्बाद नहीं हो।

अध्यक्ष पर सवाल : झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विवाद थमता नहीं दिखता। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि उनका इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान ने स्वीकार नहीं किया है। इधर डॉ. अजय कुमार के विरोधियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वे खुलकर सामने नहीं आते और इशारों में विरोध करते हैं। अलबत्ता उनके समर्थक नेताओं ने अवश्य डॉ. अजय कुमार के खिलाफ लॉबिंग तेज की है। कुछ नेताओं ने दिल्ली में कैंप कर भी डॉ. अजय कुमार के खिलाफ जमकर प्रचार अभियान चलाया है। इसमें उन नेताओं की भरमार है जो इस बात से आशंकित हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों की दौड़ में वे कहीं पिछड़ नहीं जाएं। इसमें गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं की तादाद ज्यादा है। यह धड़ा हर हाल में अपने साथ-साथ नजदीकी रिश्तेदारों के लिए टिकट सुरक्षित करना चाहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन नेताओं की नहीं चली थी, लिहाजा उन्होंने ज्यादा जोर नहीं लगाया था। देखना यह होगा कि प्रबल विरोध झेल रहे डॉ. अजय कुमार को कांग्रेस आलाकमान पद पर बनाए रखती है या फिर नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी।

हड़ताल से त्रस्त : झारखंड सरकार संविदा कर्मियों के आंदोलन से त्रस्त है। राज्य में केंद्रीय योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर संविदा पर नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान की बात करें या सर्व शिक्षा अभियान की। या फिर अन्य केंद्रीय योजनाओं की, संविदा पर नियुक्त सभी कर्मी लंबी सेवा तथा अपने भविष्य का हवाला देते हुए स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर धरना-प्रदर्शन से लेकर हड़ताल तक कर रहे हैं। राज्य सरकार भी इनके मामले में ठोस निर्णय लेने के बजाए सिर्फ आश्वासन देकर या फिर कमेटी गठित कर आंदोलन को टालने का प्रयास करती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा पर नियुक्त पारा शिक्षक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लगातार विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पारा शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही पारा शिक्षक पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में दो माह हड़ताल पर रहे थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई थी। इधर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत संविदा पर कार्यरत अनुबंधकर्मी भी स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये लगातार चार दिनों तक हड़ताल पर भी रहे। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के कार्यक्रम बाधित हुए। इससे पहले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत ही नियुक्त एएनएम तथा जीएनएम 17 दिनों तक राजभवन के सामने धरने पर बैठी रहीं, जिससे परिवार कल्याण पखवाड़ा, कुष्ठ- यक्ष्मा रोगी पहचान पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम बाधित हुए।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या ट्रंप के बयान पर विपक्ष द्वारा पीएम मोदी से सफाई मांगना सही है?

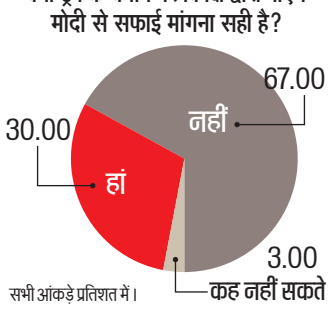

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या प्रस्तावित संशोधनों से आरटीआइ कानून कमजोर हो जाएगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चलती कैंची की तरह उनकी तेज जुबान,
परिभाषा सम्मान की भूले आजम खान।
भूले आजम खान निशाना फिर महिलाएं,
करना उन्हें लिहाज भला किस भांति सिखाएं!
करते जो अखिलेश वकालत उनकी-खलती,
राजनीति इस भांति न बबुआ बिल्कुल चलती।

- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

मुस्लिम समाज से भी विश्वास की अपेक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति जिस प्रकार से विश्वास जताया है, उसे देखते हुए मुस्लिम समुदाय को भी उनकी बातों का संज्ञान लेते हुए उनके मुताबिक आचरण करना चाहिए

प्रवीण गुगनानी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नारे 'सबका साथ सबका विकास' में एक नया शब्द जोड़ा है, सबका विश्वास। वस्तुतः कांग्रेस ने मुस्लिमों को वोट बैंक बनाया और उन्हें छद्म तुष्टिकरण करके राष्ट्र की मुख्यधारा में आने से रोके रखा। यह 'विश्वास' उस कांग्रेसी प्रवृत्ति पर विराम का प्रतीक है। मुस्लिम समाज यह जान ले कि मुस्लिम आतंकवादियों और कट्टरपंथियों व आनुपातिक रूप से अधिक अपराधियों के कारण उन पर मोदी की पहल को सिद्ध करने की जवाबदेही अधिक है। यदि मोदी ने मुस्लिम समाज का विश्वास जीतने का बीड़ा उठाया है तो मुस्लिम समाज को भी मुस्लिम आतंकियों, कट्टरपंथियों व विभाजनकारियों का बहिष्कार करना होगा।

'सबका विश्वास जीतेंगे' के नारे संग यह भी जोड़ना चाहिए है कि 'हमने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है।' विश्वास करके हम छले अवश्य गए हैं। इस देश के हिंदुओं पर मुस्लिमों द्वारा सदियों से अविश्वास करने के अभिनय से दबाव अवश्य बनाया जाता रहा है। मुस्लिमों का यही नाजायज दबाव भारत में द्विराष्ट्र की संकल्पना का कारक बना। इसी आभासी अविश्वास से कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन कर दिया गया।

मुस्लिमों का भारत पर यह अविश्वास न तो असल है न नया है, यह एक पुराना और झूठा अभिनय मात्र है! मुस्लिम समाज का कट्टरपंथी और सियासती तत्व समाज में अविश्वास के अभिनय का ताना-बाना बुनकर अपने लिए एक नया भूगोल रचना चाहता है। अविश्वास उपजने के कुछ तो कारण होते हैं। लेकिन आप यह नहीं बता पाएंगे। आप किसी भी कालखंड में किसी भी भारतीय राजा द्वारा तोड़े गए विश्वास की घटना बता दीजिए, आप न बता पाएंगे। पिछले हजार वर्षों के इतिहास में चारों दिशाओं में हिंदू राजाओं के शासन में मुस्लिमों की नई बसाहटें हुई हैं, अनेक मस्जिदों का निर्माण हिंदू राजाओं के दिए दान से कराया गया है। मोदी आज 'सबका विश्वास' जैसा नारा दे रहे हैं तो इसे समृद्ध हिंदू परंपराओं का पालन ही मानना चाहिए। 'सबका विश्वास' मुस्लिमों को दिया गया वह अवसर है जो उसे उनके पूर्वजों द्वारा किए गए तमाम अत्याचारों को भूल कर दिया गया है। यह अवसर यदि देश के पुनर्निर्माण की दृष्टि से मुस्लिमों को दिया गया है और उन पर विश्वास करने का आग्रह देश के बहुसंख्यक समाज से किया है तो प्रत्युत्तर में देश के मुस्लिम समाज को भी अपना सौ प्रतिशत देश को देना होगा। मोदी की पहल के बदले में मुस्लिम समाज को लव जिहाद, आतंकवाद, तीन तलाक, मदरसों में हथियार, मजारों का अवैध निर्माण, बहु विवाह- अधिक संतानें, सड़क पर नमाज, गौहत्या जैसी गतिविधियों को रोकना होगा। इससे ही 'विश्वास' बढ़ेगा, अन्यथा मोदी की इस ऐतिहासिक पहल को वह खो बैठेगा।

मोदी की स्पष्ट सोच है कि मुस्लिमों को देश की मुख्यधारा में लाना है। लेकिन 'सबका विश्वास' एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं है! मुस्लिम समाज को इस दिशा में सकारात्मकता दिखाकर आगे बढ़ना होगा। उसे अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा से यह सिद्ध करना होगा कि वह मुस्लिम आतंकियों के साथ नहीं है, यह दिखाना होगा कि वह विभाजनकारियों को पनाह नहीं दे रहा है, मदरसों में शिक्षा चल रही है, न कि हथियारों का संग्रह व देशद्रोहियों का जन्म नहीं हो रहा है।

'सबका विश्वास' के लिए मुस्लिम समुदाय किस तरह से माहौल तैयार करे यह कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। मुस्लिम समाज केवल यह देख ले कि जब देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी हो तब 'चांदनी चौक' और 'बिजनौर मदरसे' जैसी घटनाओं के बाद इस देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों, फिल्म कलाकारों, धार्मिक नेताओं ने अपराधियों के प्रति क्या कोई तीखी आलोचना की है?

समय आ गया है कि अब देश का मुस्लिम समाज मथुरा, काशी और अयोध्या पर अपनी पहल को स्पष्ट करे। वह इन स्थानों को हिंदू समुदाय को सौंप दे और समन्वय की एक ठोस मिसाल प्रस्तुत करे। भारतीय मुस्लिम यह बात नई पीढ़ी को बताए कि उनके पुरखे बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारियों के भयवश धर्मांतरित होकर हिंदू से मुस्लिम बने हैं। उन्हें आभास होना चाहिए कि जिन मुगल आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था वे उनके आदर्श नहीं हैं, बल्कि इन ध्वस्त धर्म स्थानों को देखकर या श्रीराम को तिरपाल में बैठे देखकर दुखी होने वाला हिंदू उसका अपना भाई है। मोदी ने पहल की है तो इस पहल को आधार और नींव बनाकर देने का कार्य हम देशवासियों का है जो हिंदू मुस्लिम में बंटे हुए हैं।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक रहे प्रो. राजेंद्र सिंह का एक कथन सामयिक है- 'चाहे महाराजा रणजीत सिंह का राज हो या शिवाजी का, किसी के भी राज में कहीं भी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। परंतु इस देश का मुसलमान, जो मत परिवर्तन करके मुसलमान बना, यहीं का है, वह हिंदुस्तान के तीन अति महत्व के श्रद्धा केंद्र हिंदुओं को क्यों नहीं दे सकता? अयोध्या, मथुरा व काशी का मुसलमानों के लिए कोई मतलब नहीं है। जब तक ये तीनों इसी रूप में रहेंगे हिंदू समाज के हृदय में मुसलमानों के प्रति प्रेम भाव जागृत नहीं हो सकता। हर वर्ष करोड़ों हिंदू दर्शन करने के लिए यहां आते हैं, और जब मंदिर की दशा देखते हैं तो उन्हें ठेस पहुंचती है। इन मंदिरों को छोड़ने के लिए आज भी मुसलमान तैयार नहीं हैं, क्योंकि आक्रमणकारी मुसलमान थे। भला आक्रमणकारी से आप का क्या रिश्ता है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति में भरोसा रखने वालों ने अल्पसंख्यकों को डर में जीने पर मजबूर किया, लेकिन हमें इस छल को समाप्त करते हुए सबको साथ लेकर चलना होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसे हम सभी को मिलकर साबित करना होगा।

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 26 जुलाई 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

एसबीआइ ने निर्यात लेन-देन के सेवा शुल्क में किया बदलाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने गुरुवार को कहा कि वह निर्यात लेन-देन से जुड़े सेवा शुल्कों में बदलाव करने जा रहा है, ताकि निर्यातकों को लागत की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। संशोधित शुल्क पहली सितंबर से लागू होंगे। पहली सितंबर से इन शुल्कों को दो प्रमुख सेग्मेंट में विभाजित किया जाएगा- एक्सपोर्ट क्रेडिट कस्टमर्स और नॉन-एक्सपोर्ट क्रेडिट कस्टमर्स। इन शुल्कों को एमएसएमई और गैर-एमएसएमई ग्राहकों के लिए भी अलग-अलग किया जाएगा।

ऑटो सेक्टर पिछले कुछ समय से मंदी के दौर से जूझ रहा है। इसका सीधा असर हमारी बिक्री पर दिखा है।

— गुंटर बुश्शेक
एमडी, टाटा मोटर्स

सेंसेक्स	37,830.98 ▼ 16.67	निफ्टी	11,252.15 ▼ 19.15	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 35,870 ₹00	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 42,300 ₹00	$ डॉलर	₹ 69.04 ▲ ₹ 0.06	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 63.85

जंग में जख्मी शेर बन दहाड़े

कैप्टन मनोज कुमार पांडे

जन्म : 25 जून 1975, सीतापुर, उत्तर प्रदेश
शहीद हुए : 3 जुलाई 1999 (24 वर्षीय)
यूनिट : 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन (1/11 जीआर)

शौर्य गाथा : कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून को उन्होंने बटालिक सेक्टर से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने जुबार टॉप पर कब्जा किया। वहां दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर में गोली लगने के बावजूद दुश्मन के पहले बंकर में घुसे। हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट में दो दुश्मनों को मार गिराया और पहला बंकर नष्ट किया। उनके साहस से प्रभावित होकर सैनिकों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। अपने घावों की परवाह किए बिना वे एक बंकर से दूसरे बंकर में हमला करते गए। आखिरी बंकर पर कब्जा करने तक वे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। यहां वह शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे- 'ना छोड़नूं' (नेपाली भाषा में 'उन्हें छोड़ना नहीं')। कैप्टन पांडे की इस दिलेरी ने अन्य प्लाटून और बटालियन के लिए आधार तैयार किया, जिसके बाद ही खालूबार पर कब्जा किया गया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च मेडल परम वीर चक्र प्रदान किया गया। उन्हें 'हीरो ऑफ बटालिक' भी कहा जाता है।

जरा याद करो कुर्बानी...

फैसला ▶ एनसीएलटी ने 4,350 करोड़ रुपये की बोली को दी मंजूरी

पतंजलि के खाते में रुचि सोया

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस की चुनौती याचिकाएं हुईं खारिज

मुंबई, प्रेट्र : लंबी रस्साकशी और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार बाबा रामदेव नियंत्रित पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया के अधिग्रहण की बाजी जीत ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए पतंजलि आयुर्वेद की 4,350 करोड़ रुपये की बोली को अनुमोदन दे दिया। इस अनुमोदन के साथ ही यह तय हो गया है कि कर्जदाता बैंकों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। रुचि सोया पर कर्जदाताओं का 9,345 करोड़ रुपये और अन्य लेनदारों का करीब 2,800 करोड़ रुपये बकाया है। सौदे को अनुमोदन देने से पहले एनसीएलटी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिंगापुर के कर्जदाता डीबीएस की याचिकाएं खारिज कर दीं।

दोनों कर्जदाताओं ने पतंजलि आयुर्वेद की बोली को कम बताते हुए सौदे को चुनौती दी थी। इनका कहना था कि इतनी कम बोली पर सौदे को अनुमोदन से उन्हें बहुत कम रकम मिलेगी। कंपनी के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने परिचालन कर्जदाताओं के 2,716.61 करोड़ रुपये के दावे भी स्वीकार कर लिए हैं। अभी यह नहीं बताया गया है कि इन कर्जदाताओं को कितनी रकम वापस मिलेगी। लेकिन इतना तय है कि कर्जदाता बैंकों को लगभग 60 फीसद रकम से हाथ धोना पड़ेगा।

एनसीएलटी ने यह भी कहा है कि यह अनुमोदन इस बात पर निर्भर करता है कि पहली अगस्त को सुनवाई से पहले बोली के हिस्से के तौर पर 600 करोड़ रुपये जमा कराने की जो शर्त है, उस रकम का मूल स्रोत क्या है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने आरपी को पूरी समाधान प्रक्रिया के खर्च का भी हिसाब-किताब देने को कहा है। सौदे के बारे में पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। इससे स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि रुचि सोया के प्रमुख ब्रांडों में न्यूट्रिला, महाकोश, सनरिच, रुचि स्टार और रुचि गोल्ड शामिल हैं।

कर्जदाता बैंकों को होगा बड़ा नुकसान। फाइल

इनका इतना बकाया

कर्जदाताओं में सर्वाधिक 1,800 करोड़ रुपये का बकाया भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) का है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 816 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक का 743 करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 608 करोड़ रुपये बकाया है।

बोली बढ़ाई थी

पतंजलि ने बोली को इस वर्ष मार्च में करीब 200 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4,350 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें रुचि सोया में लगाई जाने वाली 1,700 करोड़ रुपये की पूंजी शामिल नहीं है। कर्जदाताओं की समिति ने पतंजलि की संशोधित बोली पर विचार करने के लिए 30 अप्रैल को मतदान करने का फैसला लिया।

महिला उद्यमियों की मदद को वाट्सएप-नीति आयोग साथ

- महिला उद्यमियों को चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाने के लिए कंपनी सालभर चलाएगी कार्यक्रम
- 'वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' पुरस्कार की विजेताओं को देगी 69 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत परितंत्र के विकास के मकसद से लोकप्रिय मैसेजिंग एप कंपनी वाट्सएप ने गुरुवार को नीति आयोग के साथ एक साझेदारी की। वाट्सएप सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ मिलकर महिला उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए साल भर कार्यक्रम चलाएगी। इसके साथ ही कंपनी महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का भी विकास करेगी। नीति आयोग के 'वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (डब्ल्यूटीआइ) पुरस्कार-2019 की विजेताओं को वाट्सएप एक लाख डॉलर (करीब 69 लाख रुपये) की सहायता भी देगी।

मौके पर वाट्सएप के ग्लोबल हेड विल कैथकार्ट भी मौजूद थे। डब्ल्यूटीआइ पुरस्कार का आयोजन नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संयुक्त तौर पर करते हैं। इसमें कारोबार, उद्यमिता और सामाजिक चुनौतियों के समाधान की पहल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ऐसे देशों में शामिल है, जहां स्टार्ट-अप का ईकोसिस्टम सर्वाधिक जीवंत है। अगला बड़ा बदलाव महिला उद्यमियों की ओर से आने वाला है। इसमें डिजिटल माध्यम सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी।

इसी साल भुगतान सेवा लांच करने की तैयारी में वाट्सएप : इस साल के आखिर तक वाट्सएप भारत में अपनी भुगतान सेवा शुरू कर सकती है। फेसबुक की कंपनी ने पिछले साल करीब 10 लाख वाट्सएप उपयोगकर्ताओं के साथ पेमेंट सेवा का परीक्षण शुरू किया था। कंपनी नियामकीय मंजूरियों का इंतजार कर रही है। वाट्सएप के ग्लोबल हेड विल कैथकार्ट ने एक कार्यक्रम में यहां कहा कि हमने यूपीआइ मानकों के आधार पर भुगतान सेवा तैयार की है। इसके लिए कई बैंकों के साथ साझेदारी की है। इससे वित्तीय समावेशीकरण तेज होगा। अधिकाधिक लोग तेजी से विस्तार कर रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के दायरे में आएंगे।

टाटा मोटर्स का घाटा दोगुना

- जेएलआर के कमजोर प्रदर्शन के बीच घरेलू बाजार में दबाव का असर
- जून तिमाही में कंपनी की आय भी घटकर 61,466.99 करोड़ रुपये रह गई

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स का घाटा करीब दोगुना हो गया है। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने 3,679.66 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड घाटा उठाया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1,862.57 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वैसे जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी ने 1,109 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

घरेलू बाजार में दबाव और जैगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) के खराब प्रदर्शन की वजह से टाटा मोटर्स का घाटा बढ़ा है। जून तिमाही में कंपनी की आय भी घटकर 61,466.99 करोड़ रुपये रह गई। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की आय 66,701.05 करोड़ रुपये रही थी। नतीजों को लेकर टाटा मोटर्स ने गुरुवार को कहा कि नतीजों पर पहली तिमाही में मांग सुस्त रहने का असर दिखा है। कंपनी के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में नकदी को लेकर चिंता और हायर एक्सल लोड के चलते मुनाफा प्रभावित हुआ।

लंबी अवधि की योजना पर फोकस : कंपनी का कहना है कि कॉमर्शियल और पैसेंजर वाहन सेग्मेंट में अब भी चुनौतियां बनी हुई हैं। जून तिमाही में कॉमर्शियल वाहनों की थोक बिक्री 16 फीसद और खुदरा बिक्री 14.8 फीसद घटी। हालांकि कंपनी आगे अच्छी ग्रोथ के लिए लंबी अवधि के बेहतर प्लान पर फोकस कर रही है।

घाटे में जैगुआर लैंड रोवर : जून तिमाही में जैगुआर लैंड रोवर पर दबाव बना रहा। इस दौरान कंपनी का घाटा करीब 40 करोड़ पाउंड (करीब 3,437.2 करोड़ रुपये) के स्तर पर पहुंच गया।

जेएलआर का भी बड़ा दबाव है कंपनी पर।

कानपुर की कपड़ा मिलों पर संकट

- मिलों की संपत्तियों को बेचने की नीति आयोग ने की है सिफारिश
- कानपुर के कपड़ा उद्यमियों के साथ 'निट वियर स्कीम' तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कपड़ा उत्पादन के लिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर की दशकों से बंद पड़ी कपड़ा मिलों के दोबारा शुरू होने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की मिलों की संपत्तियों को बेचने सिफारिश की गई है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने माना कि कानपुर की बीआईसी और एनटीसी की मिलों के पुनरोद्धार की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। नीति आयोग ने इन मिलों के विनिवेश की सिफारिश भी की है।

ईरानी ने कहा कि इस क्षेत्र के पुनरोद्धार के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। कानपुर के टेक्सटाइल उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय से 'निट वियर सेक्टर' यानी बुने वस्त्रों के क्षेत्र को लेकर विशेष प्रयास करने की मांग की। मंत्रालय ने देशभर में बुने हुए कपड़े बनाने वाले उद्योगों के लिये 'निट वियर स्कीम' बनाई है। इसमें कानपुर के टेक्सटाइल्स उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मंत्रालय इस योजना को कानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में लागू करने पर काम कर रहा है।

बंद मिलों के चलने की सभी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। फाइल

एक पूरक सवाल के जवाब में कपड़ा मंत्री ईरानी ने कहा कि मंत्रालय ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (बीआइसी) की मिलों को चलाने के प्रयास पिछली सरकार ने भी किए, लेकिन वे विफल हुए। बीआइसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसमें लाल इमली और धारीवाल जैसे लोकप्रिय ब्रांड के कपड़ों का उत्पादन होता रहा है। इसकी कानपुर सहित कई अन्य जगहों पर कपड़ा मिलें हैं। ईरानी ने कहा, 'पिछली सरकार और मौजूदा सरकार में अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी की उपलब्धता की चिंता को भी दूर करने के भरसक प्रयास किए गए। लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद नीति आयोग के एक पैनल ने बीआइसी के विनिवेश का सुझाव दिया है।'

एक अन्य पूरक सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय समस्याओं और श्रम संबंधी अड़चनों के चलते देश की ज्यादातर कपड़ा मिलें बंद हुईं। ईरानी के मुताबिक एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआइटीपी) सहित अन्य योजनाओं के तहत 59 वस्त्र पार्क मंजूर किए गए हैं। इनमें से 22 पार्क 780.22 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से पूरे हुए हैं। इसके लिए नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया गया है। इनमें अब तक 80 हजार से अधिक लोगों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए।

रियल एस्टेट की फंडिंग में 48 फीसद की आई कमी

- एनबीएफसी और एचएफसी ने पिछले वित्त वर्ष में 27,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया
- छोटी कंपनियों से पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिल्डरों को मिले 4,000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की ओर से रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाने वाला कर्ज पिछले वित्त वर्ष में करीब 48 फीसद तक घटकर 27,000 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल सितंबर में नकदी की कमी के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) के द्वारा डिफॉल्ट किए जाने के बाद कर्ज में कमी आई है।

अचल संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली कंपनी जेएलएल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और एचएफसी रियल एस्टेट डेवलपरों को नया कर्ज देने से बच रही हैं। ऐसे में छोटी कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिल्डरों को 4,000 करोड़ रुपये के कर्ज देकर थोड़ी राहत दी।

जेएलएल इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख एवं सीईओ रमेश नायर ने कहा कि प्रमुख एनबीएफसी आइएलएंडएफएस के कर्ज भुगतान में चूक के चलते सितंबर, 2018 के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र नकदी की कमी से जूझ रहा है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल-सितंबर, 2018 तक एनबीएफसी एवं एचएफसी की ओर से दिए जाने वाले कर्ज की रफ्तार सामान्य थी, लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में इसमें उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। नायर ने कहा कि 2018-19 में रियल एस्टेट डेवलपरों को एनबीएफसी/एचएफसी की ओर से दिया गया कर्ज करीब आधा घटकर 27,000 करोड़ रुपये रह गया।

चीन को झुनझुना थमाएगी दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना कंपनी

जेएनएन, नई दिल्ली

- भारत और वियतनाम को उत्पादन के लिए अगला बड़ा हब बनाने के बारे में सोच रही है हैसब्रो
- कहा - ट्रेड वार की बढ़ती चिंता और अनिश्चितता के बीच चीन पर निर्भरता घटाना बेहद जरूरी

अमेरिका और चीन में गहराते ट्रेड वार के बीच वहां से निकलने की कोशिशों में जुटी कंपनियों में एक नया नाम जुड़ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना कंपनी हैसब्रो इंक चीन को झुनझुना थमाकर वहां से निकल जाने की तैयारी में है। यह दिग्गज अमेरिकी कंपनी भारत और वियतनाम में नए उत्पादन संयंत्रों पर फोकस कर रही है। कंपनी के पास फ्रोजन और एवेंजर्स जैसे मशहूर ब्रांड्स का लाइसेंस है। हैसब्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ब्रायन गोल्डनर ने दूसरी तिमाही के नतीजे जाहिर करने के बाद एक कांफ्रेंस कॉल में यह जानकारी दी।

गोल्डनर ने कहा कि चीन में अमेरिकी कंपनियों का उत्पादन अगले वर्ष के अंत तक घटकर 50 फीसद पर आ सकता है। वहां अमेरिकी कंपनियां पहले ही उत्पादन घटाकर दो-तिहाई (66 फीसद) से कम पर ले आई हैं। उन्होंने कहा, 'हम उत्पादन के लिए दुनियाभर के नए बाजारों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम नए बाजारों में प्रवेश कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।'

चीन के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। फाइल

हालांकि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार पर इस महीने के आखिर में नए सिरे से बातचीत होने की संभावना है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान कई कंपनियों ने चीन में उत्पादन पर निर्भरता कम करने की योजना बना ली है। ट्रेड वार पर कोई नतीजा नहीं निकलता देखते हुए इंटेल कॉर्प जैसी बड़ी कंपनियां चीन में अपने उत्पादन की समीक्षा कर रही हैं। चीन दशकों से दुनियाभर की कंपनियों के लिए उत्पादन का प्रमुख स्रोत रहा है। हालांकि गोल्डनर ने माना कि चीन में अभी भी कम कीमत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण की क्षमता है। वह किसी न किसी रूप में कंपनी के दुनियाभर के नेटवर्क के लिए प्रमुख बाजार रहने वाला है। लेकिन ट्रेड वार की चिंता के बीच उसे पहले ही कारोबारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) देबोरा थॉमस ने कहा कि कंपनी के कई रिटेलर दूसरी तिमाही के दौरान प्रमुख उत्पादन स्थानों से सीधे ऑर्डर देने में हिचकिचाते रहे।

सोना-चांदी में सुस्त रहा कारोबार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुस्त कारोबार के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 35,870 रुपये प्रति 10 ग्राम के पिछले भाव पर कायम रहा। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक विदेशी बाजारों के नकारात्मक रुझानों के बाजवूद चांदी भी 42,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर कायम रही। न्यूयॉर्क में सोने में 1,426.60 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 16.59 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

विश्लेषकों के मुताबिक यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) की ओर से गुरुवार शाम जारी होने वाले मौद्रिक नीति संबंधी बयान से पहले निवेशकों ने सतर्कता बरती, जिसके कारण सोने में अधिक कारोबार नहीं हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी के हाजिर बाजार में 99.9 फीसद खरा सोना 35,870 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी 35,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव कायम रहा। आठ ग्राम सोने की गिन्नी भी 27,500 रुपये प्रत्येक के भाव पर स्थिर रही। चांदी हाजिर 42,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार रही। वीकली डिलीवरी 12 रुपये चढ़कर 41,558 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 85,000 रुपये खरीद और 86,000 रुपये बिक्री के स्तर पर बनी रही।

तबादला होते ही गर्ग ने मांगा वीआरएस

- आर्थिक मामलों के विभाग का कार्यभार सौंपने के बाद गर्ग ने किया ट्वीट
- वीआरएस के लिए दिया तीन महीने का नोटिस, 31 अक्टूबर को खत्म होगी अवधि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय से ऊर्जा मंत्रालय में तबादले के अगले ही दिन आर्थिक मामलों के सचिव और वरिष्ठ नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन कर दिया। वित्त मंत्रालय में कार्यभार सौंपने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 31 अक्टूबर सरकारी सेवा में उनका अंतिम दिन होगा।

गर्ग अभी तक वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ सचिव थे और आर्थिक मामलों के विभाग के प्रमुख थे। उन्हें वित्त सचिव भी बनाया गया था। बुधवार को ही उन्हें वित्त से हटाकर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई थी। गुरुवार को विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव अतनु चक्रवर्ती को कार्यभार सौंपने के बाद गर्ग ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया।

आवेदन करने के बाद अपने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी देते हुए गर्ग ने कहा, 'आर्थिक मामलों के विभाग का कार्यभार सौंप दिया है। वित्त मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग में रहते हुए बहुत कुछ सीखा। कल ऊर्जा मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करूंगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से 31 अक्टूबर से वीआरएस लेने के लिए भी आवेदन किया है।' उन्होंने कहा कि अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से यह उनका आखिरी ट्वीट है।

वित्त मंत्रालय और आरबीआइ में इनके कार्यकाल में तल्खी बनी रही। फाइल

कार्यालय से निकलते वक्त संवाददाताओं से बातचीत में गर्ग ने कहा कि वीआरएस के लिए तीन महीने का नोटिस देना होता है। इसलिए 31 अक्टूबर से सेवानिवृत्ति मांगी है। वैसे उनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 तक है। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव रहते हुए उनका दायित्व राजकोषीय नीति और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से संबंधित मामले थे। केंद्रीय बजट बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। वह विदेश से उधारी जुटाने की बजट में घोषित योजना का काम भी देख रहे थे।

सरकारी बांड के माध्यम से विदेश से कर्ज जुटाने के इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरबीआइ के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, सी रंगराजन समेत प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रथिन राय ने इसकी कड़ी आलोचना की है। चूंकि गर्ग सॉवरेन बांड जारी करने की प्रक्रिया की देखरेख कर रहे थे, इसलिए उनके तबादले को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे, उनके कार्यकाल में आरबीआइ और वित्त मंत्रालय के बीच तल्खी बनी रही। खासतौर पर रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड के मसले पर दोनों पक्षों के संबंध बिगड़े और पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। आरबीआइ के फंड हस्तांतरण के मसले पर बनी समिति के वह सदस्य थे और उन्होंने रिपोर्ट के खिलाफ मत दिया।

मायूसी

सेंसेक्स 16.67 अंकों की गिरावट के साथ 37,830.98 पर बंद, निफ्टी 19.15 अंकों के नुकसान के साथ 11,252.15 पर स्थिर

लगातार छठे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार

मुंबई, प्रेट्र : फ्यूचर एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) सौदों की एक्सपायरी के बीच शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार छठे दिन गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 16.67 अंकों की गिरावट के साथ 37,830.98 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 19.15 अंकों की गिरावट के साथ 11,252.15 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में टाटा मोटर्स में सर्वाधिक 4.56 फीसद गिरावट रही। रेटिंग एजेंसी फिच ने कंपनी की रेटिंग 'बीबी' से घटाकर 'बीबी-' कर दी है। एजेंसी ने कंपनी के आउटलुक को भी नकारात्मक कर दिया है। बजाज फाइनेंस में 3.95 फीसद और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.11 फीसद, यस बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आइटीसी और लार्सेन एंड टुब्रो में एक फीसद से अधिक गिरावट रही। दूसरी ओर वेदांता में सर्वाधिक 3.82 फीसद तेजी रही। सन फार्मा और इंडसइंड बैंक में दो फीसद से अधिक, एक्सिस बैंक, टीसीएस, पावर ग्रिड, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में एक फीसद से अधिक तेजी रही। बीएसई पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 6.46 फीसद उछलकर 986.10 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने जून तिमाही के अपने शुद्ध लाभ में करीब 11 फीसद बढ़ोतरी दर्ज की है।

कारोबारियों ने कहा कि जुलाई के डेरिवेटिव सौदों की एक्सपायरी पर बाजार में भारी अस्थिरता रही। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि विदेशी बाजारों के सकारात्मक रुझानों और डेरिवेटिव सौदों में शॉर्ट कवरिंग के बावजूद बाजार को सहारा नहीं मिला। गिरावट का दौर लंबा खिंचने के डर से निवेशक देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं।

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के ऊर्जा सेक्टर में सर्वाधिक 1.91 फीसद गिरावट रही। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा सेक्टर में सर्वाधिक 1.61 फीसद तेजी रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.53 फीसद तेजी और स्मॉलकैप में 0.09 फीसद गिरावट रही।

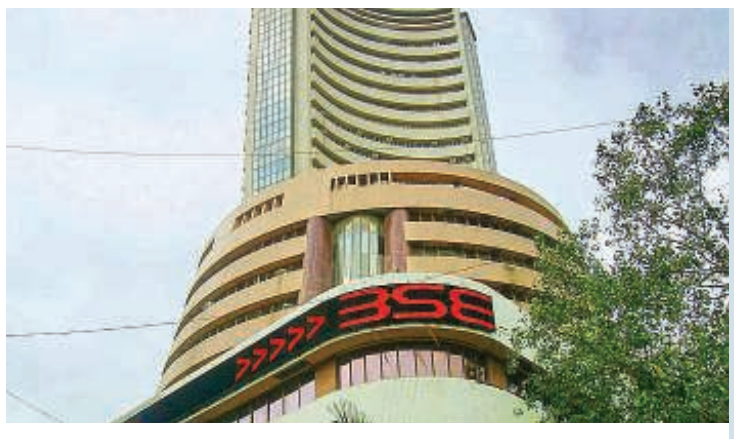

कंपनियों के वित्तीय नतीजे बाजार के लिए उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। फाइल

टीसीएस फिर बनी सबसे बड़ी कंपनी, आरआइल को पछाड़ा

नई दिल्ली : टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) गुरुवार को बाजार पूंजीकरण (एमकैप) के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। टीसीएस का एमकैप 7,98,620.04 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह आरआइएल के एमकैप से करीब 17,455.58 करोड़ रुपये अधिक है। आरआइएल का एमकैप 7,81,164.46 करोड़ रुपये है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी के खिताब के लिए टीसीएस और आरआइएल ने कई बार एक-दूसरे का पछाड़ा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा को 826 करोड़ का शुद्ध लाभ

- देना बैंक व विजया बैंक के विलय के बाद बैंक ने पहली बार वित्तीय नतीजे की घोषणा की
- बैंक की कुल कंसोलिडेटेड आय अप्रैल-जून तिमाही में 22,056.95 करोड़ रुपये रही

नई दिल्ली, प्रेट्र : बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए 826.13 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ दर्ज किया है। देना बैंक और विजया बैंक का अपने साथ विलय करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली बार वित्तीय नतीजे की घोषणा की है। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 645.71 करोड़ रुपये के कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ की घोषणा की थी। विलय के कारण जून 2019 तिमाही के आंकड़े की तुलना एक साल पहले की समान अवधि के आंकड़े के साथ नहीं की जा सकती है।

बैंक ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि आलोच्य अवधि में बैंक की कुल आय 22,056.95 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक की कुल आय 13,729.50 करोड़ रुपये थी। स्टैंडअलोन आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ आलोच्य अवधि में 709.87 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 528.26 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में स्टैंडअलोन आय 20,860.90 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 12,787.71 करोड़ रुपये थी। स्टैंडअलोन आधार पर बैंक का ग्रॉस एनपीए अनुपात 30 जून 2019 को 10.28 फीसद था।

फाइल फोटो

22 महीने की अपनी जांच रिपोर्ट में रॉबर्ट मुलर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निर्दोष करार नहीं दिया है। 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच के वह विशेष अभियोजक थे। उन्होंने न्यायिक मामलों की समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने न्याय विभाग की नीति का पालन किया है जिसके तहत कार्यरत राष्ट्रपति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता।

नंगे पैर शत्रु को सिखाया सबक

कैप्टन नीकेजाकुओ कैंगुरूसे

जन्म : 15 जुलाई, 1974 नरहेमा, कोहिमा जिला, नगालैंड
शहीद हुए : 28 जून, 1999
यूनिट : 2 राजपूताना रायफल

शौर्य गाथा : 12 दिसंबर, 1998 में सेना में भर्ती हुए। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, वे राजपूताना रायफल बटालियन में जूनियर कमांडर थे। उनकी दृढ़ता और दिलेरी के कारण उन्हें अपनी बटालियन के घातक प्लाटून का नेतृत्व सौंपा गया। 28 जून की रात कैप्टन कैंगुरूसे के प्लाटून को ब्लैक रॉक नामक टीले से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। टीले पर चढ़ाई के दौरान ऊपर से दुश्मन के लगातार हमले में कई सैनिक शहीद हुए और खुद कैप्टन को कमर में गोली

जरा याद करो कुर्बानी...

लगी, लेकिन वे रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर वे एक पत्थर की आड़ में टीले के किनारे लटके रहे। 16,000 फीट ऊंचाई और -10 डिग्री तापमान में बर्फ पर लगातार उनके जूते फिसल रहे थे। लौटकर नीचे आना ज्यादा आसान था, लेकिन वे अपने जूते उतारकर नंगे पैर टीले पर चढ़े और आरपीजी रॉकेट लांचर से सात पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया। दो दुश्मनों को कमांडो चाकू से मार गिराया और दो को अपनी रायफल से। दुश्मनों की गोलियों से छलनी होकर वे टीले से नीचे आ गिरे, लेकिन इतना कर गए कि उनके प्लाटून ने टीले पर कब्जा कर लिया। इस दिलेरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

ब्रिटिश सरकार में भारत की बल्ले-बल्ले

जॉनसन की कैबिनेट में भारतीय मूल के तीन मंत्री, प्रीति पटेल को मिला गृह मंत्रालय

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के तीन नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। इनमें अति महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रीति पटेल को दी गई है, जो मूलतः गुजरात की हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़े आलोक शर्मा को अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है जबकि इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक (39) वित्त मंत्री बनाए गए हैं। इन तीनों ने गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री आवास 10, डाउनिंग स्ट्रीट में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले जॉनसन ने साफ कर दिया कि ब्रिटेन हर हाल में 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन छोड़ेगा, इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं होगी। प्रीति पटेल के गृह मंत्री बनने पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है।

47 वर्षीय प्रीति पटेल के पास ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा, आव्रजन और वीजा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। प्रीति के सामने अपराधों से लड़ने की चुनौती है तो ब्रेक्जिट के बाद उन्हें यूरोपीय देशों के नागरिकों के लिए ब्रिटेन आने के नियम भी तय करने होंगे। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों और अन्य प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए वीजा को आसान बनाया जाएगा लेकिन सामान्य कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को प्रमुखता दी जाएगी। प्रीति ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से अलगाव) की प्रबल समर्थक हैं। उनके सहयोगी सुनक भी ब्रेक्जिट के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने भी वीजा नियमों को आसान बनाने की वकालत की है जिससे नया ब्रिटेन सभी के लिए हो।

उभरते सितारे हैं ऋषि सुनक : युवा ऋषि सुनक को ब्रिटेन की राजनीति में उभरता हुआ सितारा माना जाता है। एमबीए ग्रेजुएट सुनक को इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट माना जाता है। 2017 में हुए चुनाव में सुनक एक बार फिर जीते। इसके बाद उन्हें टेरीजा मे ने अपनी सरकार में राज्य मंत्री बनाया। जॉनसन ने उन्हें प्रोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया है।

ब्रिटेन को आगे बढ़ाएंगे शर्मा : आगरा में जन्मे आलोक शर्मा (51) टेरीजा सरकार में रोजगार विभाग के राज्य मंत्री थे। पांच साल की उम्र में माता-पिता के साथ ब्रिटेन के रीडिंग शहर पहुंचे आलोक मूलतः चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। उन्हें भी प्रोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया है।

गृह मंत्री, प्रीति पटेल। एपी

वित्त मंत्री, ऋषि सुनक। रायटर

अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री, आलोक शर्मा। एपी

लंदन में जॉनसन विरोधी प्रदर्शन

लंदन, एएनआइ : बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने कुछ ही घंटे बीते थे कि उनके विरोधी लंदन के मध्य में आ डटे। उन्होंने जॉनसन के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। जॉनसन को रेसिस्ट, सेक्सिस्ट और फासिस्ट बताते हुए विरोध जताया। ये प्रदर्शनकारी इस्लामोफोबिया (इस्लाम विरोधी भावना) से ग्रसित बता रहे थे। ये लोग हाथों में नारे लिखी तख्तियां और कार्ड हाथ में लिए हुए थे। जॉनसन दो बार लंदन के मेयर और ब्रिटेन के विदेश मंत्री रह चुके हैं।

धमाकों से दहला अफगानिस्तान, 11 लोगों की गई जान

काबुल, एएफपी/रायटर : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार को तीन बम धमाकों से दहल गई। इन धमाकों में 11 लोगों की मौत हो गई और 45 घायल हो गए। इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने ली है। ये धमाके ऐसे समय हुए, जब अफगानिस्तान में 28 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू होने वाले हैं।

अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी के अनुसार, पहला धमाका पूर्वी काबुल में सुबह आठ बजकर दस मिनट पर हुआ। यहां एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी बाइक एक बस से टकरा दी। यह बस खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय की थी। इस हमले में पांच महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। इसी इलाके में कुछ देर बाद ही एक अन्य आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। इस घटना में पांच लोग मारे गए और 20 घायल हो गए। इसके अलावा पूर्वी काबुल में एक और धमाका होने की खबर है। बता दें कि अफगानिस्तान में हाल के समय में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ता में अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव के तौर पर तालिबान हमले कर रहा है।

नीरव मोदी प्रत्यर्पण पर अंतिम सुनवाई अगले साल मई में होगी

लंदन, प्रेट्र : लंदन की एक अदालत ने भारत में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ा दी है। 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले और मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित मोदी की अदालत में अगली पेशी लंदन की जेल से ही वीडियो लिंक के जरिए होगी। हालांकि इस दौरान ब्रिटिश जज ने सभी पक्षों की सहमति से इस बात का भी संकेत दिया कि प्रत्यर्पण पर पांच दिवसीय अंतिम सुनवाई अब अगले साल मई के महीने में ही होगी।

ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर की मुख्य मजिस्ट्रेट एमा अर्बनॉट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान बताया कि मई, 2020 में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के लिए पांच दिवसीय सुनवाई होगी। चूंकि मामले में सभी सुबूत और बहस आठ अप्रैल तक पूरी होगी। इसके बाद ही पांच दिन की सुनवाई मई में होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर सभी पक्षों की सहमति है।

नीरव मोदी। फाइल

जज एमा अर्बनॉट ने वीडियो लिंक के जरिए 48 वर्षीय नीरव मोदी से कहा कि मेरे विचार से आप प्रक्रिया देर से होने के बजाय जल्दी चाहेंगे। इसलिए हम 22 अगस्त को अगली सुनवाई करेंगे। ब्रिटिश कानून के मुताबिक मोदी को अदालत में हर चार हफ्ते में पेश किया जाना है, जो अब अगस्त में होगा। अदालत में मोदी की वकील बैरिस्टर जेसिका जोंस थीं। जबकि भारत सरकार की ओर से मामले की पैरवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) कर रही है। सीपीएस बैरिस्टर हन्ना बर्टन ने कहा कि आगामी सोमवार को सुनवाई के लिए भारत सरकार ने सारे प्रबंध कर लिए हैं। इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए जज ने कहा कि यह पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं होगा।

हाल ही में अदालत में हुई तल्खी के बाद जज ने मजाकिया लहजे में कहा कि मुझे उम्मीद है कि वांड्सवर्थ आपके लिए ज्यादा गर्म नहीं है। इस पर नीरव मोदी ने हंसकर जवाब दिया, धन्यवाद मैम। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी के 19 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से ही वह दक्षिण-पश्चिम लंदन स्थित वांड्सवर्थ जेल में कैद है। नीरव की जमानत कई दफा खारिज हो चुकी है। हालांकि उस फैसले में लंदन के रायल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जज इनग्रिड सिमलर ने कहा कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा कि चूंकि पहले भी उसकी भाग जाने की प्रवृत्ति देखी गई है।

मध्यस्थता की बात कर ट्रंप ने की बड़ी राजनयिक भूल

बड़ा मामला ▶ वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रपति की अज्ञानता से अहम देश हो सकता है दूर

भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बुश और बराक के किए पर पानी फेर रहे हैं ट्रंप

वॉशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश कर 'हद दर्जे की राजनयिक भूल' की है। यह कहना है अमेरिका के एक शीर्ष समाचार पत्र का। अखबार का यह भी मानना है कि ट्रंप भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पूर्व राष्ट्रपतियों के किए पर पानी फेर रहे हैं। अखबार के मुताबिक राष्ट्रपति के बर्ताव से एक प्रमुख देश विमुख हो सकता है।

ट्रंप ने सोमवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक के दौरान यह बयान देकर दुनिया को स्तब्ध कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के ओसाका में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान कश्मीर मामले को सुलझाने में उनकी मदद मांगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के तुरंत बाद भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि मोदी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है।

ट्रंप के बयान के बाद खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हुए कहा कि वह कश्मीर को भारत एवं पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला मानता है और वह तभी मदद के लिए तैयार होगा, जब दोनों देश चाहेंगे।

अमेरिका के शीर्ष दैनिक 'द वॉशिंगटन पोस्ट' ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, 'ट्रंप ने हद दर्जे की राजनयिक भूल की है।' अखबार ने आगे कहा, 'भारत के साथ व्यापार युद्ध के बाद, कश्मीर मामले पर उनकी भूल एक अहम देश को और विमुख कर देगी, जिसकी मित्रता की अमेरिका को चीन के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए आवश्यकता है।' अखबार ने आगे कहा, 'राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने भारत के साथ संबंधों में सुधार किया, ट्रंप कुछ गलत शब्दों से उनके किए पर पानी फेर रहे हैं।' समाचार पत्र ने कहा, 'वह अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों को वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यदि वह पाकिस्तान को खुश करते हैं, तो अमेरिका वहां से सम्मान से साथ निकल पाएगा।' समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है, 'अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने में मदद करने में पाकिस्तान का हित है। इससे तालिबान, हक्कानी नेटवर्क को वर्चस्व बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन हमेशा की तरह, ट्रंप को इस बार भी पता नहीं है कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है।'

डोनाल्ड ट्रंप। एपी

ऐसा महसूस हो रहा है विश्व कप जीत कर लौटा हूं : इमरान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि पहले अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद उनके समर्थकों ने जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है, उससे उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे वह देश के लिए क्रिकेट का विश्व कप जीत कर लौटे हैं। हवाईअड्डे पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए इमरान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि न वो कभी किसी के आगे झुके हैं और न ही कभी देश को किसी के आगे झुकने देंगे।

अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 1992 में क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले 66 वर्षीय इमरान खान तीन दिन की अमेरिकी यात्रा खत्म कर कतर एयरलाइंस के सामान्य उड़ान से गुरुवार तड़के यहां पहुंचे। इमरान ने कहा कि हमें उन सभी संस्थाओं को बदलना होगा, जिन्हें पाकिस्तान को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों ने खत्म कर दिया है। इमरान ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से कहा है कि 'चोरों और लुटेरों' द्वारा विदेश में रखे गए पाकिस्तान के धन को वापस लाने में मदद करें। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक इमरान खान ने विदेश में 'भीख' मांगने के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, 'न तो मैं किसी के आगे झुका हूं और न अपने देश को झुकने दूंगा। हम स्वाभिमानी राष्ट्र हैं।'

इमरान खान। एएफपी

अब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे पाक : भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब सच स्वीकार कर लिया है कि उनके देश में 30-40 हजार आतंकी हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर कश्मीर में लड़ाई के लिए भेजा जाता है, तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करे। इमरान ने अमेरिकी यात्रा के दौरान पाक में आतंकियों की मौजूदगी स्वीकार करते हुए कहा था कि उनके देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस सच को अमेरिका से छिपा कर रखा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है।' उन्होंने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री खुद ऐसी बात कह रहे हैं तो जरूरी है कि आतंकियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। दुनिया को दिखाने के लिए आधी अधूरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हर हाल में आतंकियों का सफाया जरूरी है। कुमार ने कश्मीर पर मध्यस्थता संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पैदा हुए विवाद को भी खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का समय है। भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हैं।

रवीश कुमार। फाइल

उत्तर कोरिया ने किया कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण

- अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास की खबर से नाराज
- वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता बहाल होने पर मंडराए संकट के बादल

सियोल, एएफपी/रायटर : उत्तर कोरिया ने गुरुवार को फिर उकसावे वाला कदम उठाया। उसने कम दूरी तक मार करने वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के इस कदम से अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता बहाल होने पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। यह माना जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यास पर नाराजगी जाहिर करने के लिए उसने यह कदम उठाया है।

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार, ये नए प्रकार की मिसाइलें मानी जा रही हैं। ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसान के समीप से पूर्वी सागर या जापान सागर की तरफ दागी गई थीं। एक मिसाइल 430 किलोमीटर और दूसरी 690 किलोमीटर दूर तक गई। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता चोई ह्यून-सू ने कहा, 'हम उत्तर कोरिया से आग्रह करते हैं कि वह इस तरह के कृत्य को बंद कर दे। इससे सैन्य तनाव को दूर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी।' जबकि जापान के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया के कदम पर अफसोस जताया है और कहा कि मिसाइलें उनके देश के आर्थिक जोन से पहले ही गिर गई थीं।

उत्तर कोरिया ने हाल ही में यह चेतावनी दी थी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगर प्रस्तावित सैन्य अभ्यास को रद नहीं करते हैं तो परमाणु वार्ता पटरी से उतर सकती है। वाशिंगटन और प्योंगयांग में नए दौर की वार्ता अभी तक शुरू नहीं हुई है।

जापान सागर की तरफ दागी गई थीं मिसाइलें। एएफपी

कोरियाई सीमा पर मिले थे ट्रंप और किम: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने गत 30 जून को कोरियाई सीमा पर मुलाकात की थी। तब उत्तर कोरिया की सीमा में कदम रखने वाले ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। इस दौरान दोनों नेताओं में परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी। इस मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया ने यह पहला मिसाइल परीक्षण किया है। उसके इस कदम से परमाणु वार्ता खतरे में पड़ गई है। ट्रंप और किम की पहली मुलाकात गत वर्ष जून में सिंगापुर में हुई थी। इसके बाद इस साल फरवरी में दोनों के बीच वियतनाम में शिखर वार्ता हुई थी। लेकिन उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग पर यह वार्ता विफल हो गई थी।

मई में भी दागी थीं मिसाइलें : उत्तर कोरिया ने गत मई में भी इसी तरह कई मिसाइलें समुद्र में दागी थीं। उस समय ट्रंप ने कहा था कि इसका किम के साथ उनके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के करीब 30 हजार सैनिक तैनात हैं। वे हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं।

चीन से तनाव के बीच ताइवान के पास से गुजरा अमेरिकी युद्धपोत

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी नौसेना का एक युद्धपोत बुधवार को ताइवान जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से होकर गुजरा। अमेरिका के इस कदम से चीन भड़क सकता है। यह पोत ताइवान के पास से ऐसे समय गुजरा, जब वाशिंगटन और बीजिंग के संबंधों में तनाव है।

नौसेना प्रवक्ता क्ले डॉस के अनुसार, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए एक युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा। अमेरिकी नौसेना उन सभी जगहों पर अपने अभियान संचालित करेगी, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होते हैं।'

बता दें कि ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है। वह इस क्षेत्र में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। हालांकि, अमेरिका इसकी परवाह किए बगैर ताइवान को सैन्य साजो-सामान मुहैया कराता है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को दो अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इस पर चीन की ओर से कड़ा एतराज जताया गया है। बीजिंग ने गत बुधवार को एक बयान में अमेरिका को आगाह किया कि अगर ताइवान को लेकर कोई भी कदम उठाया जाता है तो वह युद्ध के लिए तैयार है।

हथियार बिक्री से रोकने वाले प्रस्तावों पर ट्रंप ने लगाया वीटो

- अमेरिकी राष्ट्रपति के कदम की सदन की स्पीकर ने की आलोचना

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचने पर रोक लगाने के लिए संसद में पेश तीन प्रस्तावों पर वीटो लगा दिया। ट्रंप के इस कदम की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने तीखी आलोचना की है।

ट्रंप ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, 'ये प्रस्ताव अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करेगा और हमारे सहयोगियों और साझीदारों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा।' उन्होंने यह भी कहा, 'सऊदी अरब में रह रहे 80 हजार से ज्यादा अमेरिकियों की रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। इन्हें यमन के हाउती विद्रोहियों से खतरा है।' जबकि स्पीकर पेलोसी ने एक बयान में कहा, 'यह चकित करने वाला है कि राष्ट्रपति ने न सिर्फ पत्रकार जमाल खशोगी की जघन्य हत्या समेत सऊदी अरब के भयावह कृत्यों पर आंखे मूंद लेना पसंद किया है बल्कि उसे और ज्यादा हथियार बेचने की मंजूरी भी दे दी है। राष्ट्रपति के शर्मनाक वीटो ने संसद की इच्छा को कुचलने का काम किया है। संसद निगरानी करने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करती रहेगी।'

प्रस्ताव पर प्रतिनिधि सभा ने लगाई थी मुहर

सऊदी अरब को 810 करोड़ डॉलर (करीब 56 हजार करोड़ रुपये) के हथियार बेचने के सौदे पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पेश किए गए थे। इन प्रस्तावों पर गत बुधवार को प्रतिनिधि सभा ने मुहर लगा दी थी। इस सदन में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है।

सऊदी दूतावास में हुई थी खशोगी की हत्या

तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के दूतावास में गत दो अक्टूबर को वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के पीछे सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान का हाथ होने का दावा किया गया था।

हो सकती है सुलह

राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ब्रिटेन को दिया टैंकरों की अदला-बदली का प्रस्ताव, कहा- नहीं छोड़ेंगे बातचीत के अवसर

ईरान ने अमेरिका से तनाव कम करने के दिए संकेत

न्यूयॉर्क टाइम्स से

लंदन : अमेरिका के साथ बढ़े टकराव के बीच ईरान ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने प्रतिबंध हटने पर अमेरिका के साथ बातचीत करने के संकेत दिए। रूहानी ने ब्रिटेन को टैंकरों की अदला-बदली का प्रस्ताव भी दिया है।

तेहरान में कैबिनेट की बैठक के बाद रूहानी ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत करने के संकेत दिए। ईरान की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूहानी ने कहा, 'बेशक ऐसे देश हैं जो अमेरिका और हमारे बीच में मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। पत्राचार और बातचीत चल रही है और सबको पता होना चाहिए कि हम कभी बातचीत के अवसर को नहीं छोड़ेंगे।'

वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव तब ज्यादा बढ़ गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका को अलग कर लिया था साथ ही ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे।

रूहानी ने बुधवार को कहा कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध अगर हटाए जाते हैं तो वह वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर दूसरे पक्ष की ओर से सही और संतुलित कदम उठाया जाता है और चल रहे इस आर्थिक युद्ध में संघर्ष विराम की घोषणा की जाती है तो एक दूसरे से बात करने और किसी निष्कर्ष पर आने का अवसर मिलेगा।

रूहानी ने यूरोपीय देशों के साथ तनाव कम करने के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे ब्रिटेन का टैंकर छोड़ सकते हैं, लेकिन बदले में ब्रिटेन जिब्राल्टर के तट से जब्त किए गए ईरानी जहाज को छोड़े। रूहानी का बयान यह भी दर्शाता है कि ईरान ने बदले की कार्रवाई में ही ब्रिटेन का टैंकर जब्त किया था। ईरान ने दो दिन पहले ब्रिटिश फ्लैग लगे स्वीडेन की कंपनी के मालिकाना हक वाले तेल टैंकर को होरमुज जलडमरूमध्य में पकड़ा था। इसके चालक दल के 23 सदस्यों में से 18 भारतीय हैं। बुधवार को कंपनी ने कैप्टन से बातचीत के बाद कहा था कि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।

जिब्राल्टर की अदालत में है ईरान के टैंकर का मामला : ब्रिटिश रॉयल नौसेना के सैनिकों ने चार जुलाई को जिब्राल्टर के तट पर ईरान के टैंकर को जब्त कर लिया था। आरोप था कि टैंकर सीरिया के लिए तेल आपूर्ति लेकर निकला था जोकि यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है। ब्रिटेन में तब के विदेश सचिव जेरेमी हंट ने अपने ईरानी समकक्ष से बातचीत में कहा था कि पकड़ा गया जहाज ग्रेस-1 लौटाया जा सकता है अगर उन्हें यह गारंटी मिले कि यह सीरिया नहीं जाएगा। यह मामला जिब्राल्टर की अदालत में है जहां टैंकर की जब्ती को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। (बाएं) एपी

होर्मुज स्ट्रेट में अपने जहाजों को सुरक्षा देगी ब्रिटिश नौसेना

लंदन, एएफपी : ईरान की जल सीमा के सटी होर्मुज स्ट्रेट (खाड़ी) से गुजरने वाले ब्रिटेन के जहाजों की सुरक्षा का जिम्मा ब्रिटिश नौसेना को सौंपा गया है। ब्रिटेन सरकार ने यह कदम खाड़ी में ईरानी सैनिकों के ब्रिटिश जहाज को जब्त करने के कदम के बाद उठाया है। इससे पहले चार जुलाई को ब्रिटिश नौसेना ने सीरिया जा रहे ईरानी तेल टैंकर को जिब्राल्टर के पास जब्त किया था। उसके चालक दल के सदस्यों में ज्यादातर भारतीय हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदी भारतीयों को स्वस्थ और सुरक्षित बताया है।

ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि जिस भी जहाज पर ब्रिटेन का झंडा लगा होगा, नौसेना उन सभी को सुरक्षा देगी। यह बयान हफ्ते भर से ब्रिटिश झंडे वाले जहाज स्टेना इंपेरो को ईरान द्वारा रोके जाने के बाद आया है। जहाज पर सवार चालक दल के 23 सदस्य ईरान के कब्जे में हैं। इस बीच फ्रांस ने कहा है कि वह खाड़ी में अतिरिक्त कुमुक नहीं भेजने जा रहा। लेकिन तैनात बल से मिलने वाली सूचनाओं को साझा करने में उसे कोई हर्ज नहीं है। स्टेना इंपेरो को रोकने से पहले ईरान ने अपने तेल टैंकर को जिब्राल्टर के पास रोके जाने पर ब्रिटेन को चेताया था।

ब्रिटेन-ईरान की तनातनी में फंसे भारतीयों में से नौ रिहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईरान ने समुद्री जहाज एमटी रियाह से हिरासत में लिए गए 12 भारतीयों में से नौ को गुरुवार को रिहा कर दिया। इन भारतीयों को जुलाई के पहले सप्ताह में हिरासत में लिया गया था। इस जहाज के तीन कर्मी अभी ईरानी हिरासत में हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश जहाज स्टेना इम्पेरो के चालक दल में शामिल 18 भारतीय भी ईरानी हिरासत में हैं। इस प्रकार से कुल 21 भारतीय ईरान के कब्जे में हैं। स्टेना जहाज को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पिछले सप्ताह होर्मुज स्ट्रेट में कब्जे में लिया था।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
स्पोर्ट्स
शुक्रवार 26 जुलाई 2019
www.jagran.com

भारतीय पुरुष हॉकी टीम में क्वालिटी तो है, लेकिन टीम को लगातार सुधार की जरूरत है।
— धनराज पिल्लै, पूर्व भारतीय कप्तान

टेटे में हम एक दिन पदक जीतेंगे : रिजिजू

नई दिल्ली : केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को टेबल टेनिस में भारत के प्रदर्शन की सराहना की और उम्मीद जताई कि एक दिन भारत इस खेल में ओलंपिक पदक जरूर जीतेगा। रिजिजू ने यह बात अल्टिमेट टेबल टेनिस लीग (यूटेटे) के तीसरे सीजन के उद्घाटन मौके पर कही। भारत ने हाल ही में टेबल टेनिस में अच्छी सफलता हासिल की है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में हालिया प्रदर्शन इस बात का गवाह है।

एकमात्र टेस्ट ▶ आयरलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 209 रन पर गंवाए पांच विकेट

विश्व विजेता इंग्लैंड पर मंडराया हार का खतरा

रॉय ने लगाया टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

14 जुलाई को आइसीसी विश्व कप का खिताब उठाने वाली इंग्लैंड टीम की एशेज सीरीज की तैयारियों को करारा झटका लगा है। लॉर्ड्स में पड़ोसी देश आयरलैंड के खिलाफ एक मात्र टेस्ट में दूसरे दिन चायकाल तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में पांच विकेट खोकर 209 रन बना लिए हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 87 रन की ही बढ़त हो पाई है। कप्तान जो रूट 12 और मोइन अली सात रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पहले दिन आयरलैंड ने इंग्लैंड को 87 रनों पर ढेर करके शर्मसार किया था। जबकि आयरलैंड पहले का खेल खत्म होने तक 207 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।

दूसरे दिन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 26 रनों पर ही सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स (06) का विकेट गंवा दिया था। उन्हें रैंकिन ने पवेलियन भेजा। इसके बाद जैक लीच (92) और जेसन रॉय (72) ने दूसरे विकेट लिए 145 रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड की टीम को संभाल लिया। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर हालांकि रॉय को स्टुअर्ट थॉमसन ने बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। रॉय ने 78 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। रॉय का यह उनके टेस्ट करियर में पहला अर्धशतक था। हालांकि इसके बाद रीच भी चलते बने। रीच को टिम मुर्टाघ ने 92 रनों पर पवेलियन भेजा। उन्होंने 162 गेंद का सामना करते हुए 16 चौके लगाए। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने की वजह से इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंस गई। जो डेनली (10) भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके और उन्हें केविन ओ ब्रायन ने रन आउट करके चलता कर दिया। डेनली के जाने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (00) के रूप में मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा। बेयरस्टो को अडेर ने पवेलियन भेजा। टीम को संभालने की जिम्मेदारी इसके बाद कप्तान रूट और मोइन अली के कंधों पर आ गई। दोनों ने इसके बाद इंग्लैंड का कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। आयरलैंड के लिए मुर्टाघ, अडेर, रैंकिन और थॉमसन ने एक-एक विकेट निकाला।

रॉय को आइसीसी की बधाई

लंदन : 47 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करने वाले जेसन रॉय को आइसीसी ने बधाई दी। पहली पारी में रॉय हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए थे। आइसीसी ने ट्विटर पर रॉय को बधाई देते हुए लिखा कि कोई बल्लेबाज को वनडे क्रिकेट से बाहर निकाल सकता है, लेकिन कोई वनडे क्रिकेट को बल्लेबाज के दिमाग से नहीं निकाल सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट ने भी लाल गेंद के क्रिकेट में रॉय के पहले अर्धशतक पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि रॉय का लाल गेंद की क्रिकेट में भी जलवा बरकरार है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक ने 24 जुलाई को रॉय को टेस्ट कैप सौंपी थी।

बचपन का सपना पूरा हुआ : मुर्टाघ

लंदन, एएफपी : डायल एम, यह किसी नंबर कॉलिंग के लिए नहीं, बल्कि आयरलैंड के गेंदबाज टिम मुर्टाघ का निकनेम है। मुर्टाघ ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर दमदार प्रदर्शन करते हुए नौ ओवर में केवल 13 रन दिए और पांच विकेट झटके। मिडिलसेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने वाले मुर्टाघ एक टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले आयरलैंड के पहले गेंदबाज बने। लंदन में जन्मे मुर्टाघ का यहां तक का सफर काफी दिलचस्प है। वह 2012 में ही आयरलैंड में खेलने के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब हुए। इसका कारण यह था कि उनके दादा-दादी डबलिन में पैदा हुए थे। खास बात यह है कि वह साल 2000 में अंडर-19 विश्व कप में इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे। मुर्टाघ ने अपने इस शानदार स्पैल के बाद कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। यह हर क्रिकेटर के लिए एक सपना होता है कि वह लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच खेले, इसी के कारण मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। मौजूदा टेस्ट गेंदबाजों में वह जेम्स एंडरसन के बाद सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। एंडरसन के नाम 950 प्रथम श्रेणी विकेट दर्ज हैं जबकि मुर्टाघ के 805 विकेट हैं। लॉर्ड्स 12 साल तक उनका घरेलू मैदान रहा है, जब उन्होंने 2007 में सरे से मिडिलसेक्स जॉइन किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान की उन्हें बड़ी समझ है और इसी के चलते इस मैदान पर उनके नाम 291 प्रथम श्रेणी विकेट दर्ज हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को मुर्टाघ ने सबसे तेज पांच विकेट (गेंदों के लिहाज से) झटके। उन्होंने केवल 44 गेंद फेंकी।

आउट होने के बाद वापस लौटते अर्धशतकीय पारी खेलने वाले जैक लीच। एपी

रंगीन मिजाजी में फंसे इमाम

पाक क्रिकेटर इमाम उल हक पर कई महिलाओं को धोखा देने का आरोप

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक पर कई लड़कियों को धोखा देने का आरोप लगा है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में लड़कियों और इमाम के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह बल्लेबाज विवादों में घिर गया।

आरोप है कि पिछले छह महीने के दौरान इमाम ने एक ही समय में सात से आठ लड़कियों को डेट कर उनके साथ धोखाधड़ी की। स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अनाम व्यक्ति ने कहा है कि यह तो कुछ नहीं है, उसके पास इमाम की हरकतों के सबूत वीडियो और तस्वीरों की शक्ल में भी मौजूद हैं लेकिन इन्हें वह तभी पोस्ट करेगा जब संबंधित लड़कियों की इस पर रजामंदी होगी।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के मुख्य चयनकर्ता और पूर्व बल्लेबाज इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम की हरकत की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है लेकिन बोर्ड ने किसी कार्रवाई से इन्कार कर दिया। बोर्ड के मीडिया निदेशक समी उल हसन के मुताबिक, बोर्ड इस बारे में कोई बयान जारी करने से परहेज करेगा, क्योंकि यह इमाम का निजी मामला है।

...और भी फंसे इन चक्करों में

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज इमाम उल हक ही नहीं, कई ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो इन आरोपों में फंस चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न, पाकिस्तान के शाहीद अफरीदी, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ भी इन चक्करों में फंस चुके हैं।

वार्न ने कबूला : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज वार्न सिर्फ फिरकी के ही जादूगर नहीं रहे हैं। मैदान के बाहर वह हजारों महिलाओं से संबंध बनाने का दावा करते रहे हैं। वार्न गर्व से यह बताते हैं कि हजारों महिलाओं के साथ सोने के बावजूद वह सिर्फ पांच बार ही पकड़े गए। हेलन कोहेन, एंगेला गलागर, लॉरा सेयर्स, केरी कोलीमोर, लिज हर्ले, क्लोई कॉनरेड के साथ उनके किस्से खूब मशहूर हुए और उनकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी मीडिया में बार-बार छाईं।

शाहीद भी कम नहीं : साल 2000 में सिंगापुर में शाहिद अफरीदी अपनी टीम के दो साथियों अतीक उज जमां और हसन रजा के साथ कराची के एक होटल के कमरे में लड़कियों के एक ग्रुप के साथ मनोरंजन करते हुए पकड़े गए थे। तब शाहिद 20 साल के थे। बाद में सभी खिलाड़ियों ने दावा किया कि वे लड़कियां ही उनकी प्रशंसक थीं और वे सिर्फ ऑटोग्राफ दे रहे थे। हालांकि इन तीनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया था और उस समय केन्या में होने वाली आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था।

रऊफ पर लगे आरोप : पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ आइपीएल की स्पॉट फिक्सिंग में भले बोल्ड हो गए हों, लेकिन इश्क की पिच पर खूब खेले। हालांकि उन्हें तब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब मॉडल लीना कपूर ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। रऊफ का नाम लीना के साथ कई दिनों तक जोड़ा गया, लेकिन रऊफ ने सार्वजनिक तौर पर इसे कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी लीना के साथ कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चली थीं।

पाक खिलाड़ी इमाम उल हक। फाइल फोटो

नदीम के पंच ने वेस्टइंडीज-ए को बड़े स्कोर से रोका

क्रिकेट डायरी

नॉर्थ साउंड, एएफपी : बायें हाथ के स्पिन गेंदबाज शाहबाज नदीम (5/62) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत-ए ने यहां सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को वेस्टइंडीज-ए को पहली पारी में महज 228 रनों पर ढेर कर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत-ए ने अपनी पहली पारी में एक विकेट खोकर 70 रन बना लिए हैं। उस समय प्रियंक पांचाल 31 और शुभमन गिल नौ रन बनाकर खेल रहे थे। भारत ने अपना एकमात्र विकेट सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन (28) के रूप में 61 के कुल स्कोर पर खोया।

इससे पहले, विंडीज-ए के कप्तान शरमाह ब्रूक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मेजबान टीम के लिए रहकीम कोर्नेवाल ने सबसे अधिक 59 रन बनाए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 100 गेंदों का सामना किया और सात चौकों के अलावा तीन छक्के लगाए। दूसरे सर्वोच्च स्कोरर जैरेमेन ब्लैकवुड रहे, जिन्होंने 53 रन की अपनी पारी के दौरान 116 गेंदें खेलीं तथा छह चौके लगाए। इन दोनों के अलावा विंडीज-ए का कोई और बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जमा सका। भारत के लिए नदीम के अलावा मुहम्मद सिराज और मयंक मार्कंडेय ने दो-दो विकेट लिए। शिवम दुबे को एक सफलता मिली।

भारत की अंडर-19 टीम जीती

वोरसेस्टर (इंग्लैंड), प्रेट्र : कप्तान प्रियम गर्ग (नाबाद 100) के शानदार शतक के बाद कार्तिक त्यागी (4/16) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच में गुरुवार को बांग्लादेश अंडर-19 टीम को 35 रन से हरा दिया। सीरीज की तीसरी टीम मेजबान इंग्लैंड अंडर-19 है। भारत की सीरीज में यह लगातार दूसरी जीत है। उसने इससे पहले मेजबान इंग्लैंड को भी मात दी थी। भारतीय टीम अब अंक तालिका में दो मैचों में चार अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में पांच विकेट पर 264 रन का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 47.1 ओवर में 229 रन पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश के लिए कप्तान अकबर अली ने 56, शमीम हुसैन ने 46, तंजीत हसन ने 44 और मृत्युंजय चौधरी ने 33 रन बनाए। भारत की ओर से कार्तिक त्यागी के चार विकेटों के अलावा शुभांग हेगडे ने तीन, रवि बिश्नोई ने दो और पूर्णांक त्यागी ने एक विकेट लिया। इससे पहले, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 264 रन का स्कोर किया। कप्तान गर्ग ने 97 गेंदों की अपनी नाबाद शतकीय पारी में सात चौके और चार छक्के लगाए। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल ने 63, ध्रुव जुरेल ने 34 और तिलक वर्मा तथा प्रग्नेश कांपिलेवर ने 23-23 रन बनाए। बांग्लादेश अंडर-19 टीम के लिए मृत्युंजय चौधरी ने दो और तंजीम हसन शाकिब, शमीम हुसैन तथा रबिकुल हसन ने एक-एक विकेट लिए।

ओप्पो की जगह लेगा बायजूस

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर सितंबर के बाद से चीनी स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो की जगह बायजूस ब्रांड का नाम दिखेगा। बायजूस बेंगलुरु स्थित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन ट्यूटोरियल फर्म है। भारतीय टीम की जर्सी पर वेस्टइंडीज दौरे तक ओप्पो का लोगो रहेगा। वेस्टइंडीज दौरा तीन अगस्त से शुरू होगा और दो सितंबर को समाप्त होगा। दक्षिण अफ्रीका 15 सितंबर से भारत का दौरा करेगी और इस सीरीज के साथ मेजबान टीम की जर्सी पर लगा लोगो भी बदल जाएगा। मार्च 2017 में ओप्पो ने 1079 करोड़ रुपये में पांच साल के लिए (मार्च 2022 तक) भारतीय टीम के प्रायोजक का अधिकार हासिल किया था। हालांकि, एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कंपनी ने इस सौदे से अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि उसका मानना है सौदे की कीमत बहुत ही अधिक है और वे इसे जारी नहीं रख सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को 31 मार्च, 2022 तक उस सौदे की रकम बाइजू से मिलती रहेगी।

विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने पर विचार करेंगे नीरज

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को कहा कि वह इस साल के आखिर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने पर विचार करेंगे।

नीरज ने यह बयान तब दिया जबकि यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया। इससे पहले इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि नीरज ने 27 सितंबर से छह अक्टूबर के बीच दोहा में होने वाली चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया है या नहीं। अधिकारियों की इस बारे में स्पष्ट राय नहीं थी कि उनका जालाहली में 68वीं अखिल भारतीय अंतर सेना एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 83.90 मीटर तक भाला फेंकने के प्रयास पर विश्व चैंपियनशिप के क्वालीफिकेशन के लिए विचार किया जाएगा या नहीं। लेकिन अब पता चला है पिछले साल 17 से 20 सितंबर को हुआ यह टूर्नामेंट मानदंडों पर खरा उतरा है। विश्व चैंपियनशिप के लिए पुरुषों के भाला फेंक का क्वालीफिकेशन मार्क 83 मीटर था।

ओपेलका ने इस्नर को किया टूर्नामेंट से बाहर

टेनिस डायरी

ओपेलका ने गत विजेता जॉन को 7-6, 6-7, 7-6 से हराया

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी रेली ओपेलका ने अटलांटा ओपन के दूसरे दौर में उलटफेर करते हुए दो बार के गत चैंपियन जॉन इस्नर को चौंकाकर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ओपेलका ने तीन सेट तक चले इस मुकाबले को 7-6, 6-7, 7-6 से अपने नाम किया।

21 वर्षीय ओपेलका ने पहला सेट टाई-ब्रेक में जीता। इसके बाद इस्नर ने दूसरा सेट जीतकर मैच में जरूर वापसी की लेकिन ओपेलका ने उन्हें यह सेट आसानी से जीतने नहीं दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर तीसरे सेट में भी देखने को मिली जब यह सेट भी टाई-ब्रेक में गया और इसे ओपेलका ने अपने नाम किया।

गैर वरीयता प्राप्त ओपेलका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फरवरी में न्यूयॉर्क ओपन में भी इस्नर को पराजित किया था। फरवरी में ओपेलका ने अपना पहला एटीपी खिताब जीता था। ओपेलका ने कहा, 'इस्नर को हराना मेरे लिए खास है। मैंने अच्छा टेनिस खेला। इस्नर के खिलाफ तीनों सेट टाई-ब्रेक में खेलना मुश्किल था। मैं इस जीत से खुश हूं। उन्होंने कई बार यह खिताब जीता है। उन्हें इस टूर्नामेंट में हराना काफी मुश्किल काम होता है।' शीर्ष वरीय इस्नर दो बार के गत चैंपियन हैं और 10 में से नौ बार अटलांटा फाइनल में पहुंचे थे।

ब्रायन बंधुओं से भिड़ेंगे दिविज और एर्लिच : भारतीय टेनिस खिलाड़ी दिविज शरण और जोनाथन एर्लिच ने अटलांटा ओपन के पहले दौर में मियोमिर केचमानोविक और रोबर्ट लिंडस्टेड की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई जहां उनका सामना ब्रायन बंधुओं माइक और बॉब की दिग्गज जोड़ी से होगा। दिविज और एर्लिच ने टूर्नामेंट के पहले दौर में 2-6, 6-3, 13-11 से जीत दर्ज की। जोड़ी के रूप में 100 से अधिक एटीपी खिताब जीतने वाले ब्रायन बंधुओं ने पहले दौर में क्रिस्टोफर युबेंक्स और डोनाल्ड यंग की अमेरिकी वाइल्ड कार्ड जोड़ी को आसानी से 6-4, 6-2 से हराया।

वहीं, भारत के दिग्गज लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार मॉरियस कोपिल को ब्रिटेन के टेलर फ्रिट्ज और अमेरिका के कैमरन नोरी की जोड़ी के खिलाफ सीधे सेटों में 6-7, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगल्स में हिस्सा ले रहे एकमात्र भारतीय प्रजनेश गुणेश्वरन भी बुधवार को पहले दौर में हार गए थे।

रामकुमार पहले दौर में हारे

बिनगैमटन (अमेरिका) : भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन को पहला सेट जीतने के बावजूद यहां बिनगैमटन चैलेंजर के पहले दौर में अपने से कम रैंकिंग वाले अमेरिका के वाइल्ड कार्ड धारक अलेक्जेंडर रिचार्ड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले दौर में बाई हासिल करने वाले दूसरे वरीय रामकुमार को हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट के पहले दौर में दुनिया के 443वें नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी के खिलाफ 6-2, 6-7, 2-6 से हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए। करियर के सर्वश्रेष्ठ 167वीं रैंकिंग और अच्छी फॉर्म के साथ यहां पहुंचे रामकुमार की हार हैरान करने वाली है। रामकुमार हाल में सुरबिटोन ट्रॉफी चैलेंजर में उप विजेता रहे थे जबकि इटली में गुजिनी चैलेंजर का खिताब जीता था।

जीत के बाद जश्न मनाते रेली ओपेलका। एपी

यह समय भारतीय टेबल टेनिस के लिए अच्छा : सौम्यदीप रॉय

साक्षात्कार

भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने पिछले दो वर्षों में बहुत कामयाबी हासिल की है। कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर एशियन गेम्स और अब कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भी भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। अल्ट्रा टेबल टेनिस लीग शुरू होने के बाद से भारतीय टेबल टेनिस बहुत आगे निकला। भारतीय टेबल टेनिस के इस सफर पर निखिल शर्मा ने लीग की टीम यू मुंबा के कोच सौम्य दीप रॉय से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :-

सौम्यदीप रॉय। फाइल फोटो

● मौजूदा समय को भारतीय टेबल टेनिस के लिहाज से किस तरह देखते हैं?

-भारतीय टेबल टेनिस ने पिछले दो वर्षों में काफी अच्छा किया है। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और लगातार पदक जीत रहे हैं। खासकर युवा खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जो वाकई बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से यह समय भारतीय टेबल टेनिस के लिए अच्छा है।

● हरमीत देसाई और अहिका मुखर्जी ने ओडिशा में सभी को चौंकाते हुए कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीते। आप क्या कहेंगे?

- हरमीत और अहिका शानदार खेले। उन्होंने कई अच्छे खिलाड़ियों को हराया। दोनों वाकई भारत का भविष्य हैं।

● यह सब तब शुरू हुआ जब से अल्ट्रा टेबल टेनिस लीग शुरू हुई। भारतीय टेबल टेनिस को आगे ले जाने में लीग का कितना रोल है?

-हां, यह सब कॉमनवेल्थ गेम्स से शुरू हुआ, जहां हमने काफी पदक जीते। हमने एशियन गेम्स में भी पदक जीते जिससे हमे काफी आत्मविश्वास मिला है। आप कह रहे हैं टेबल टेनिस लीग के बाद हुआ, तो घर में विश्व स्तर के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने से हमें फायदा तो मिला है।

● लीग का तीसरा सत्र शुरू हो गया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?

- हमें यहां कई शीर्ष स्तरीय खिलाड़ियों के साथ शीर्ष खेल देखने को मिलेगा। यहां चुआंग ची युआन, जी साथियान, शरत कमल और डू होई केम जैसे खिलाड़ी खेलेंगे। मुझे लगता है कि सभी टीम संतुलित हैं और हर मुकाबले मुश्किल होंगे। यह लीग काफी रोमांच से भरी होने वाली है।

● क्या आपने अपनी टीम यू मुंबा के संयोजन को समझा है?

- मुझे लगता है कि हमारी टीम यू मुंबा टेबल टेनिस लीग की सबसे संतुलित टीम है। हांगकांग के होई केम हमारी टीम की यूएसपी हैं। हमारे पास मिक्स्ड डबल्स में किरिल गेरासिमेंको जैसे अनुभवी और मानव ठक्कर जैसे युवा खिलाड़ी हैं। सुतीर्थ मुखर्जी भी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। ऐसे में हमारी टीम का संयोजन बहुत अच्छा है और इसके बारे में चिंता की बात कोई नहीं है।

फुटबॉल डायरी

स्पोर्टिंग के ब्रूनो फर्नांडीज ने मैच के चौथे मिनट में गोल करके टीम का खाता खोला था। हालांकि लिवरपूल के डीवॉक ओरिजी ने 16 मिनट बाद ही गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया

लिवरपूल ने स्पोर्टिंग सीपी के खिलाफ खेला ड्रॉ

वाशिंगटन, एएफपी : इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल अपने अमेरिकी दौरे पर स्पोर्टिंग सीपी के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सका और टीम को 2-2 से मुकाबला ड्रॉ खेलना पड़ा। लिवरपूल की टीम इस दौरे पर तीन मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है और पुर्तगाल के क्लब के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आई।

स्पोर्टिंग सीपी के ब्रूनो फर्नांडीज ने मैच के चौथे मिनट में गोल करके टीम का खाता खोला था। हालांकि लिवरपूल के डीवॉक ओरिजी ने 16 मिनट बाद ही गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। पहला हाफ खत्म होने में सिर्फ एक मिनट बचा था और ऐसे में जॉर्जीनीयो वायनालडम स्पोर्टिंग सीपी के डिफेंस को तोड़कर अपनी टीम लिवरपूल को मैच में 2-1 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में भी स्पोर्टिंग सीपी के मार्कस वैंडल वेले डिसिल्वा को स्कोर 2-2 से बराबर करने में ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने 53वें मिनट में गोल दाग दिया। हालांकि मैच में लिवरपूल के मैनेजर जुर्गेन क्लोप ने अपने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों फॉरवर्ड रोबर्टो फिरमिनो, मुहम्मद सलाह और सादियो माने को इस मैच के लिए आराम दिया था। ये तीनों खिलाड़ी कोपा अमेरिका और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में खेले थे। 17 साल के सेप वैन डेन बर्ग ने लिवरपूल के लिए अपना पहला मैच खेला।

मेराडोना के घुटनों की सफल सर्जरी हुई

ब्यूनस आयर्स, एएफपी : अर्जेंटीना के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान डिएगो मेराडोना के घुटनों की सर्जरी सफल रही। उनके वकील ने बताया कि ब्यूनस आयर्स के एक क्लिनिक में बुधवार को उनकी सर्जरी की गई, जो सफल रही। मेराडोना ने स्वास्थ्य कारणों से पिछले महीने मेक्सिको के सेकेंड डिविजन क्लब डोराडोस के कोच पद से त्यागपत्र दे दिया था। वह इस क्लब से केवल नौ महीने ही जुड़े रहे। उनके वकील माटियस मोरला ने जानकारी दी कि उन्हें घुटनों और कंधों के सर्जरी की जरूरत थी। उन्होंने ट्वीट किया, 'सब कुछ ठीक रहा।' मेराडोना का विवादों से गहरा नाता रहा है। फुटबॉल की दुनिया का यह महान खिलाड़ी ड्रग्स की लत को लेकर भी विवादों में रह चुका है। दुनिया मेराडोना को मेक्सिको में वर्ष 1986 में खेले गए फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उनके विवादित गोल 'हैंड ऑफ गॉड' के लिए भी जानती है। अर्जेंटीना ने मेक्सिको में खेले गए इस विश्व कप में मेराडोना की कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी। 1997 में करियर की समाप्ति के बाद से उन्हें लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हैं।

भारत फीफा रैंकिंग में दो पायदान नीचे 103वें नंबर पर खिसका

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की गुरुवार को जारी विश्व रैंकिंग में दो पायदान नीचे 103वें स्थान पर खिसक गई। भारत इस महीने के शुरू में अहमदाबाद में इंटरकोंटिनेंटल कप में दो मैच हार गया था, जबकि एक मैच उसने ड्रॉ खेला था। भारत ताजिकिस्तान से 2-4 से और उत्तर कोरिया से 2-5 से हार गया था, जबकि सीरिया के खिलाफ उसने 1-1 से ड्रॉ खेला था। भारत के 1214 रैंकिंग अंक हैं और पिछली बार से उसके पांच अंक कम हुए हैं। भारतीय टीम अब एशियाई देशों में 18वें स्थान पर है। ईरान (23वां) एशियाई देशों में शीर्ष पर है। उसके बाद जापान (33), कोरिया (37), ऑस्ट्रेलिया (46) और कतर (62) का नंबर आता है। विश्व रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर है। उसके बाद ब्राजील, फ्रांस, इंग्लैंड और उरुग्वे हैं।

मैच के दौरान गेंद पर काबू पाने का प्रयास करते लिवरपूल और स्पोर्टिंग सीपी के खिलाड़ी। एपी

सिंधू और प्रणीत क्वार्टर फाइनल में, प्रणय बाहर

टोक्यो, प्रेट्र : ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधू और बी साई प्रणीत गुरुवार को शानदार जीत दर्ज कर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, लेकिन एचएस प्रणय को हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।

महिला सिंगल्स के दूसरे दौर के मैच में पांचवीं वरीय सिंधू को जापान की गैरवरीय अया ओहोरी को एक घंटे तक चले मुकाबले में 11-21, 21-10, 21-13 से हराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 750 टूर्नामेंट में ताजा जीत के साथ सिंधू का ओहोरी के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 8-0 हो गया है। सिंधू का सामना अब चीन की चेन जिआओ जिन और चौथी वरीय जापान की अकाने यामागुची के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से होगा। सिंधू को पिछले सप्ताह इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में यामागुची के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

वहीं, साई प्रणीत ने भी पुरुष सिंगल्स के 45 मिनट तक चले मुकाबले में स्थानीय शटलर केंता सुनेयामा को 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। साई प्रणीत अंतिम आठ के दौर में इंडोनेशिया के टॉमी सुगिआर्तो से भिड़ेंगे।

चोटी पर दुश्मन सामने जवान का सीना

इतिहास जंग की दास्तानों से भरा पड़ा है। और सभी जंग करीब-करीब बराबर के लोगों, समुदायों और देशों के बीच हुई हैं। क्षमता में पासंग होने पर हथियार डाल दिए जाने का रिवाज रहा है, युद्ध की नौबत ही नहीं आती। लेकिन कारगिल जंग ने इस परंपरागत रूप से चले आ रहे सच को गलत साबित कर दिखाया। दुश्मन चोटी पर था, सीना ताने भारतीय जवान पहाड़ी के नीचे उसे ललकार रहे थे। जान की परवाह नहीं की। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों के जरिए देश में घुसपैठ करने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को भारतीय सेना ने चूर-चूर किया था। लगभग 60 दिनों तक युद्ध चला। 20 साल पहले आज (26 जुलाई) ही के दिन 1999 में कारगिल जंग में विजय की घोषणा हुई थी। इस जंग के बाद देश में एक पूरी पीढ़ी तैयार हो चुकी है, जो इस जंग के अमर शहीदों की वीरता और शौर्य से प्रेरित और गर्वित होगी। हर भारतीय के लिए यह दिन राष्ट्रभक्ति के भाव से भर देने वाला है। पेश है एक नजर

ऑपरेशन बद्र की नापाक साजिश

1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होते रहे। दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम 'ऑपरेशन बद्र' रखा। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। वह भारत का संपर्क एनएच-1 से पूरी तरह काट देना चाहता था।

बड़े हमले का मुंहतोड़ जवाब

शुरुआत में इसे घुसपैठ माना गया और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा पर खोजबीन और इन घुसपैठियों की रणनीति का पता चलने के बाद भारतीय सेना को अहसास हो गया कि हमले की योजना बड़े पैमाने पर की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत दो लाख सैनिकों को मोर्चे पर भेजा। मई से शुरू हुआ यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ।

अपनों ने ही खोली साजिशकर्ता मुशर्रफ की पोल

पाकिस्तान ने दावा किया कि इस युद्ध को लड़ने वाले सभी कश्मीरी आतंकी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। माना जाता है कि सेनाध्यक्ष बनने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही इसे अंजाम दिया था।

पाक के तत्कालीन प्रधानमंत्री **नवाज शरीफ** ने भी अपनी भूमिका से इंकार किया था और मुशर्रफ को ही जिम्मेदार ठहराया था। इतना ही नहीं मुशर्रफ के रिश्तेदार ले. जनरल (रि.) शाहिद अजीज ने अपनी पुस्तक 'ये खामोशी कहां तक' और पाक सेना में कर्नल रहे अशफाक हुसैन ने 'विटनेस टू ब्लंडर-कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स' नाम की अपनी किताब में मुशर्रफ की भूमिका को स्पष्ट किया है और दोषी ठहराया है।

पाकिस्तान में तख्तापलट

पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर **परवेज मुशर्रफ** राष्ट्रपति बने।

दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देशप्रेम का उबाल देखने को मिला। देश एकसूत्र में और मजबूती से एकजुट हुआ। भारत सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया।

चरवाहों से मिली घुसपैठ की सूचना

'विटनेस टू ब्लंडर- कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स' में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की 6 नार्दर्न लाइट इंफैंट्री के कैप्टन इफ्तेखार और लांसनायक हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे तभी उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पहले तो उन्होंने बंदी बनाना चाहा लेकिन बाद में जाने दिया। करीब डेढ़ घंटे बाद यही चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे। दूरबीनों से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। कुछ घंटे बाद वहां एक लामा हेलिकॉप्टर उड़ता हुआ आया। वह काफी नीचे था। यही पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है।

20 वर्षों में भारतीय सेना मीलों आगे निकल गई है। हमारी फौज अब पहले से कहीं ज्यादा पेशेवर है। ट्रेनिंग से लेकर उपकरणों तक...हर क्षेत्र में हम दुनिया की श्रेष्ठतम सेनाओं में गिने जाते हैं। कारगिल जैसी घटनाएं अब नहीं हो सकतीं। सरकारों ने भी सेना पर फोकस बढ़ाया। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क डालता है देशवासियों का विश्वास।

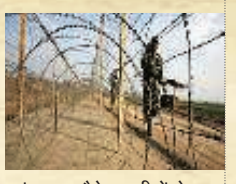

योगेंद्र सिंह यादव,
परमवीर चक्र विजेता-कारगिल युद्ध

हर मिनट एक राउंड फायर

इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब दो लाख पचास हजार गोले दागे गए। वहीं, 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट एक राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी।

18 हजार फीट पर लड़ी लड़ाई

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। मिग-29 से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर आर-77 मिसाइलों से हमला किया गया। यह युद्ध करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर हुआ। दोनों देशों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

किसका कितना नुकसान

भारत
527 शहीद 1363 घायल 1 युद्धबंदी
1 लड़ाकू विमान और 1 हेलीकाप्टर गिरा
1 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

पाकिस्तान
453 सैनिक मारे गए (तटस्थ रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम 700 पाक सैनिक मारे गए।)
700 के आसपास घायल
8 युद्धबंदी

13 जेएंडके राइफल एक युद्ध में दो परमवीर चक्र हासिल करने वाली पहली रेजिमेंट बनी

2 राजस्थान राइफल रेजिमेंट ऑपरेशन विजय में 4 महावीर, 7 वीर चक्र हासिल करने वाली पहली रेजिमेंट बनीं

भारतीय तोपखाने ने रोजाना 5 हजार गोले दाग पूरे युद्ध में ढाई लाख गोले दागे

थल सेना को 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र, 55 वीर चक्र और वायुसेना को 2 वीर चक्र मिले

माइनस डिग्री तापमान में भी नहीं डगमगाए थे कदम

शौर्यगाथा कारगिल हीरो ब्रिगेडियर ठाकुर की जुबानी

आज सारा देश कारगिल विजय की 20वीं सालगिरह मनाएगा और जांबाजों को श्रद्धासुमन अर्पित करेगा। 18 हजार फीट ऊंची चोटी पर थे दुश्मन और इधर नहीं थी घास के तिनके की भी ओट...। माइनस डिग्री तापमान...। पर तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद नहीं डगमगाए थे हमारे रणबांकुरों के कदम...। कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर की जुबानी कारगिल विजय की कहानी। विशेष प्रस्तुति।

कमलेश वर्मा • कुल्लू

माइनस डिग्री तापमान। बर्फबारी और तेज हवाएं। 18 हजार फीट ऊंची चोटी। पथरीली, सीधी चढ़ाई। छिपने के लिए घास का तिनका भी नहीं। ऑक्सीजन भी कम। ...और दुश्मन घात लगाए सिर पर बैठा था। ऑपरेशन विजय आसान न था। बस मन में एक ही जज्बा था कि दुश्मन को अपनी जमीन से खदेड़ कर उस पर जीत दर्ज करना है। इसी जज्बे को दिल में लिए भारतीय सेना के जवान आगे बढ़े और विजय पाई। 18 ग्रेनेडियर के जवान भी इस युद्ध में क्या खूब लड़े। तोलोलिंग चोटी पर तिरंगा फहराया। इसी तरह टाइगर हिल को फतह किया...।

देश के जवानों की वीरता की यह दास्तां 18 ग्रेनेडियर यूनिट का नेतृत्व करने वाले, कारगिल युद्ध के हीरो सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने बयां की। दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, आज भी उन कठिन हालात और उन पर काबू करने वाले हमारे असीम हौसले के बारे में सोचता हूं, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। युद्ध में एक पल भी ऐसा नहीं था, जब हमारे जवानों के कदम डगमगाए हों...।

ब्रिगेडियर ने कहा, कारगिल युद्ध को 20 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। वर्ष 1999 में जब 18 ग्रेनेडियर यूनिट को कारगिल युद्ध में जाने के आदेश हुए तो पूरी यूनिट के 900 जवान 15 मई को मोर्चे पर बढ़ गए। चोटी पर घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। अन्य यूनिट के जवानों के साथ 18 ग्रेनेडियर ने भी जमकर लोहा लिया। हमने टाइगर हिल को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाकर तिरंगा फहराया।

बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच दुश्मनों की गोलियों का जवाब देते हुए हमने सबसे पहले तोलोलिंग चोटी को फतह किया। दिन के समय जवान छोटे-छोटे पत्थरों के पीछे छिपते थे और वहां से दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखते थे। असीम शौर्य का परिचय देते हुए 18 ग्रेनेडियर के 35 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 95 जाबांज घायल हुए। घायल व शहीद हुए एक-एक जवान को आठ जवानों द्वारा नीचे पहुंचाया जाता था।

सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर • जागरण

खाद्य सामग्री की जगह भरा था असला-बारूद

बकौल ब्रिगेडियर ठाकुर, 18 ग्रेनेडियर की कमांडो टीम का नेतृत्व कैप्टन बलवान सिंह ने किया था। जवानों ने अपने खाने के सामान को कम करके उस स्थान पर भी असला और बारूद भर लिया था। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए 18 ग्रेनेडियर को 52 वीरता पुरस्कार दिए गए। 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व करने के लिए ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया।

तब तक युद्ध विराम नहीं...

ब्रिगेडियर ठाकुर के अनुसार, टाइगर हिल पर भारतीय सेना के तिरंगा फहराते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पास गए और उनसे बिना शर्त युद्ध विराम की गुहार लगाई, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब तक भारत की सीमा से सभी घुसपैठियों के खदेड़ नहीं दिया जाएगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा।

कश्मीरी युवाओं में जज्बा भरते हैं शहीदों के किस्से

सेना भर्ती में हिस्सा लेते कश्मीरी युवा • फाइल फोटो

विवेक सिंह • जम्मू

कारगिल युद्ध में कश्मीर निवासी छह सैनिकों की शहादत आज भी स्थानीय युवाओं में देशभक्ति की लौ जलाए हुए है। उनसे प्रेरणा ले कश्मीर के हजारों युवा पाकिस्तान पोषित अलगाववादियों और आतंकियों की धमकियों को दरकिनार कर फौज की वर्दी पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। इस समय कश्मीर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में सेना, सुरक्षाबलों के साथ वे युवा भी सहयोग दे रहें हैं, जो फौजी बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि अलगाववादी व आतंकवादी कश्मीर में अमन, शांति चाहने वाले इन युवाओं को भी अपना दुश्मन मानते हैं।

बारामूला के युवा शुरू से ही पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम बनाने में आगे रहे हैं। वर्ष 1947 में पाक सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश रची तो क्षेत्र के बीस साल के युवा मकबूल शेरवानी ने देश के लिए लड़ते हुए शहादत दी थी। कारगिल में भी कश्मीर के सैकड़ों जांबाजों ने न केवल पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी, बल्कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए हंसते-हंसते सीने पर गोलियां खाईं। बारामुला के शौकत हुसैन, लांस नायक गुलाम मुहम्मद खान, राइफलमैन रवींद्र सिंह, नायक दोस्त मुहम्मद खान, राइफलमैन मुस्ताक अहमद के साथ श्रीनगर के राइफलमैन असलम धर की कुर्बानी को देश आज भी याद करता है। यह सभी सेना की 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री (जैकलाइ) के लड़ाके थे। आज उनकी बहादुरी के किस्से कश्मीरीयुवाओं में देशप्रेम की अलख जगा रहे हैं।

वर्ष 2019 में भी आतंकियों की धमकियों को दरकिनार कर कश्मीर में दस हजार के करीब युवा भर्ती रैलियों में फौजी बनने के लिए जोर लगा चुके हैं। पिछले सप्ताह पट्टन के हैदरबाग में संपन्न हुई भर्ती रैली में 5,366 युवाओं ने भाग्य आजमाया। वहीं फरवरी माह में भी बारामूला में रैली में सैनिकों के 111 पदों के लिए 2500 युवाओं की भीड़ उमड़ी थी। इसके साथ ही सेना, टेरीटोरियल आर्मी के लिए हुई भर्ती रैलियों में भी युवाओं का खासा उत्साह देखने को मिला। हजारों कश्मीरी युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए लंबी कतारें लगाईं।

कश्मीर में नहीं शूरवीरों की कमी : कैप्टन बाना सिंह

परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह का कहना है कि कश्मीर में भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले शूरवीरों की कमी नहीं है। कारगिल के युद्ध में भी उनकी बहादुरी आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। आज कश्मीरी युवा ही देश के साथ खड़े होकर दुश्मन के इरादों को नाकाम बना रहे हैं।

मौत बनकर दुश्मन पर टूटे थे गुलाम मुहम्मद...

वीर चक्र विजेता बारामूला के लांस नायक गुलाम मुहम्मद खान 7 जून 1999 को रॉकेट लांचर के साथ कारगिल में प्वाइंट 5203 पर कब्जे की जंग में दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। उनकी पलटन ने चोटी पर पहुंचने के लिए नौ घंटे चढ़ाई की और दुश्मन की झलक मिलते ही उनपर कहर बनकर टूट पड़े। लांस नायक गुलाम मुहम्मद खान पर दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। घायल होने के बाद भी वह लड़ते रहे और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए।

निर्मला के जज्बे को सलाम

- बच्चों को सुनाती रहीं पति की जांबाजी की 'लोरियां'
- शहीद के बलिदान और परिवार के जज्बे की कहानी

शहीद मुन्नाराम की पत्नी निर्मला • जागरण

शहीद मुन्नाराम यादव (फाइल फोटो)

अतुल सिंह • बस्ती

कारगिल के युद्ध में पति मुन्ना राम यादव की शहादत के बाद शहीद की पत्नी निर्मला देवी ने प्रण लिया था कि दोनों बेटों को फौजी बनाएंगी। बड़े बेटे को सैनिक बनाने के बाद उन्होंने सारे गांव में मिठाई बांटी। कहा, मैंने अपना एक प्रण पूरा किया। अब छोटे बेटे को फौजी बनाने में जुटी हुई हैं।

बस्ती, उप्र के शहीद मुन्ना राम यादव के बड़े सुपुत्र अमित यादव आज सैनिक बन देश की रक्षा कर रहे हैं। बस्ती के मलौली गोसाई गांव निवासी मुन्ना राम यादव गंवई संस्कृति में पले-बढ़े थे और उनके भीतर देश प्रेम का जच्बा कूट-कूट कर भरा था। वर्ष 1985 में सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी ड्यूटी पाकिस्तान सीमा पर पेट्रोलिंग में लगी थी। उनकी शहादत की खबर आई तो ऐसा लगा कि वज्रपात हो गया है। गांव में भी मातम पसर गया।

निर्मला देवी कहती हैं कि पति की शहादत पर गर्व करते हुए कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे तीनों बच्चे उस समय छोटे थे। पालन-पोषण में कोई कमी नहीं की। बच्चों को पति की धरोहर मान आगे बढ़ाने का प्रण किया और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की हर संभव कोशिश की। बचपन से ही उनमें देश प्रेम का जच्बा जगाया। बड़ा बेटा अमित जवान हुआ तो पिता की तरह देश की रक्षा का संकल्प लिया और फौज में भर्ती होने निकल गया। वर्ष 2009 में सेना के इंजीनियरिंग कोर में भर्ती हो गया। अब वह पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। छोटा बेटा सुमित प्रयागराज में बीएससी दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। वह भी फौज में जाना चाहता है। वह दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन होगा।

सेना में तैनात अमित यादव • जागरण

सिंदूर हो गया अमर, तू कोख धन्य कर देना...

श्रवण कुमार शर्मा • मैनपुरी

कारगिल युद्ध को हुए बीस साल का लंबा दौर गुजर तो गया मगर लगता है कल की हो बात है। तिरंगे में लिपटा शहीद पति का पार्थिव देख वे अंदर से टूट ही गई थीं। लेकिन पति की शहादत पर गर्व ने जीने का मकसद भी दिया। बच्चों को पति की जांबाजी की कहानियां सुनाईं, देशभक्ति की लोरियां सुनाईं। जब बेटा सैनिक बना तो सपूत को सरहद पर ये कहकर भेज दिया- मेरा सिंदूर हो गया अमर, तू कोख को धन्य कर देना।

वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक सेना की घुसपैठ रोकने के लिए 3 ग्रेनेडियर्स बटालियन को भेजा गया था। यहां तैनात मैनपुरी, उप्र के गांव टिकरई निवासी नागेंद्र सिंह चौहान दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। नागेंद्र के तीन बेटे प्रमोद, अंकित और अमित हैं। उस समय अमित की उम्र करीब डेढ़ साल की थी। ममता ने बच्चों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। परवरिश तो की ही, अच्छी शिक्षा भी दिलाई। साथ ही पति की शहादत की कहानियां सुनातीं रहीं और बच्चों में देशभक्ति का जच्बा कायम किया। कहती हैं, मैं चाहती थी कि बच्चे सरहद पर जाकर दुश्मन से पिता की शहादत का बदला लें। छोटे बेटे अमित कुमार ने सेना में भर्ती होकर उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया। अमित वर्तमान में सिक्किम में तैनात है।

शहीद नागेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

शहीद नागेंद्र सिंह के सुपुत्र अमित कुमार

फीरोजाबाद, उप्र के नगला छबरैय्या निवासी ब्रजलाल यादव ने सरहद पर शौर्य दिखाया तो शहीद की पत्नी रूबी ने पति की शहादत का बदला लेने को बेटे को सरहद पर भेज दिया। ब्रजलाल जब वीरगति को प्राप्त हुए तब बेटा पुष्पेंद्र महज तीन साल का था। शहीद की पत्नी रूबी बताती हैं कि पति के बिछुड़ने का गम तो था ही, मगर बच्चों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पुष्पेंद्र को आगरा और फिर देहरादून में पढ़ाया। पुष्पेंद्र में सेना में जाने का जच्बा जगाया। एक साल पहले ही पुष्पेंद्र फौज में भर्ती हो गया है। वर्दी में बेटे को देखा तो लगा कि पति को श्रद्धांजलि अर्पित हो गई।

जज्बा देश सेवा का जज्बा ऐसा कि इनमें से एक की शहादत के बाद मां ने फौज में भेज दिया छठवें बेटे को भी, झुंझुनू जिले के सिंह परिवार की कहानी

पांच भाइयों ने एक साथ लड़ी थी कारगिल की लड़ाई

मदन श्योराण • भिवानी

प्रताप सिंह
सेवानिवृत्त सूबेदार-105 प्रादेशिक सेना

ए. पवन सिंह
सेवानिवृत्त सिपाही-105 प्रादेशिक सेना

बी. अशोक सिंह
105 प्रादेशिक सेना, ड्यूटी पर तैनात हैं

सी. लक्ष्मण सिंह
सेवानिवृत्त हवलदार-11 राज राइफल

डा. शहीद कंवरपाल सिंह
2 राज राइफल

मंगेश देवी। वीर सपूतों की मां। जिनके चरणों में आज इस अवसर पर हर भारतवासी को नमन-वंदन करना चाहिए। ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल में उनके पांच सपूत अलग-अलग मोर्चों पर दुश्मन से लोहा ले रहे थे। तब पूरे दिन अपने टीवी और रेडियो से चिपकी रहती थीं और ईश्वर से हर समय भारत की जीत और बच्चों की सलामती की दुआ करतीं। अपने पांच लालों को दुश्मनों से लड़ते देखने और एक की शहादत के बाद मंगेश ने छठी संतान को भी सेना में भेज दिया।

कारगिल युद्ध के 20 साल बाद भी उनके दो बेटे सेना में मोर्चा संभाले हुए हैं। तीन सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भिवानी, हरियाणा की जगत कॉलोनी में रहने वाले सिंह परिवार की बेटी हैं मंगेश देवी। उनकी ससुराल हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव बनगोठड़ी में है। बनगोठड़ी में रह रहे मंगेश देवी के बेटे सूबेदार प्रताप सिंह बताते हैं, हम पांचों भाई अलग-अलग यूनिट में थे। युद्ध के दौरान मुझे दिल्ली से बुलाया गया था। मैं 105 प्रादेशिक सेना में था। मेरे चार भाई लक्ष्मण सिंह, पवन सिंह, कंवर पाल सिंह और राम अवतार सिंह भी जम्मू में तैनात थे। पांचों भाइयों ने ठान रखा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हमें तब न अपनी चिंता थी और न परिवार की, बस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून सवार था।

प्रताप बताते हैं, इस युद्ध में भाई कंवरपाल सिंह तोतोलिंग की पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान दुश्मन का गोला गर्दन पर लगने के कारण शहीद हो गए थे। इस शहादत से हमें दुख तो पहुंचा, लेकिन हम इससे टूटे नहीं। हमने अपने छठे भाई को भी कारगिल युद्ध के बाद सेना में भेजा। छोटा भाई अशोक सिंह अब भी 105 प्रादेशिक सेना में है और ड्यूटी पर तैनात है।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

शुक्रवार 26 जुलाई 2019

14

www.jagran.com

पहला जियोसिंक्रोनस संचार उपग्रह लांच हुआ

1963 में आज ही नासा ने फ्लोरिडा के केप केनवरल से डेल्टा बी बूस्टर रॉकेट पर दुनिया का पहला संचार उपग्रह सिंकॉम 2 लांच किया। यह 0 .71 मीटर चौड़ा और 35 किग्रा वजनी था। इसके जरिए पहला सफल टेलीविजन ट्रांसमिशन किया गया।

पहले सौर ऊर्जा संचालित विमान ने लगाया पृथ्वी का चक्कर

2006 में आज ही सोलर इंपल्स–2 नाम के सौर ऊर्जा संचालित विमान ने पृथ्वी का चक्कर पूरा किया। 17 हजार सोलर सेल वाले इस विमान का वजन 2 .4 टन था। पायलट ब्रर्ट्रेंड पिक्कर्ड और एंड्रे बॉर्शबर्ग ने 505 दिनों में 42 हजार किमी की यात्रा पूरी कर विमान को अबूधाबी में उतारा।

ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने दादाभाई नौरोजी

1892 में आज ही देश के ग्रांड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादाभाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। वे लंदन की सेंट्रल फिंसबरी निर्वाचन क्षेत्र से 1892 से 1895 के बीच सांसद रहे। इनका जन्म 4 सितंबर, 1825 को मुंबई में हुआ था। शिक्षा के लिए लंदन गए। भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों के बारे में गहन अध्ययन किया। 1867 में उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी प्रस्तावित की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज भारत के चौथाई आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीयों के हितों के लिए ही उन्होंने वहां चुनाव लड़ा।

इधर-उधर की

खराब ड्राइविंग से पकड़ी गई ड्रग्स

सिडनी, एजेंसी : किस्मत खराब हो तो अर्जुन जैसे धनुर्धर के बाण भी निशाना चूक जाते हैं। कहीं अगर आप सिद्धहस्त नहीं हैं और आपकी किस्मत खराब हो, तो भगवान ही आपका मालिक है। इसी फेर में सिडनी में मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप पुलिस के शिकंजे में आई। यहां का एक आदमी 270 किग्रा मेथमफेटामाइंस से लदा वाहन लेकर जा रहा था। उसे कायदे से वाहन चलाना नहीं आता था। रास्ते में उसे सड़क किनारे पुलिस का एक गश्ती वाहन खड़ा दिखाई दिया। बस क्या था, महाशय के हाथ-पैर सुन्न हो गए। बौखलाहट में उसने पुलिस वाहन में ही टक्कर मार दी। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी तो तो सारा मामला सामने आया। उस व्यक्ति को खराब तरीके से गाड़ी चलाने और नशीली दवाओं की आपूर्ति के मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है।

शोध अनुसंधान

ज्यादा तीखा खाने से डिमेंशिया का खतरा

क्या आपको बहुत तीखा खाना पसंद है तो संभल जाएं? एक अध्ययन का दावा है कि रोजाना 50 ग्राम से ज्यादा मिर्ची खाने से डिमेंशिया रोग का खतरा बढ़ सकता है। डिमेंशिया एक मानसिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। कतर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जुमिन शी के नेतृत्व में 55 साल से ज्यादा उम्र वाले 4,572 चीनी लोगों पर अध्ययन किया गया। इसमें उन लोगों की याददाश्त में तेज गिरावट पाई गई, जो लंबे समय से रोजाना 50 ग्राम से ज्यादा मिर्च खाने के आदी थे। 50 ग्राम से ज्यादा मिर्च खाने वाले लोगों की स्मृति में गिरावट का दोगुना खतरा पाया गया। जुमिन ने कहा, 'हमने पूर्व के अध्ययन में यह पाया कि मिर्च खाना ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि इस अध्ययन में हमने बुजुर्गों की स्मृति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पाया।' -प्रेट्र

पार्किंसन को नियंत्रित करने में नई थेरेपी मददगार

शोधकर्ताओं ने एक नई थेरेपी ईजाद की है। उनका दावा है कि कान में बिजली का मामूली झटका देने से पार्किंसन रोग के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पार्किंसन की बीमारी में व्यक्ति के हाथ-पैर कांपने लगते हैं और उसके लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। ब्रिटेन की केंट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, अध्ययन में पाया गया कि स्टिम्यूलेशन थेरेपी को दो माह तक रोजाना दो बार अपनाए जाने का पार्किंसन रोग पर उल्लेखनीय प्रभाव देखने को मिला। प्रतिभागियों ने चलने-फिरने, निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति, मूड और नींद में सुधार महसूस किया। अध्ययन के आखिर में उन्होंने यह भी बताया कि उनके लिए रोजमर्रा के क्रिया-कलापों को खुद से करना आसान हो गया है। स्टिम्यूलेशन थेरेपी हेडसेट के जरिये आजमाई जा सकती है। यह निष्कर्ष पार्किंसन से पीड़ित 46 लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। -प्रेट्र

वेटलिफ्टिंग से बढ़ती है मस्तिष्क की ताकत

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- चूहों पर अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने किया दावा
- रक्त संचार बढ़ने के साथ ही मस्तिष्क में बढ़ती है न्यूरॉन्स की संख्या

मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है वेटलिफ्टिंग। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन : वेटलिफ्टिंग करने से न सिर्फ मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि वेटलिफ्टिंग करने से मस्तिष्क की ताकत तो बढ़ती ही है, साथ ही मस्तिष्क के भीतर की कोशिकाओं में भी बदलाव आता है, जिससे सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है।

शोधकर्ताओं ने चूहों पर अध्ययन कर यह पता लगाया कि वेटलिफ्टिंग करने से चूहों का मस्तिष्क कैसे काम करता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने छोटे वजनी टुकड़ों को चूहों से बांध कर उन्हें सीढ़ी पर चढ़ने-उतरने के लिए छोड़ दिया। अध्ययन से पता चला कि ऐसा करने से स्मृति कमजोर (भूलने) होने की समस्या को कम किया जा सकता है।

दरअसल, एक उम्र के बाद लोगों के सोचने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने परिजनों का नाम तक भूल जाते हैं। उन्हें यह तक याद नहीं रहता कि उन्होंने अपने घर की चाबियां कहां रखी हैं। पिछले कई अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने यह बताया था कि इस समस्या से बचने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज फायदेमंद हो सकती है। एरोबिक एक्सरसाइज यानी दौड़ने, उछल-कूद और घूमने आदि से मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है और नए न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ती है। इससे दिमागी सूजन में भी कमी आती है। यदि इस सूजन का समय रहते इलाज नहीं किया जाता है तो कई बार इससे डिमेंशिया और अन्य तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होने की संभावना बढ़ जाती है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि जिम जाने से मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अभी तक बहुत कम अध्ययन किए गए हैं और यह भी पता नहीं लग पाया था कि वेटलिफ्टिंग से मस्तिष्क की कोशिकाएं और इसकी कार्यप्रणाली कैसे प्रभावित होती है। शोधकर्ताओं का यह अध्ययन अल्पाइड साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

इस तरह किया अध्ययन : कोलंबिया की मिसौरी यूनिवर्सिटी के शोधार्थी टेलर केल्टी ने बताया कि इस अध्ययन के लिए उन्होंने चूहों पर छोटे वजनी टुकड़ों को बांध दिया और 100 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए छोड़ दिया और उनकी हरकतों की निगरानी की। कुछ हफ्तों बाद शोधकर्ताओं ने चूहों की मांसपेशियों में वृद्धि देखी।

अगले कुछ दिनों के बाद शोधकर्ताओं ने उनके समूह में ऐसे चूहे मिला दिए जिनमें डिमेंशिया की बीमारी शुरुआती स्तर पर थी। उनके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। पांच हफ्तों के इस अभ्यास के बाद सबको एक हल्की रोशनी की भूलभुलैया में छोड़ दिया गया। इसमें पाया गया कि जो चूहे स्वस्थ थे वे एक बार में ही रास्ता समझ गए जबकि डिमेंशिया पीड़ित चूहे पहले तो लड़खड़ाए, फिर उन्होंने जल्द ही अपना रास्ता समझ लिया। शोधकर्ताओं के अनुसार उन चूहों की याददाश्त में आया बदलाव वेटलिफ्टिंग के कारण ही संभव हुआ।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में दिखे हिम तेंदुए

मुकेश मेहरा, कुल्लू

स्पेक्ट्रम

- पार्क में पिछले महीने लगाए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हलचल
- तीर्थन वैली के आसपास नजर आया हिम तेंदुआ

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में हिम तेंदुए संरक्षित हो रहे हैं। पार्क में पिछले माह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में इसकी हलचल कैद हुई है। हालांकि अभी विभाग ने एक ही क्षेत्र के कैमरों को खंगाला है और उसमें बर्फानी तेंदुआ दिखा है।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में अरसे से हिम तेंदुए की मौजूदगी के सुबूत मिल रहे थे। इस बात को पुख्ता करने के लिए वन विभाग ने नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर 50 सीसीटीवी कैमरे पार्क के अलग-अलग क्षेत्रों में लगाए थे। जुलाई के पहले सप्ताह में तीर्थन वैली में लगाए गए कुछ कैमरों की जांच की गई तो उसमें हिम तेंदुए की हलचल कैद हुई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ विंग अब अन्य जगहों पर लगाए गए कैमरों की जांच भी करेगा। तीर्थन घाटी सहित सैंज, जीवानाग, खीर गंगा आदि क्षेत्रों में यह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

जानकारों की मानें तो हिम तेंदुए 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं पर कई बार बर्फबारी के दौरान निचले क्षेत्रों में भी आ जाते हैं। जिस क्षेत्र में हिम तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखा है वह 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई का बताया जा रहा है। विभाग सभी फुटेज खंगालने के बाद यह जांच करेगी कि यह एक ही बर्फानी तेंदुआ है या अलग-अलग हैं। इससे विभाग के पास यह जानकारी इकट्ठी होगी कि इस क्षेत्र में कितने बर्फानी तेंदुए हैं।

स्पीति में पाया जाता है हिम तेंदुए : हिम तेंदुए लाहुल-स्पीति जिले की स्पीति घाटी में पाया जाता है। यहां इनकी संख्या 15 से 20 तक आंकी गई है। एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत इन पर निगरानी रखी जा रही है। भारत के अलावा यह जम्मू-कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊंचाई वालों क्षेत्रों में मिलता है।

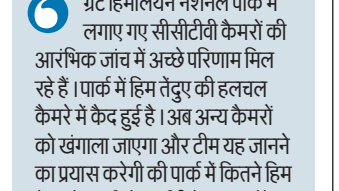

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में लगाए गए कैमरे में कैद हुई हिम तेंदुए की तस्वीर। जागरण

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की आरंभिक जांच में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। पार्क में हिम तेंदुए की हलचल कैमरे में कैद हुई है। अब अन्य कैमरों को खंगाला जाएगा और टीम यह जानने का प्रयास करेगी की पार्क में कितने हिम तेंदुए हैं। पार्क में बर्फानी के साथ कॉमन तेंदुआ भी दिखा है।

-अजीत कुमार, अरण्यपाल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क

चांद पर मिल सकती है चौंकाने वाली जानकारी

खुलेंगे राज ▶ दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में अनुमान से अधिक पानी होने की उम्मीद

माइनस 223 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाले क्षेत्र में उतरेगा रोवर

नई दिल्ली, प्रेट्र : चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 का रोवर जब उतरेगा, तब वहां पानी की मौजूदगी के बारे में चौंकाने वाली और काफी अहम जानकारी मिल सकती है। दरअसल, ताजा अध्ययनों में पता चला है कि इस क्षेत्र में पहले के अनुमानों से कहीं अधिक मात्रा में पानी बर्फ के रूप में हो सकता है।

चंद्रयान-1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का साक्ष्य सबसे पहले जुटाने वाले इसरो की योजना अब नए मिशन के जरिए वहां जल की उपलब्धता के वितरण और उसकी मात्रा की माप कर उन प्रयोगों को आगे बढ़ाने की है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव काफी ठंडा और काफी संख्या में विशाल गड्ढों (क्रेटर) वाला है। दरअसल, क्रेटर कटोरे जैसी आकृति वाला एक विशाल गड्ढा होता है जो उल्का पिंड के टकराने, च्वालामुखीय गतिविधि या विस्फोट के प्रभाव से बनता है। वहां ऐसे स्थान भी हैं जहां निरंतर धूप खिली रहती है या वहां लगातार अंधेरा छाया रहता है। यही कारण है कि नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2024 में वहां अंतरिक्षयात्रियों को भेजने की योजना बनाई है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 22 जुलाई को अपने 'बाहुबली' जीएसएलवी मार्क-3 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया था। इसके साथ चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए 48 दिनों का अपना ऐतिहासिक सफर शुरू किया। यह वहां पानी के लिए अपनी खोज करेगा।

मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआइएफआर) में एसोसिएट प्रोफेसर सुदीप भट्टाचार्य ने कहा, ''चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव की तुलना में कहीं अधिक छाया है और वहां क्रेटर जैसे स्थायी रूप से कुछ अंधकार वाले क्षेत्र होने की भी संभावना है।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए वहां बर्फ के रूप में पानी होने की कहीं अधिक संभावना है और वहां कुछ अन्य तत्व भी मौजूद होंगे, जिनका हम दक्षिणी ध्रुव पर पता लगाएंगे।''

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में चंद्रमा पर मौजूद क्रेटर को बुध ग्रह पर मौजूद क्रेटर से समानता रखने वाला पाया है। 'नेचर जियोसाइंस' जर्नल में प्रकाशित अपने शोधपत्र में उन्होंने चंद्रमा के सामान्य क्रेटरों के अंधेरे वाले क्षेत्रों के अंदर स्थायी रूप से बर्फ की मोटी परत होने का साक्ष्य मिलने की बात कही है। शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में लिखा है कि नासा के लुनार रिकोनाइसेंस आर्बिटर (एलआरओ) डेटा के जरिए चंद्रमा के करीब 12,000 क्रेटर के बारे में बुध ग्रह की तरह ही जांच की गई, जिससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा बर्फ की मोटी परत की मौजूदगी के चलते है। भट्टाचार्य ने बताया कि चंद्रयान-2 लैंडर संभवतः ऐसा पहला उपकरण होगा जो इस क्षेत्र में (चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर) उतरेगा।

सतह में मौजूद क्रेटरों में छिपे हैं कई रहस्य

नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के शोधार्थियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस ध्रुव (दक्षिणी क्षेत्र) की सबसे बड़ी विशेषता ''क्रेटरों'' की मौजूदगी है, जिनमें से कुछ तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचा है। स्थायी रूप से वहां अंधेरा छाये रहने के परिणामस्वरूप एलआरओ ने सौर मंडल में इन क्रेटरों के अंदर सर्वाधिक ठंडा और न्यूनतम तापमान पाया। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक पेपर में नासा वैज्ञानिकों ने कहा है कि वहां का तापमान शून्य से 223 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआइएफआर) में एसोसिएट प्रोफेसर सुदीप भट्टाचार्य ने इस बात का जिक्र किया कि चंद्रमा की सतह और वायुमंडलीय संरचना, भौतिक स्वभाव तथा भूकंपीय गतिविधियों की माप के लिए लैंडर और रोवर में कुल पांच तरह के औजार हैं।

गूगल फोटो का नया वर्जन लाया गूगल

सैन फ्रांस्सिको, आइएएनएस : गूगल ने 'गैलरी गो' नामक गूगल फोटोज का एक नया विकल्प यूजर के लिए पेश किया है, जो आपके फोन में केवल 10 एमबी की जगह घेरेगा। यह एप यूजर्स को कम स्टोरेज वाले हैंडसेट में फोटो स्टोर करने में मदद करेगा। इस फोटो गैलरी एप को ऑफलाइन काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके स्वचालित रूप से फोटो व्यवस्थित करेगा। इसके अलावा इंटरनेट या क्लाउड बैकअप की आवश्यकता के बिना ही पहली बार स्मार्टफोन यूजर्स को आसानी से फोटो ढूंढने, एडिट करने के लिए भी 'गैलरी गो' मदद करेगा। गूगल फोटोज के प्रोडक्ट मैनेजर बेन ग्रीनवुड ने कहा कि 'गैलरी गो'को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप कम डॉटा का इस्तेमाल किए बिना अपनी तस्वीरों को मैनेज कर सकें। उन्होंने कहा कि केवल 10 एमबी वाला यह एप आपके फोन को धीमा करे बगैर ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों को स्टोर करना सुनिश्चित करेगा। इस एप में कई अन्य एडिटिंग टूल भी होंगे,जो फोटो की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करेंगे।

कनाडा में योग का क्रेज

भागदौड़ और तनाव भरे जीवन के बीच तन-मन को स्वस्थ रखने में योग एक बेहद कारगर उपाय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी योग लोगों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। कनाडा की राजधानी ओटावा में पार्लियामेंट हिल के सामने लॉन में योग सत्र का आयोजन हुआ। इसमें युवतियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। रायटर

पूर्वजों की याद में मनाया पायनियर डे

अमेरिका के उटा राज्य की सॉल्ट लेक सिटी में हर वर्ष 24 जुलाई को पायनियर डे मनाया जाता है। इस दिन राज्य में सामूहिक अवकाश रहता है और स्थानीय लोग परेड में भाग लेकर झांकियां निकालते हैं और आतिशबाजी कर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। सॉल्ट लेक सिटी में मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने यह समारोह मनाया। एपी

स्क्रीन शॉट

जाह्नवी की प्रतिभा से प्रभावित हैं अंगद

अभिनेता अंगद बेदी अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की प्रतिभा के कायल हो चुके हैं और काम के प्रति उनके समर्पण की तारीफ करते हैं। अंगद के अनुसार, जाह्नवी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। अंगद आजकल फिल्म 'कारगिल गर्ल' में व्यस्त हैं, जिसमें जाह्नवी भी हैं। दोनों ने अप्रैल में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी और तब से दोनों ही काफी व्यस्त चल रहे हैं। फिल्म में दोनों भाई-बहन के किरदार में हैं और फिलहाल फिल्म की शूटिंग जॉर्जिया में की जा रही है। शूटिंग के अपने अनुभव के बारे में अंगद ने बताया, 'हर कलाकार एक योजना के तहत काम करता है। लेकिन, जाह्नवी ऐसी कलाकार हैं, जो बिना योजना के अच्छा काम कर सकती हैं।'

जाह्नवी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में अंगद ने बताया, 'हमारे निर्देशक शरण शर्मा ने हमारा परिचय कराया था, जब हम फिल्म की पहली रीडिंग के लिए गए थे। शरण चाहते थे कि हम दोनों आपस में कई बार मिलें, ताकि पर्दे पर हम भाई-बहन की तरह नजर आएं। हमने एक साथ रिहर्सल किया, खाना खाया और उसने मेरे परिवार यानी नेहा और मेहर के साथ समय भी बिताया।' अंगद ने बताया कि यहां तक कि डांस रिहर्सल के दौरान जाह्नवी ने अपने जूते निकाल दिए और फ्लोर को नमन करके डांस शुरू कर दिया। वह हर स्टेप के साथ खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं।'

फैन की शादी में श्रीलंका पहुंचे सोनू सूद

फैन्स सितारों पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। उनके जन्मदिन पर फूल और तोहफे भेजते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों तक उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं। सितारे भी फैंस से मिलना-जुलना पसंद करते हैं। कई बार जरूरतमंद फैन की मदद के लिए हाथ भी बढ़ा देते हैं। लेकिन सोनू सूद तो सबसे एक कदम आगे निकले। सोनू अपनी एक फैन की शादी में शरीक होने श्रीलंका पहुंच गए। मदरा डब्ल्यू हेमाचंद्रा नाम की इस खास फैन को लेकर सोनू ने बताया कि फिल्मों की शूटिंग या प्रमोशन के दौरान कई फैन्स से मुलाकात होती है। कई बार वे परिवार के सदस्य जैसे और खास दोस्त बन जाते हैं। मदरा भी उन्हीं में से एक हैं। सोनू का कहना है कि मदरा इंटरनेट पर उनसे जुड़ी हर खबर पर नजर रखती हैं और सबसे पहले उन्हें भेजती हैं। सोनू मदरा से मिलने पहले भी श्रीलंका जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार उनसे मिलने पहुंचे थे, तब मदरा अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने आई थीं। वह चाहती थीं कि मैं उनकी शादी में शामिल होऊं। मैंने सोचा कि अगर मैं यह कर पाया तो उन्हें खुशी होगी और हमेशा के लिए अच्छी यादें बन जाएंगी। सोनू ने अपनी फैन की शादी में जाने के लिए अपने शेड्यूल में भी बदलाव किए। फिल्म के निर्देशक भी यह जानकर हैरान थे कि शादी के लिए सोनू शूटिंग शेड्यूल में बदलाव कर रहे हैं। श्रीलंका की इस छोटी-सी ट्रिप में सोनू ने वहां के बीच की सैर की और शॉपिंग के लिए भी गए।

अध्ययन

बीमारी से उबरने के बाद भी फैल सकता है संक्रमण, क्लीनिकल इंफेक्शियस डिजीजेज नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ अध्ययन

चमड़ी के कालाजार का संक्रमण है खतरनाक

नई दिल्ली,आइएसडब्ल्यू : कालाजार से उबरने के बावजूद कई बार इसके मरीजों में त्वचा संबंधी लीश्मेनियेसिस रोग होने की आशंका रहती है, जिसे चमड़ी का कालाजार भी कहते हैं। ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीजेज इनिशिएटिव (डीएनडीआइ) और बांग्लादेश स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पता चला है कि कालाजार का उपचार पूरा होने के बाद चमड़ी के कालाजार से ग्रस्त मरीज भी इस बीमारी का संक्रमण फैला सकते हैं। इसी कारण शोधकर्ताओं का कहना है कि चमड़ी का कालाजार इस बीमारी के उन्मूलन में एक प्रमुख बाधा हो सकता है।

इस अध्ययन में संक्रमण मुक्त बालू मक्खियों से चमड़ी के कालाजार से ग्रस्त रोगियों को कटवाया गया और फिर उन मक्खियों में कालाजार के परजीवी लिश्मैनिया डोनोवानी की मौजूदगी का परीक्षण किया गया है। बांग्लादेश के मयमं सिंह मेडिकल कॉलेज में किए गए इस परीक्षण के दौरान रोगियों के हाथों को 15 मिनट तक ऐसे पिंजरे में रखवाया गया था, जिसमें संक्रमण मुक्त नर और मादा बालू मक्खियां मौजूद थीं। इसके बाद, उन बालू मक्खियों का परीक्षण उनमें लिश्मैनिया डोनोवानी परजीवी को पहचानने के लिए किया गया, जिसके कारण कालाजार होता है।

बालू मक्खी के काटने से फैलता है कालाजार। प्रतीकात्मक

शोधकर्ताओं ने पाया कि 47 रोगियों में से लगभग 60 प्रतिशत ने बालू मक्खियों में परजीवी को संचारित किया। इससे स्पष्ट है कि ये बालू मक्खियां बाद में किसी अन्य व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि चमड़ी के कालाजार से ग्रस्त मरीजों के घावों में भी कालाजार फैलाने वाला परजीवी होता है। चमड़ी के कालाजार से ग्रस्त लोगों का कई बार लंबे समय तक उपचार नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में नियंत्रित कालाजार और रोगियों की छोटी संख्या होने के बावजूद बीमारी के संचरण का खतरा रहता है। यह अध्ययन शोध पत्रिका क्लीनिकल इंफेक्शियस डिजीजेज में प्रकाशित किया गया है।

लिश्मैनिया डोनोवानी से फैलता है रोग : डीएनडीआई में वरिष्ठ लीश्मेनियेसिस सलाहकार और इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता डॉ जॉर्ज अलवर ने बताया कि अभी तक चमड़ी के कालाजार की भूमिका के बारे में जानकारी बहुत कम थी। इस शोध के नतीजे दिखाते हैं कि कालाजार के उपचार के बाद होने वाला चमड़ी का कालाजार इस बीमारी के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कालाजार रोग लिश्मैनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है और इसका संक्रमण बालू मक्खी के काटने से फैलता है। कालाजार से उबरने के बाद चमड़ी का कालाजार त्वचा पर घाव, चकत्ते के रूप में विकसित होने लगता है। ऐसा आमतौर पर कालाजार का उपचार पूरा होने के छह महीने से एक साल के भीतर हो सकता है।

प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रम चलाने की जरूरत : अध्ययन से जुड़े इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च, बांग्लादेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दिनेश मंडल ने बताया कि घातक रोग न होने के कारण चमड़ी के कालाजार को आमतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रयासों नजरंदाज कर दिया जाता है। इसके लिए प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रम चलाने की जरूरत है।

ओशो से प्रभावित होगा पंकज त्रिपाठी का लुक

'सेक्रेड गेम्स' के सीजन 2 का इंतजार इस 15 अगस्त को खत्म हो जाएगा। 25 दिनों में शहर में क्या होगा? त्रिवेदी कौन है? इन सब सवालों से पर्दा उठेगा। पिछले सीजन में अभिनेता पंकज त्रिपाठी का गुरुजी का किरदार काफी रहस्यमयी था। दूसरे सीजन को जिस समय में सेट किया गया है, उसमें पंकज त्रिपाठी का गुरुजी का किरदार आध्यात्मिक गुरु ओशो से प्रेरित बताया जा रहा है। पहले आचार्य रजनीश, फिर भगवान श्रीरजनीश के बाद ओशो के नाम से प्रसिद्ध भारत के दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु ओशो का जीवन काफी विवादास्पद था। 'सेक्रेड गेम्स 2' के ट्रेलर में पकंज के संवाद और हावभाव ओशो से मेल खाते हैं। सूत्रों की माने तो ओशो के जीवन जीने के तरीकों और उनके अभ्यासों को पंकज त्रिपाठी के किरदार में देखा जा सकेगा। दूसरे सीजन में कल्कि कोचलीन और रणवीर शौरी भी नजर आएंगे।